हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

20 मार्च, 2015

खण्ड-1, अंक-11

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY

विषय सूची

शुक्रवार, 20 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
कतिपय अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में मामला उठाना/सदन की बैठक का स्थगन/स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(11) 1
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	
श्री करण सिंह दलाल द्वारा	(11) 10
कतिपय अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में मामला उठाना/सदन की बैठक का स्थगन/स्थगन प्रस्ताव की सूचना (पुनरारम्भण)	(11) 10
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11) 11
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(11) 30
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11) 35
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(11) 39
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	

मूल्य

684

गन्ना मिलों द्वारा गन्ने की अदायगी न किये जाने संबंधी

वक्तव्य- (11) 39

सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (11) 49

बैठक का समय बढ़ाना (11) 73

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (11) 73

बैठक का समय बढ़ाना (11) 98

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (11) 98

बैठक का समय बढ़ाना (11) 106

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (11) 107

बैठक का समय बढ़ाना (11) 111

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (11) 111

हरियाणा विधानसभा

शुक्रवार, 20 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात :10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

कतिपय अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में मामला उठाना/ सदन की बैठक का स्थगन/स्थगन प्रस्ताव की सूचना।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, इससे पहले कि सदन की कार्यवाही शुरू की जाये हम यह कहना चाहते हैं कि कल क्वैश्चन ऑवर में जिस प्रकार से माननीय मंत्री द्वारा इस सदन का माहौल खराब किया गया उसके कारण हमारी पार्टी के सभी विधायकों को पैदल चलकर राजभवन तक जाना पड़ा। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि आपकी अध्यक्षता में यह सदन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। माननीय मंत्री द्वारा कल क्वैश्चन ऑवर में नेहरू परिवार के लिए, राजीव गांधी के लिए और महात्मा गांधी के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया वह इस सदन की मर्यादाओं के खिलाफ है। स्पीकर सर, संसदीय प्रणाली में इस सदन के अंदर सभी सदस्यों को अपनी बात सभ्य तरीके से कहने का पूर्ण अधिकार है इसलिए हम सदन का ज्यादा समय खराब न करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप सदन के नेता, विपक्ष के नेता और हमारी विधायक दल की नेता के साथ अपने चैम्बर में बैठक करके इस मामले का समाधान निकालें। (शोर एवं व्यवधान)

वित्तमंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, मेरी आप सभी से रिकवैस्ट है कि यह क्वैश्चन ऑवर है इसमें सभी माननीय सदस्यों के बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं इसलिए पहले आप क्वैश्चन ऑवर को कम्पलीट हो जाने दें उसके बाद जैसा आपने कहा मैं सदन के नेता, विपक्ष के नेता और आपकी नेता को इस मुद्दे पर अपने चैम्बर में बात करने के लिए बुलाऊंगा इसलिए अब आप सभी बैठ जायें और क्वैश्चन ऑवर की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, हमने किसानों की समस्याओं के बारे में आपको एक अति महत्वपूर्ण एडजर्नमैंट मोशन दिया था। हम चाहते हैं कि आपको हाउस की कार्यवाही को तुरंत रोककर सबसे पहले उस पर चर्चा करवानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परमिन्द्र जी, आपका कालिंग अटैंशन मोशन जो कि हरियाणा प्रदेश के गरीब किसानों को अधिकतम ब्रिकी मूल्य पर बोनस देकर सहायता करने के बारे है यह मुझे आज सुबह 08.42 बजे मिला है इसलिए इस पर विचार करने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। इस पर विचार करने के बाद इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि इस विषय पर हाउस में कब डिस्कशन करवाई जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, . . . (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, करण सिंह दलाल जी ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन ऑवर के तुरंत बाद आप अपनी नेता को मेरे चैम्बर में भेज दें। हम इस मुद्दे पर बात कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अभी आप क्वैश्चन ऑवर को चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) मैंने श्री करण सिंह दलाल की बात को स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन ऑवर के बाद सभी पार्टियों के नेता मेरे चैम्बर में आ जायें। (शोर एवं व्यवधान) अभी तक तो सभी पार्टियों के नेता सदन में आये भी नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) जो बात आपने अभी कही मैं उससे सहमत हूं इसलिए मैं उस बारे में बात करने के लिए भी तैयार हूं लेकिन अभी मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप क्वैश्चन ऑवर को चलने दें और क्वेश्चन ऑवर के तुरंत बाद आप मेरे चैम्बर में आ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, पहले हमारे एडजर्नमैंट मोशन के बारे में हमें बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परमिन्द्र जी, मैं इसको अभी देख लेता हूं। (शोर एवं व्यवधान) अभी आप सभी बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) मैं आप द्वारा दिये गये एडजर्नमैंट मोशन पर विचार कर रहा हूं। पहले आप क्वैश्चन ऑवर को चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, कल जो माहौल खराब हुआ था वह भी क्वैश्चन ऑवर में ही खराब हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, यह माहौल अगर आप कहते हैं कि क्वैश्चन ऑवर में खराब हुआ तो अभी भी तो क्वैश्चन ऑवर ही है और आप सभी माननीय सदस्यों के क्वैश्चन लगे हुए हैं जिन पर माननीय मंत्रियों को जवाब देना है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मेरा आप सभी से बार-बार अनुरोध है कि आप सभी माननीय सदस्य कृपा अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल तबाह हो गई हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि किसानों को गेहूँ की खरीद पर सरकार की तरफ से 350/- रूपये बोनस दिया जाये क्योंकि किसानों का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सदस्यों का अधिकार है इसलिए प्रश्नकाल चलने दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन की मर्यादा प्रश्नकाल से भी महत्वपूर्ण है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल की सैंक्टिटी को बनाए रखना चाहिए। विपक्ष ने शायद अपने प्रश्नों के उत्तर देख लिये हैं और ये उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये प्रश्नकाल से बचना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रश्नकाल के समय का उपयोग किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल प्रश्नकाल में ही सदन की मर्यादा को तोड़ा गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, हमारा काम रोको प्रस्ताव है उस पर सरकार जवाब दे। सदन के नेता सदन में मौजूद हैं उनको जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस काम रोको प्रस्ताव पर अच्छी तरह से विचार करूँगा। अभी आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : सर, विचार करने की बात नहीं है, आप हमें एश्योर कीजिए कि इस पर चर्चा की जायेगी । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल शुरू किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता यहाँ बैठे हुये हैं, वे इस मामले में सदन के सामने अपने विचार रखें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष ने सवालों की लिस्ट देख ली है और उन सवालों के सम्भावित जवाब देख कर ये भाग रहे हैं। ये घबरा कर भाग रहे हों, जो उत्तर दिये जायेंगे कहीं वे इनकी पोल न खोल दें और वे जवाब इनके लिए तकलीफदेह हों। सरकार सवालों के जवाब देना चाहती है लेकिन विपक्ष सुनना नहीं चाहता क्योंकि इन सवालों से इनकी पोल खुलती है ? यह कैसा सदन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरविन्द्र सिंह कल्याण : अध्यक्ष महोदय, ये सदन से बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, सदन में सच्चाई बयान की जाती है। जो सवाल पूछा जायेगा उसका जवाब सच्चाई होगी। यह बात भी सच है कि महात्मा गाँधी कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गाँधी जी ने तो कह दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस के लोग आजादी की लड़ाई की कीमत वसूलेंगे। गाँधी जी ने तो कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : सर, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं 15 मिनट के लिए हाउस स्थगित करता हूं। मेरा श्री अभय सिंह चौटाला, श्रीमती किरण चौधरी और सदन के नेता से निवेदन है कि वह मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिले। (शोर एवं व्यवधान)

***10.10 बजे (तत्पश्चात सदन 15 मिनट के लिए * स्थगित हुआ और प्रात : 10.25 बजे पुन : समावेत हुआ)।**

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है उसके बारे में चर्चा करायें, यह जरूरी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब आपके चैम्बर में फैसला हो गया था कि...... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार को काम रोको प्रस्ताव दे रखा है मेरा अनुरोध है कि पहले आप इस पर चर्चा करायें (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, प्लीज, बैठ जाईये ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, सदन सर्वसम्मति से चले । पहले मैं पहले तू ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस महान सदन में पहले यहाँ तू नहीं पहले मैं हूँ । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कई बातों में कुछ अर्थ होता है और कई बातों में कुछ और ही अर्थ होता है। जो भी कोई माननीय सदस्य जिस किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो एक-एक करके माननीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेकर ही बात करें और कौन सी बात की जानी चाहिए यह भी सभी माननीय सदस्यों को भलीभांति ज्ञात होना चाहिए ताकि सदन की कार्यवाही उचित प्रकार से चलती रहे। यदि हम किसी सदस्य को माननीय कहकर सम्बोधित कर देंगे.........(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दा आज हमारी पार्टी लेकर आई है उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार ने ओलावृष्टि के नुकसान के 3 हवाई सर्वे करवायें हैं (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सदस्यों को किसानों से कोई मतलब नहीं है ये लोग यहाँ पर बिना मतलब के ही खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय......(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, आपका जो मुद्दा है (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, इनको किसानों से क्या मतलब है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ .... (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही तभी चलेगी जब............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किसानों को बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में चर्चा करें । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, तीन सर्वे हुए जिनमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री रामबिलास शर्मा और आप खुद भी गये थे। आप तीनों ने अलग-अलग हवाई सर्वे किए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा से पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नाम की नेम प्लेट हटाई और राजीव गांधी जी का नाम हटाने की बात आई तो ये हाउस से वाकआउट कर गये। इनको तो अपनी नेम प्लेट हटाने का दुख है। ये लोग राजीव गांधी जी तक ही सीमित है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ आज क्या हो रहा है ....(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार मुद्दों से भटकना चाहती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इनका तो एक ही मकसद है कि किसी भी कारण से हाउस की कार्यवाही न चले । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठ जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इनके पास एक ही मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य पार्टी में अपने नम्बर बनाने के लिए हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मैं आपके काम रोको प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करता हूँ । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य घर से सोच कर आयें हैं कि आज हाउस को चलने नहीं देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने कल सदन में कहा था कि बजट सत्र अब तक पूर्ण भावना से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जो अचानक घटनाक्रम हुआ वह अच्छा नहीं हुआ है। पिछली बार भी मैंने सत्र में एक बात कही थी कि सरकार को सदन की बैठकों को बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की कटौती करनी चाहिए। विधान सभा की पिछली बैठकों का रिकॉर्ड जब हम देखते हैं तो उसके हिसाब से सदन की गतिविधियाँ शतप्रतिशत बढ़नी चाहिए। प्रदेश के हित में हरेक विधायक को अपने-अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को सदन में उठाने का ज्यादा से ज्यादा समय मिलें, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अपना उत्तर देते हुए शायद मुझे लगता है कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो उसमें अनावश्यक वाद-विवाद होते हैं। अनावश्यक वाद-विवादों को देखकर जनता को भी लगता होगा कि हमने जो विधायक अपनी समस्याओं को हल करने के लिये सदन में चुनकर भेजे हैं वे विधायक ऐसी बातों पर वाद-विवाद करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि हम जो बातें कर रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जनता की पहली प्राथमिकता तो यह होती है कि उनकी समस्याओं को हल किया जाये और उनके विकास की गति को आगे बढ़ाया जाये। हम जनता की इन बातों को यदि सदन में रखेंगे तो इस बढ़े हुए बजट सत्र का लाभ सीधा जनता को हो सकता है। कई बार

[श्री मनोहर लाल]
शब्दों के वाद-विवाद को लेकर हम आपस में ही उलझ जाते हैं, खासकर जो व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष पार्टियों के नाम से होते हैं, पार्टियों के विचारों को लेकर कुछ न कुछ कहा जाता है, इस तरह से जब सदन में ठेस पहुँचाने वाली बात हो जाती है तो मुझे लगता है कि हम एक सीमा लांघ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) की बात सामने आई थी और मैंने आखिरी में स्वीकार भी किया था कि आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ वह मुझे जनता के सहयोग से सदन के नेता के रुप में प्राप्त हुआ है वह केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ही मिला है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) मुझे भी लगता है कि एक ऐसा विवाद जो आज से नहीं बल्कि बहुत वर्षों से चलता आ रहा है, जिस पर कई आयोगों और अदालतों ने निर्णय भी दे दिये हैं कि इस प्रकार का कोई संदर्भ नहीं है जिसके बारे में समय-समय पर आक्षेप, आरोप और प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। जब एक सदस्य कुछ कहता है तो सामने वाला कुछ और कहता है जिससे एक-दूसरे को ठेस लगती है। हमारे सभी नेता सम्मानित नेता हैं। यदि सम्मानित नेताओं के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है तो ठेस लगती है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि शब्दार्थ के साथ उनके भावार्थ भी अलग होते हैं। शब्द किस मायने में कहा गया है यह उसकी बात पर निर्भर करता है। मैं इस विषय में अभी अपने नेताओं से बातचीत कर रहा था, इसमें मुझे तो अनुभव नहीं है लेकिन आप में से तो बहुतों को अनुभव होगा। पत्नी के भाई को क्या कहते हैं ?

आवाजें : साला

श्री मनोहर लाल : इस बात को ले करके कितना बवंडर मच सकता है लेकिन किस संदर्भ में कहा जाता और किस संदर्भ में नहीं कहा जाता तब जाकर उसकी भावना निकलती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए शब्दों के अर्थ को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। शब्द कोष में तो केवल शब्द होता है, उसका भावार्थ नहीं होता। भावार्थ तो बोलने के लहजे से पता चलता है। कई बार नेता का नाम लेकर कहा जाता है, हर नेता के कुछ अच्छे पक्ष होते हैं और कुछ बुरे पक्ष होते हैं। हमें हमेशा नेता के अच्छे पक्ष को रखना चाहिए क्योंकि उन नेताओं के नाम से ही हमें आगे प्रेरणा देनी होती है। उसी में से यह विषय निकल कर आता है। कई बार हम अनुपातिक तौर पर भी कुछ बातें इतनी ज्यादा आगे बढ़ा देतें हैं और कुछ बातों को गौण (साधारण) समझकर छोड़ देते हैं इन बातों से ही इतिहास भरा पड़ा है, उस इतिहास में भी जिसका जो स्थान है उस नाते से उसे मिलना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष अपने विचारों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है और किंतु उसे अपने विचारों को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे विपक्ष बिल्कुल ही दब जाए या छोटा रह जाए। मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि जब केन्द्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार चल रही थी उस समय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चन्द्र शेखर के पास उन्हीं की पार्टी का हरियाणा का एक कार्यकर्ता एक शिकायत लेकर गया और कहा कि आजकल उपायुक्त महोदय हमारी बात नहीं सुनते, मंत्री महोदय हमारी बात नहीं सुनते। इस पर पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कहा कि किसकी सुनते हैं ? कार्यकर्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सुनते हैं। उस समय मैं वहां स्वयं मौजूद नहीं था, मुझे सुनने वाले ने यह बात बताई है। उस कार्यकर्ता को यह कहा गया कि जब गाय ब्यावेगी तो दूध बाछड़ा पीयेगा काटड़ा नहीं पीयेगा और जब भैंस ब्यावेगी तो दूध काटड़ा

पीयेगा बाछड़ा नहीं पीयेगा। इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने यह बात समझाई थी। मैं यह नहीं मानता कि आपको केवल सत्ता पक्ष की ही बात सुननी चाहिए बाकी पार्टियों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए! सहज विचार यही है कि जनता जिसे बहुमत देती है वही पार्टी सत्ता में बैठती है। उसकी एक कार्य प्रणाली होती है और उस कार्य प्रणाली को लेकर काम करने का अवसर सत्ता पक्ष को मिलता है और मिलना ही चाहिए। इसके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कुछ बातों से कुछ पार्टी के सदस्यों को या नेताओं को व्यक्तिगत रूप से कोई भी ठेस पहुँचे ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस नोंकझोंक में भी मैं एक ध्यान करता हूँ कि इस बार ऐसा संयोग बना है कि इस सदन की संरचना काफी अलग है। हमारे अध्यक्ष महोदय पहली बार अध्यक्ष बने हैं, मैं सदन के नेता के रूप में पहली बार सदन में आया हूँ। मैं नया हूँ और संयोग से विपक्ष के नेता भी पहली बार प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, श्रीमती किरण चौधरी पहले मंत्री रह चुकी हैं लेकिन कांग्रेस विधायक दल की नेता पहली बार बनी हैं। हमारे हरियाणा जनहित कांग्रेस (BL) पार्टी भी के दो सदस्य बने हैं लेकिन उनके भी नेता पहली बार बने। भले ही वे पहले सांसद रह चुके हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी बता दें कि हरियाणा में भाजपा की सरकार भी पहली बार बनी है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, यह बात भी ठीक है। यह सदन नये नेता और नये अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा है। नये नेताओं का व्यवहार ठीक है परंतु जो हमारे अनुभवी लोग हैं वे उनकी बातों का आनंद लेते हैं। पहले से एस्टेबलिस्ड जो अच्छे और अनुभवी नेता है उन्होंने कई जगह हमारी प्रशंसा की है। इसके लिये मैं उनका धन्यवादी हूँ इसलिए हम सब लोग सदन के इस सत्र में भी और आगे के सत्र की कार्यवाही में भी ध्यान रखें कि हमारा व्यवहार खराब न हो। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि कल के सदन की कार्यवाही में से जो आपत्तिजनक शब्द हैं उन शब्दों को निकाल दें। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में सदन में आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा। सभी पार्टियों के नेता सदन की गरीमा को ध्यान में रखकर सदन की कार्यवाही अच्छी तरह चलायेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, सदन के नेता ने जो बात कही है वह बहुत अच्छी बात है। हम सदन को एश्योर करते हैं कि अगर उधर से नोकझोंक नहीं होगी तो हमारी तरफ से भी कोई नोक-झोंक नहीं होगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कल की कार्यवाही में कांग्रेस के बारे में जो भी अपमानजनक टिप्पणी और आर.एस.एस. से संबंधित शब्द प्रयोग किये गए थे उन्हें निकाल दिया जाए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, सदन के नेता ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। हम भी चाहते हैं कि हाउस स्मूथ चले और सदन के नेता का एक-एक शब्द हमारे लिए एक आदेश है। सदन के नेता ने कहा है कि कहीं पर आपत्तिजनक शब्द हैं तो निकाल दिए जायेंगे। लेकिन सदन को यह तो बतायें कि आपत्तिजनक शब्द कौन से हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप बैठिये, मैंने उन शब्दों के बारे में बता दिया है कि कौन से शब्द कार्यवाही से निकालने हैं ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विज साहब सदन के नेता की बात को भी नहीं मान रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, वे कौन से शब्द हैं जो कार्यवाही से निकालने हैं। उन शब्दों के बारे में पहले सदन में चर्चा तो करवाईये कि उन शब्दों में क्या गलत है ? आप पहले सदन में चर्चा तो करवाईये।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप बैठिये, यह रूलिंग मैंने देनी है कि कौन से शब्दों को कार्यवाही में रखना है और कौन से शब्द कार्यवाही से निकालने हैं। यह बात मैं निश्चित करूंगा कि कार्यवाही से कौन से शब्द निकालने हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सदन यह जरूर जानना चाहेगा कि आप कौन से शब्द सदन की कार्यवाही से निकालने जा रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप बैठिये, मैं आपको बताता हूं । कल की कार्यवाही के दौरान जो शब्द कांग्रेस पार्टी के बारे में और उसके नेताओं के बारे में कहे गये थे उन शब्दों को कल की सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल विज साहब ने नेहरू जी के बारे में भी कहा था उस शब्द को भी कार्यवाही से निकलवाया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसी प्रकार से कल की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में और आर.एस.एस. के बारे में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कल सदन की कार्यवाही के दौरान किया गया है उन सभी शब्दों को कल की सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विज साहब सदन के नेता की बात ही नहीं मान रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विज साहब अपनी पार्टी के नेता की ही बात नहीं मान रहे हैं यह बहुत गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी से यह बात पूछी जाए कि क्या श्री ए.ओ.ह्यूम कांग्रेस के जन्मदाता नहीं थे। क्या कांग्रेस पार्टी अपने जन्मदाता के जन्मदिवस को नहीं मनाती। क्या श्री ए.ओ.ह्यूम एक अंग्रेज नहीं थे ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सारी बातें पहले ही हो चुकी हैं और आपने पहले ही ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया है। सदन के नेता ने भी इस बारे में अपनी बात कही है। क्या विज साहब सदन के नेता से भी बड़े हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से यह बात पूछी जाए कि क्या श्री ए.ओ.ह्यूम कांग्रेस के जन्मदाता नहीं थे ?

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विज साहब फिर एक कन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं । कांग्रेस क्या है ? इस बारे में बहस करवा लें । I am ready to join a debate. Let me ask you what did you do in the Independence of India and what the Congress did? (Interruption) He is still creating a controversy.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कोई भी आदमी अपने जन्मदाता को डिसऑन नहीं कर सकता । जो आदमी अपने जन्मदाता को डिसऑन करता है वह तहस-नहस हो जाता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या विज साहब इस सदन से भी ऊपर है? He is a culprit.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सारा सदन ठीक से चल रहा है और विज साहब हाउस की गरिमा को ही नहीं मान रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठिये, चौटाला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आपने दो मिनट पहले अपने चैम्बर में बैठकर इन सभी मुद्दों पर चर्चा करके क्या डिसाईड किया था ? सदन में कुछ ऐसे भी साथी हैं जो आपके साथ तो कुछ और बात करके आते हैं और सदन में आते ही एक मिनट में ही अपनी बात के लिए बदल जाते हैं । अभी एक कांग्रेस के सदस्य श्री आनन्द सिंह दांगी जी ने हमारी पार्टी के बारे में यह कहा कि यह तो सरकार की बी-टीम है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, माननीय सदस्य गलत बात कह रहे हैं , यह बात मैंने नहीं कही है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, चौटाला साहब कैसे बात कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं ये कैसी बात कह रहे हैं। बी-टीम वाली बात दांगी साहब ने नहीं कही बल्कि मैंने कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले चौटाला साहब की बात तो सुन लीजिए कि वे आखिर कहना क्या चाहते हैं, आप सभी सदस्य बैठ जाईये ।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, चौटाला साहब कैसी बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, विपक्ष के नेता ने मेरा नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, आप बैठिये , पहले विपक्ष के नेता की बात सुन तो लीजिए कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं ?

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, विपक्ष के नेता ने मेरा नाम क्यों लिया है इनको क्या आनन्द सिंह दांगी ही सब जगह नजर आता है ? इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, पहले विपक्ष के नेता को अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए फिर आप अपनी बात कह लेना।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, चौटाला साहब कैसी बातें कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं ये कैसी बात कह रहे हैं। बी-टीम वाली बात दांगी साहब ने नहीं कही बल्कि मैंने कही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, दांगी साहब ने यह बात नहीं की होगी। अब करण सिंह दलाल जी खुद कह रहे हैं कि यह बात उन्होंने स्वयं कही है। इनसे कोई पूछने वाला हो कि ये लोग हमारी पार्टी को बी-टीम की संज्ञा क्यों देते हैं ? सदन में जब किसानों का कोई मुद्दा आता है तब ये साथी उस पर चर्चा नहीं करते हैं। जब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात सदन में आती है तो ये उस पर भी चर्चा नहीं करते हैं तथा सदन से वॉक-आउट कर जाते हैं। (विघ्न) सदन में जब किसी व्यक्ति विशेष की नेम प्लेट हटाने का प्रस्ताव आया तो ये सदन से बाहर चले गये। (शोर एवं व्यवधान) यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये साथी इस सदन में हमारी पार्टी के बारे में बी-टीम की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये साथी सदन में न तो प्रदेश के हितों की चर्चा करते हैं तथा न ही हरियाणा के किसानों के छोटे-मोटे मुद्दों के लिए ही सीरियस हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग हाउस में किस लिए आये हैं ? सदन में जब राजीव गांधी की नेम प्लेट हटाने की बात आती है तो ये सदन छोड़कर राज्यपाल महोदय के पास चले जाते हैं। इनका मकसद तो केवल एक ही है कि सदन में इनके द्वारा हुई नोकझोंक अखबारों की सुर्खियों में आ जाये और अखबारों में इनकी फोटो आ जाये। (शोर एवं व्यवधान)। ये किसी प्रकार से भी सदन में सीरियस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन्होंने इस सदन में जो आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, वे शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें। (शोर एवं व्यवधान)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण (श्री करण सिंह दलाल द्वारा)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, on a point of personal explanation, मैं बोलना चाहता हूं कि बी-टीम की बात का श्री अभय सिंह चौटाला जी ने बुरा माना है। मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के लोगों ने इनका काम देखा है तथा इनका काम देखने के बाद ही महसूस किया कि इनका काम बेमायने है इसलिए इनको बी-टीम की संज्ञा दी गई है। (शोर एवं व्यवधान)

कतिम्पय अपमानजनक टिपणियों के संबंध में मामला उठाना, सदन की बैठक का स्थगन/स्थगन प्रस्ताव की सूचना (पुनरारम्भण)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने सदन के सम्मुख अपने भाव रखे हैं जिन पर आपने अपनी रूलिंग भी दे दी है। उस रूलिंग को स्वीकार करते हुए मैं सदन में यह कहना चाहूंगा कि आपने सदन के पूरे रिकार्ड से परसों भी ये आपत्तिजनक शब्द सदन की कार्यवाही से निकलवाये थे जिनमें एक मंत्री महोदय की औकात के बारे में कहा गया था। इसी प्रकार से कल भी सदन में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया जिनमें हमारे एक मंत्री के प्रति वाहयात शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप इस बात का गौर करें कि सदन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न हो तथा इस सदन में बोले गये आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सदन में जिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनको सदन की कार्यवाही से निकाल देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी जो कैप्टन साहब ने सदन में प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों का जिक्र किया है, केवल इतना ही नहीं, आज इस सदन में पागल शब्द का प्रयोग भी किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, शोरशराबे में शायद आप द्वारा ये शब्द सुने नहीं गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सदन में सुबह जो माहौल बना था, उसके बाद आपने अपने चैम्बर में सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया था तथा मामले को निपटाने के लिए अच्छे माहौल में सभी पार्टियों के नेताओं के बीच में आपसी बातचीत भी हुई थी । मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आपने तथा सदन के नेता ने जो बात कही है, हमें उस बात पर तथा आप पर पूरा विश्वास है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी आपत्तिजनक शब्द सदन में आज कहे गये हों अथवा कल कहे गये हों, कृपया वे आपत्तिजनक शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन इनको भी आपकी बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जो आदेश करेंगे वह इनको मंजूर है । (शोर एवं व्यवधान) विज साहब हमारे पुराने मित्र हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह तो पूछना ही पड़ेगा कि कौन से गलत शब्द कहे गये हैं ? (शोर एवं व्यवधान) मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जन्मदाता कौन है ? क्या एक अंग्रेज ए.ओ.ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी को पैदा किया था अथवा नहीं किया था ? (शोर एवं व्यवधान) क्या ये साथी अपनी पार्टी के जन्मदाता को भूल जाना चाहते हैं ? (शोर एवं व्यवधान) ये साथी पहले सिर्फ मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें कि क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति ए.ओ.ह्यूम ने की थी अथवा नहीं ? (शोर एवं व्यवधान) अगर ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति ए.ओ.ह्यूम ने नहीं की थी तो मैं अपने शब्द वापिस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, विज साहब ने सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति ए.ओ.ह्यूम ने की थी । लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इनके द्वारा जो शब्द कहे गये थे वे शब्द उचित नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये बार बार वही बात कर रहे हैं इनसे माफी मंगवाएं । (शोर एवं व्यवधान) ये तो ज्यादती हो रही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये आपके आदेश को नहीं मान रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, bring him to the bars of the House and reprimand him. (Interruption) He should be called to the bars of the House and he should be reprimanded because of his behaviour and the way in which he is talking.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये बता दें कि कांग्रेस का जन्मदाता कौन था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, संस्थापक या जन्मदाता कहने में क्या दिक्कत है लेकिन जो शब्द कहे गए हैं उनके बारे में मैं मानता हूं कि वे ठीक नहीं हैं इसलिए मैंने वे शब्द कार्यवाही से निकलवा दिए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब क्राइस्ट को हैंग किया जा रहा था तो क्राइस्ट ने कहा था कि "Father, forgive them; for they do not know what they are doing."

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो लेकिन ये बता दें कि इनका जन्मदाता कौन था, मैं उसको मान लूंगा। जो कौम अपने जन्मदाता को भूल जाती है उनको पहचाने में डिसआन करती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) We will not tolerate this.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये तो बदतमीजी की हद है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने सारे माहौल को ठीक करने का प्रयास किया लेकिन ये उनकी बात भी नहीं मानते और आपकी बात भी नहीं मानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये मुख्यमंत्री महोदय के आदेश को नहीं मानते हैं, चेयर की बात को नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आपका मजाक है और सारे सदन का मजाक है। (शोर एवं व्यवधान) ये लीडर आफ दि हाउस की बात को नहीं मानते हैं इसलिए इनको सदन की बार में बुलाकर रैप्रीमैंड करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, this is your power. Shri Kuldip Sharma can not say so.

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, *****

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : मैंने सारे शब्द भी निकाल दिए हैं और आपकी बात भी मान ली इसलिए अब आप सब बैठ जाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, ******

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ******

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य इस समय बोल रहे हैं उनकी किसी बात को रिकार्ड न किया जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार दोबारा सदन से निवेदन करता हूं कि जो बात जहां समाप्त हो जाती है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए। सदन के अध्यक्ष अगला विषय टेक अप कर रहे हैं इसलिए हम सबको उस पर चलना चाहिए इसलिए अब प्रश्न काल को शुरू करने दिया जाए।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

Replacement of obsolete Electricity Wires

430 *Shri Zakir Hussain : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the approximately 40-50 years old obsolete electricity wires in district Mewat?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : श्रीमान, आवश्यकता अनुसार समय-समय पर पुरानी बिजली तारों को बदला जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जिला मेवात में 20.5 किलो मीटर पुरानी बिजली की तारों को पहले ही बदला जा चुका है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेवात में लगभग 40-50 साल पुरानी जो बिजली की तारे हैं उन सबको बदलने बारे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है इस बारे मेरा प्रश्न है लेकिन मंत्री जी ने इसका जवाब गोल मोल दिया है कि इन तारों को आवश्यकता के अनुसार बदला जाता है। ऑन रिकार्ड जो कंडक्टर्ज हैं ये 60 या 70 साल पहले से लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप खुद मानते हैं कि ये तारें किस तरह से लटकी हुई हैं, जगह जगह पर तारों के लटकने से एक्सीडैंट्स होते हैं जिसकी वजह से वे तारे पूरी बिजली भी नहीं ले पाती और लाईन लोसिज भी होते हैं, यह बात तो बिजली बोर्ड के रिकार्ड में है। 27 अगस्त, 2010 को एल.टी. लाईन से नहीं बल्कि एच.टी. लाईन 11 के.वी. की लाईन झुकी हुई थी जिसकी वजह से खेड़ला गांव में एक्सीडैंट हुआ और वहां ट्राली पर बैठी हुई आठ औरतों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हो गई थी । अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं मेरे पास नूंह हल्के की पूरी लिस्ट है। वहां 30-40 गांव ऐसे हैं जिनमें 1960-70 से बिजली की लाईनें डली हुई हैं लेकिन उनको बदला नहीं गया है। मेरे हल्के के आकेड़ा गांव में 16 साल का बच्चा मैट्रिक का पेपर देकर आया था वहां बिजली की बहुत पुरानी लाईन है जिसके कारण वह लड़का बिजली की चैपेट में आ गया और उसकी डैथ हो गई। अध्यक्ष महोदय, जो बिजली की तारें नीचे आई हुई हैं और बहुत खराब हालत में हैं यह बड़ी चिंता का विषय है। मैं मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रदेश में और विशेषकर मेरे हल्के नूंह में जो बिजली की तारें नीचे आई हुई हैं और खराब हालत में हैं उनको तुरंत प्रभाव से बदला जाए ताकि किसी मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े।

राव नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश दूसरे राज्यों की बनिस्पत खुशहाल प्रदेश है और हमारे प्रदेश में पीला कार्ड धारक, नारंगी कार्ड धारक यानि सभी परिवार बिजली का उपयोग करते हैं। पानी और बिजली आज हर आदमी को चाहिए। मेवात जिले में163261 परिवार हैं लेकिन वहां बिजली के कनैक्शन केवल 54839 हैं। इस तरह से वहां तकरीबन 1 लाख से ज्यादा परिवारों ने बिजली के कनैक्शन नहीं लिए हुए। बिजली बोर्ड नुकसान में चल रहा है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सरकार बिजली की तारों को तो बदलवायेगी लेकिन जाकिर जी वहां से जनप्रतिनिधि हैं इसलिए वहां के लोगों को जागरूक करें कि वे बिजली के कनैक्शन लें। वहां बिजली की चोरी बहुत होती है। वर्ष 2013-14 में 31.17 करोड़ बिजली यूनिट कंजूम हुई और बिल केवल 10.6 करोड़ रूपये का आया और इस तरह से करीबन 100 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। इसी तरह से 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक 27.96 करोड़ बिजली यूनिट कंजूम हुई और 10.46 करोड़ रूपये का बिल आया है और करीबन 86 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। मैं मेरे माननीय साथी जाकिर हुसैन जी से प्रार्थना करूंगा कि वे वहां लोगों को जागरूक करें कि वे बिजली के कनैक्शन लें और आने वाले तीन सालों में मेवात में बिजली की तारें वगैरा बदलने के लिए 188.84 करोड़ रूपये का प्रावधान किया हुआ है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सवाल के जवाब से आगे निकल गये। मंत्री जी ने संवेदनशील मामले पर कहा है। क्योंकि बिजली बोर्ड की संवेदनहिनता करने की आदत बन चुकी है और बिजली की तारों मे बिजली नहीं आती है तथा बिल बना देते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में छोटी सी बात लाना चाहूंगा क्योंकि यह विषय बहुत लम्बा है यदि पूरी बात करूंगा तो बहुत समय लग जायेगा । माननीय कृष्ण बेदी जी जो हमारे मिनिस्टर हैं वे मेवात ग्रीवंसीज कमेटी के चेयरमैन हैं। उनसे भी जानकारी ली जा सकती है कि उन्होंने 28 फरवरी को नूंह में मीटिंग ली थी जिसमें बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ एस.पी. को मौके पर बुलाकर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी । क्योंकि वहां पर 5 साल से बी.पी.एल. परिवारों के कनैक्शन नहीं लगाये और रिकार्ड में कनैक्शन दिखा रखे हैं । हमारे मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी से इस बात की जानकारी ली जा सकती है। मैं उनको मुबारकवाद देता हूं कि बहुत अच्छी मीटिंग वहां पर लेकर आए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर बिजली बोर्ड द्वारा बिजली के कनैक्शन दिए नहीं जाते हैं और बिल आ जाते हैं। इसको ठीक किया जाए। यही वजह रही कि बी.पी.एल. परिवारों को लेकर वहां एफ.आई.आर. दर्ज की गई। अध्यक्ष महोदय, दूसरी संवेदनहीनता बिजली बोर्ड मेवात में जो बरतता है वह भी नोटिस में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के में बीबीपुर गांव है। वहां के लिए जनवरी, 2014 में प्रपोजल आई थी वहां का लोड 5 एम.वी.ए. का है और उसके लिए 66 के.वी.ए. का सब स्टेशन मांग लिया गया । जबकि लोड के मुताबिक 33 के.वी.ए. का सब स्टेशन की मांग करनी चाहिए थी । मेरे पास इससे संबंधित सारे पेपर्ज हैं यदि मंत्री जी चाहेंगे तो मैं ये पेपर्ज दे दूंगा। ये चैक करवा लें। इस तरह की संवेदनहीनता वहां पर हो रही है। इस मैटर को लेकर मैं बिजली बोर्ड के अधिकारियों के पास दो महीने तक चपड़ासियों की तरह चक्कर काटता रहा लेकिन मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। अध्यक्ष महोदय, जब बिजली बोर्ड के अधिकारी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे तो आम आदमी की क्या हालत होगी ? अध्यक्ष महोदय, वहां पर सब-स्टेशन नहीं हैं। बिजली की तारें टूटने की वजह से लोग मर रहे हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमें आदमी मारने के लिए भी कनैक्शन लेना पड़ेगा अगर लेना पड़ेगा और तो माननीय मंत्री जी उसकी फीस भी बता दें पूरे मेवात की तरफ से हम उसको भी अदा कर देंगे।

राव नरबीर सिंह : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने बीबीपुर सब-स्टेशन का जिक्र किया है जो कि 33 के.वी.ए. का बनना है। इस सब-स्टेशन को रोज़-का-मेव से बिजली जानी है। मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से आई.एम.टी. रोज़-का-मेव बना हुआ है। वहां पर किसानों को उनकी ज़मीन के पैसे भी दे दिये गये हैं। यह 220 के.वी.ए. का सब-स्टेशन माननीय सदस्य जाकिर भाई के हल्के में बनना है। किसानों को उनकी ज़मीन का पैसे देने के बावजूद भी वे किसान वहां पर यह सब-स्टेशन नहीं बनने दे रहे हैं। इसलिए मैं जाकिर भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे वहां के किसानों को समझायें जिससे वे वहां पर 220 के.वी.ए. का सब-स्टेशन बनने दें ताकि यह सब-स्टेशन बनने के बाद उससे आगे बीबीपुर के 33 के.वी.ए. के सब-स्टेशन को बिजली की सप्लाई की जा सके।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से तो इस सवाल में एक और सवाल निकल आया है मैं on the floor of the House मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि रोज़-का-मेव से बिज़ली का सब-स्टेशन बनाने की कोई परपोज़ल ही नहीं है। इससे सम्बंधित पत्र

में जो लिखा गया है उसे मैं माननीय मंत्री जी को पढ़कर सुना देता हूं " Proposal for creation of New 66 KV Sub-Station, Bibipur with 1x10 MVA 66/11 KV Power Transformer at Village Bibipur, Distt. Mewat." यह पत्र दिनांक 16.01.2014 का है। यह सारा पंचायत का रेजोल्यूशन है। इसमें रोज़-का-मेव का कोई जिक्र नहीं है, दूसरी बात जो किसान वहां पर बैठे हुये हैं उनके बारें में मै बताना चाहता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि विभिन्न जगहों पर आज प्रदेश के किसानों की ज़मीन छोड़ी जा रही है। यह ज़मीन पिछली सरकार द्वारा 15-15, 20-20 और 40-40 लाख रूपये प्रति एकड़ में एक्वायर कर ली गई थी। तत्कालीन सरकार द्वारा अपने एक मंत्री को फायदा पहुंचाने के लिए आर-ज़ोन में एक गांव की ज़मीन छोड़ दी गई। इस कारण वहां के किसानों के साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी हुई है कि वे बेचारे पिछले चार साल से भूखे-प्यासे धरने पर बैठे हैं। उनका साथ देने के लिए सिर्फ एक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल उनकी सहायता के लिए आगे बढ़कर आई है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब इलैक्शन के दौरान आये हुए थे तो वे उनसे मिलने खुद गये। इसी प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी उन किसानों से मिलकर उनका दुख-दर्द बांटने गये वर्ना तो उस सड़क से बड़े-बड़े नेता मंत्री और मुख्य मंत्री तक निकल गये लेकिन किसी ने भी उनकी तकलीफ नहीं जाननी चाहिए। पूर्व सरकार के जिस मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने गांव को आर-ज़ोन में शामिल करवाया। वहां पर किसानों की ज़मीनों का मुआवज़ा रिश्वत लेकर दिया गया। जिस कारण इस समय सम्बंधित डी.आर.ओ. जेल में सज़ा काट रहा है। वहां पर इस तरह के हालात हुए हैं । मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि उन किसानों के साथ इंसाफ किया जाये। मैं माननीय सदन के नेता को बताना चाहूंगा कि ये एक बार बहुत जल्दी-जल्दी में नूंह गये थे लेकिन जैसे माननीय चौधरी अभय सिंह जी किसानों से मिलने गये उसी प्रकार से मैं माननीय सदन के नेता से अपील करूंगा और आमंत्रण भी दूंगा कि जब वे रेवाड़ी और बावल में किसानों के हित और सुख-दुख में साथ आये इसी प्रकार से इन नौ गांवों के किसानों को भी उनकी ज़मीन का बढ़ाकर उचित मुआवज़ा दिया जाये या उनकी ज़मीन छोड़ी जाये। ये किसान चार साल से धरने पर बैठे हैं और इनमें से कुछ किसानों की तो इस दौरान मृत्यु भी हो चुकी है। इसमें वाद-विवाद की कोई बात नहीं है जो हो चुका है अब वह बिना हुआ नहीं हो सकता अर्थात वह वापिस तो नहीं हो सकता इसलिए मेरी आपसे यह अपील है कि मैं इन गांवों की लिस्ट दे रहा हूं इनको माननीय मुख्यमंत्री जी चैक करवा लें और जो बीबीपुर का सब-स्टेशन है इसमें भी कोई वाद-विवाद की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस सब-स्टेशन को जल्दी से जल्दी बनाया जाये जिससे लोगों को बिजली मिले। हमारी यही बराबर कोशिश है कि लोग कनैक्शन लें और बिजली के बिल भी बराबर भरें। लोगों की तरफ से कोई कमी न हो इसके लिए हम प्रयासरत हैं।

राव नरबीर सिंह : स्पीकर सर, इन्होंने कहा कि इनके हल्के से जो पहले एम.एल.ए. थे वे पिछली सरकार में वज़ीर होते थे जो उन्होंने अपने गांव को आर-ज़ोन में शामिल करवा लिया था लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है क्योंकि पिछली सरकार दूसरी पार्टी की सरकार थी। इसके अलावा जहां तक जाकिर भाई बीबीपुर के सब-स्टेशन की बात कर रहे हैं मैं इनको पुन: :बताना चाहूंगा कि उसकी सप्लाई रोज़-का-मेव से होनी है। इसके लिए मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रोज़-का-मेव के वर्क का अवार्ड 20.02.2014 को कर दिया गया है।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को उन गांवों की लिस्ट दे देता हूं जिनमें बिजली की तारें बदली जानी हैं जो कि बहुत खस्ता हालत में हैं । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे इन गांवों की तारों को जल्दी से जल्दी बदलवायें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके । इसी प्रकार से मैं मंत्री जी को अलावलपुर गांव जो कि देवड़ा के साथ लगता गांव है, के बारे में बताना चाहूंगा कि इस गांव का जिला, तहसील और हल्का नूंह है लेकिन इस गांव में बिजली की सप्लाई इथीन सब-डिवीज़न से आती है। वहां पर केवल मात्र एक किलोमीटर की लाईन लगेगी जिससे यह गांव बिजली सप्लाई के मामले में नूंह में आ जायेगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस काम को भी जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करें ।

राव नरबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं ज़ाकिर भाई को यह जानकारी देना चाहूंगा कि बिजली विभाग ने आने वाले वित्त वर्ष 2015-16 में 236 नई एल.टी. लाईनें डालने की योजना बनाई है और इसी प्रकार से 180 किलोमीटर एस.टी. लाईनें डालने की योजना बनाई हुई है। हम कोशिश करेंगे कि माननीय सदस्य की इस डिमाण्ड को भी उसमें कवर कर लिया जाये।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बात को घुमा देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि एक सड़क होडल-नूंह से देवला नगली को जाती है और उसकी लम्बाई 7 किलोमीटर है और मंत्री जी उस 7 किलोमीटर के सफर को डेढ़ घंटे से पहले तय नहीं कर सकते। उस पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क की इतनी बुरी हालत है। अगर ये डेढ़ घंटे से पहले पहुंच जायें तो ये जा कर देख लें, मैं इनके लिए दावत रख देता हूँ। इनका प्यार तो इसी बात से झलक रहा है।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को आश्वस्त करता हूँ कि जब भी मेवात में कोई सड़क बनेगी तो वह देवला की बनेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, मंत्री जी ने कह दिया है अब वह सड़क बन जायेगी ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों की लिस्ट है वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। गांव बीबीपुर तहसील नूँह, जिला मेवात में वर्तमान में विभाग द्वारा 66 किलोवाट का सब-स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है जबकि पहले विभाग द्वारा 33 किलोवाट का प्रस्ताव था । इस सब-स्टेशन की स्थापना से लगभग 50 गांवों को फायदा होगा। इसी प्रकार से मेवात जिले के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी बिजली की तारें 1960 व 1970 के दशक की लगी हुई हैं ये बहुत ही जर्जर हालत में हैं, इसलिए इन तारों को बदला जाये । उन गांवों के नाम इस प्रकार से हैं :- 1 मेवली फीडर में :मेवली फीडर से खेड़ला, गुड़बास, बड़ौजी, नलहड़, पलड़ी, पल्ला, सौंख, बीवां, टपकन आदि। नम्बर 2 उजीना फीडर में जयसिंहपुर, चिलावली, कोंतलाका, बीबीपुर, सुलतापुर, देवला नंगली, अलावलपुर, ठेकड़ा, बझेड़ा आदि। नम्बर 3 मालब फीडर में : रानीका, बूराका, छावा, निलामपुर, दिहाना, बीरसीका, शेखपुर, आकेड़ा और मालब। इन गांवों की तारों को बदला जाये । इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूँगा कि नूँह के गांव अलावलपुर को इथीन सब-डिविजन से बिजली की सप्लाई है जबकि अलावलपुर की तहसील व निर्वाचन क्षेत्र नूँह है। गांववासियों को इथीन से बिजली की सप्लाई होने से बहुत असुविधा होती है। मात्र एक किलोमीटर लाईन लगाने से यह गांव नूँह सब डिविजन से जुड़ जायेगा, कृपया इस काम को यथाशीघ्र करवाया जाये।

To fill up the posts of BDPO

***171. Shri Anoop Dhanak** : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state whether it is a fact that the both posts of BDPO at Uklana and Agroha are lying vacant; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the said vacant posts together with the time by which these posts are likely to be filled up?

कृषि मंत्री : (श्री औम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उकलाना और अग्रोहा के बी.डी.पी.ओ. के खाली पदों के बारे में पूछा है और यह भी पूछा है कि वे कब तक भर दिये जायेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ उकलाना के बी.डी.पी.ओ. लम्बी छुट्टी पर थे लेकिन अब उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अग्रोहा का पद अभी भी खाली है तथा उसका चार्ज हमने आदमपुर वाले बी.डी.पी.ओ. को दिया हुआ है। कुल मिला कर बी.डी.पी.ओ. के 126 पद हैं जिनमें से 35 पद रिक्त हैं। इन 35 पदों में से 19 की भर्ती प्रोमोशन से होनी है जबकि 16 पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। इन दोनों तरह के पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक इन बी.डी.पी.ओ. को जो जहाँ था वहाँ पर इसलिए रखा हुआ था कि 31 मार्च, 2015 तक जो बजट का काम था वह पूरा हो जाये।1 अप्रैल के बाद उपलब्ध बी.डी.पी.ओज. को रैशनलाईजेशन के तहत इस ढंग से लगाया जायेगा कि सबका काम समय पर पूरा हो जाये।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो मेरे हलके उकलाना का बी.डी.पी.ओ. है वह लम्बी छुट्टी पर गया हुआ था वह असल में नारनौंद का बी.डी.पी.ओ. है और उसके पास नारनौंद का चार्ज है। इसके साथ ही साथ उसके पास नारनौंद नगरपालिका का भी चार्ज है तथा उकलाना का अतिरिक्त चार्ज है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एक बी.डी.पी.ओ. के पास अगर तीन-तीन चार्ज होंगे तो मेरे उकलाना हलके का काम कैसे होगा? इसी प्रकार से आदमपुर के बी.डी.पी.ओ. के पास अग्रोहा का चार्ज है। एक बार मैं मेरे हलके के लितानी गांव की समस्या लेकर गया था क्योंकि लितानी में दलदल बहुत ज्यादा हो गई है जिसमें बच्चे और पशुओं के धंसने का डर बना हुआ है। मैं बी.डी.पी.ओ. के पास 4 बार जा चुका हूँ लेकिन वह मुझे एक बार भी नहीं मिले। इस बारे में मंत्री जी को मिसगाईड किया गया है। उकलाना में कोई बी.डी.पी.ओ. नहीं है वह बी.डी.पी.ओ. जो है वह नारनौंद का है जिसके पास उकलाना का अतिरिक्त चार्ज है। मेरे दो ब्लॉक लगते हैं उकलाना और अग्रोहा तथा तीसरा ब्लॉक बरवाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे दोनों बी.डी.पी.ओ. जल्दी से जल्दी लगाये जायें।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि वह बी.डी.पी.ओ. नारनौंद का है और उसको उकलाना का अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। हमने आते ही बी.डी.पी.ओ. की बदली के बारे में सोचा था लेकिन हमने इसलिए वह प्रक्रिया रोक ली ताकि जिन-जिन पंचायतों में विकास कार्यों के प्रोजैक्ट चल रहे हैं वे 31 मार्च तक पूरे हो जायें। अगर उनको तुरन्त वहाँ से बदल दिया जाता तो वे प्रोजैक्ट प्रभावित हो सकते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगले वित्त वर्ष में हम रैशनलाईजेशन करके बी.डी.पी.ओज. का तबादला कर दिया जायेगा और इनको बी.डी.पी.ओ. दे दिया जायेगा। दूसरी बात यह भी है कि विभाग में अभी 35 बी.डी.पी.ओज. के पद खाली हैं इसलिए कमी भी है। हम उन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आरम्भ कर रहे हैं ताकि हर ब्लॉक को एक फुल-टाईम बी.डी.पी.ओ. मिल सके।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अभिमन्यु जी तो मंत्री हैं, ये तो अपना काम चला लेंगे लेकिन मेरे उकलाना में एक फुल-टाईम बी.डी.पी.ओ. लगाने का कष्ट करें ताकि मेरे उकलाना हलके का विकास हो सके।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने कह दिया है कि जल्दी ही उकलाना में फुल-टाईम बी.डी.पी.ओ. लगा दिया जायेगा।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने अभी बताया है कि महकमे में जो भी प्रमोशंज पैंडिंग हैं अप्रैल के बाद हम उनको तुरंत प्रभाव से कर रहे हैं।

श्री परमिन्दर सिंह ढूल : स्पीकर सर, जिन कर्मचारियों की बी.डी.पी.ओ. के पद पर प्रमोशन होनी थी वे अपनी प्रमोशन का इन्तजार कर रहे हैं क्योंकि उनके कोटे की प्रमोशन नहीं हो रही है। उनकी फाईलें दफ्तरों में चक्कर काटती रहेंगी तब तक प्रमोशन से वह बी.डी.पी.ओ. की पोस्टें ही भर जाएंगी। आपने जो पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है उन पर तो आप वैसे ही पैसा खर्च कर रहे हैं। जब आपके पास कर्मचारी हैं तो आप उनको प्रमोशन दो। आप एस.ई.पी.ओ. की लिस्ट के आधार पर उन कर्मचारियों को प्रमोशन देकर बी.डी.पी.ओ. बनाओ इससे आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। आपने जो कर्मचारी कॉंट्रैक्ट पर लगा रखे हैं उनको हटाओ क्योंकि उनकी कोई लायबिलिटी तो बनती नहीं। उनकी लायबिलिटी तो न आपके प्रति है, न जनता के प्रति है। उन्होंने तो पैसे लिए और काम कर दिया। क्या मंत्री जी इनके बारे में कुछ बताएंगे ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है उसके जवाब में मैंने कहा है कि हमने 19 लोगों को प्रमोशन से आगे बढ़ाना है। इस महकमें में पहले थोड़ी दिक्कत थी कि उसमें पहले अकाउंटैंट और एस.डी.ओ. दोनों पदों को भरा जाता था । अब उसमें कलियर हो गया है और अब इसको हम तुरन्त ही आगे बढ़ा रहे हैं । हमने 19 लोगों को प्रमोशन के माध्यम से बी.डी.पी.ओ. बनाना है बाकि डायरेक्ट भर्ती की डिमांड भी हमने कंसरंड अथोरिटी को भेज दी है ।

Allotment of Industrial Plots in Industrial Estate, Panchkula

***536. Shri Tek Chand Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether HUDA has invited applications for allotment of industrial plots in Industrial Estate of Panchkula in December, 2011 ; if so, to whom these plots were allotted; and

whether these plots were allotted to persons who even did not fulfill the criterion advertised by HUDA?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी।

ब्यान सदन के पटल पर रखा जाता है।

(क) हाँ, श्रीमान जी, अलाटियों की सूची इस प्रकार से है :

क्र0 संख्या	भू-खण्ड का आकार	आवेदक का नाम
1	1280 वर्ग मीटर	मैसर्ज वाई0पी0टी0 इंटरटेनमैंट हाउस प्राईवेट लिमिटेड, एस0सी0ओ0-399, दूसरी मंजिल, सैक्टर-20, पंचकूला
2	1000 वर्ग मीटर	श्रीमती मनजोत कौर पत्नी श्री प्रभजीत सिंह, मकान नं0 220, सैक्टर-25 पंचकूला
3	1000 वर्ग मीटर	श्रीमती रेणू हुड्डा, मकान नं0 37, सैक्टर-28ए, चण्डीगढ़
4	1000 वर्ग मीटर	श्री अशोक वर्मा/डायमंड हट, शॉप नं0 7-8, प्रथम मंजिल, गोल्ड सोक, सुशांत लोक-I खण्ड-सी, गुड़गांव
5	1000 वर्ग मीटर	श्रीमती नंदिता हुड्डा, मकान नं0 210, सैक्टर-11, चण्डीगढ़
6	1000 वर्ग मीटर	श्री पवन कंसल, ए-7, अंतरिक्ष अपार्टमैंट, भू-खण्ड नं0 डी0-3, सैक्टर-14 (विस्तार) रोहणी, नई दिल्ली-85
7	1000 वर्ग मीटर	सरदार कवॅरप्रीत सिंह संधू, 390, चार चमन, कुंजपुरा रोड करनाल हरियाणा
8	1000 वर्ग मीटर	श्रीमती अनुपम सूद एवं श्री सचिन सूद, मकान नं0 104, सैक्टर-12, पंचकूला
9	1000 वर्ग मीटर	डॉक्टर गणेश दत्त रतन, मकान नं0 1104, सैक्टर-33 सी, चण्डीगढ़
10	1000 वर्ग मीटर	लैफटिनैंट कर्नल ओ0पी0 दहिया (सेवानिवृत) मकान नं0 261, सैक्टर-35ए, चण्डीगढ़
11	496 वर्ग मीटर	श्रीमती मोना बैरी, मकान नं01044, सैक्टर-11, पंचकुला
12	496 वर्ग मीटर	श्री अमन गुप्ता, मैसर्ज, मोहन राईस मिल हिनोरी रोड, लाडवा जिला कुरुक्षेत्र
13	496 वर्ग मीटर	श्री सागर कटयाल, मकान नं0 216-एल, माडल टाउन रोहतक
14	496 वर्ग मीटर	श्री प्रदीप कुमार सुपुत्र श्री सिंह राम, मकान नं0 509, सैक्टर-7बी, चण्डीगढ़

(ख) मामला दो सिविल रिट याचिकाओं यानि याचिका नं0 4226/2014 व याचिका नं014264/2014 से उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वैसे तो इसका उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हुडा ने कुल 14 प्लाटों का विज्ञापन किया था और उन 14 प्लाटों का प्रक्रिया के तहत आबंटन किया गया था। इस मामले में जो जानकारी मांगी गई है उससे सम्बन्धित सिविल रिट याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जिसकी पूरी जानकारी कुछ मर्यादा के कारण यहां सदन में नहीं दी जा सकती ।

श्री टेकचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी इस समय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय प्लॉट अलॉट हुए थे उस समय कलैक्टर रेट में और हुडा के रेट में क्या अन्तर था? क्योंकि उस समय कलैक्टर रेट तो ज्यादा था लेकिन वह प्लॉट हुडा के रेट के हिसाब से अलॉट किये गये। मैं जानना चाहता हूं कि उनके रेट में कितना अन्तर था ?

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, the Hon'ble Minister has already told that the matter is pending in the Hon'ble Punjab & Haryana High Court. Hence, there should be no discussion over the question.

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है यह बात सही है जो जानकारी सदन के पटल पर दी जा सकती है उस जानकारी को मर्यादा के तहत सांझा करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इनको कोई आपत्ति हो तो आप उसे दर्ज करा सकते हैं यह इनका अधिकार होगा। वर्ष 2011 में पंचकूला में इंडस्ट्रीयल सैक्टर हुडा में जो 14 प्लॉट अलॉट किए गये हैं। यह आप जानते है कि वह बड़ा पुराना सैक्टर है, बड़ा फैमस सैक्टर है और बड़ा बेश कीमती सैक्टर है। उसमें जो 14 प्लॉट पुराने थे वह लैफ्ट ऑवर या रिज्यूम्ड थे, उनको आबंटन करने की प्रक्रिया हुई थी। जिनका वर्ष 2011 में विज्ञापन हुआ, दिसम्बर-2012 से जनवरी 2013 तक कुल 582 एप्लीकेशनस आई थी। इसमें जो 14 प्लॉटों का आबंटन हुआ वह तीन साईज के थे। उसमें 1280 गज का एक प्लॉट था, 1000 गज के 9 प्लॉट थे और 496 गज के 4 प्लॉट थे। उस समय हुडा का 6400/- रूपये पर वर्ग मीटर का रेट था। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उस समय जो कलैक्टर रेट था वह इससे कुछ गुणा में था। उसकी इतनी जानकारी तो तुरन्त नहीं है लेकिन इतनी प्रारम्भिक जानकारी जरूर मिली है कि वह शायद हो सकता है तीन गुणा के करीब भी ज्यादा हो और उससे ज्यादा भी हो सकता है । उनका उसी के सम्बन्ध में दूसरा सवाल था कि क्या वह प्लॉट्स ऐसे व्यक्तियों को दिए गये थे जो हुडा के क्राईटेरिया में पात्र नहीं थे। यह याचिका न्यायालय में लम्बित है। उस याचिका में प्रार्थी द्वारा जानकारी दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को प्लॉट मिले हैं, उनमें पात्रता के बारे में कुछ प्रश्नचिन्ह सामने आये हैं और यह मामला कोर्ट में पैंडिंग है। सरकार को उच्च न्यायालय से जो भी आदेश मिलेगा सरकार उसकी पालना करेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार भी अपने स्तर पर इस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। सरकार को भी ऐसा लगता है कि यह मामला कार्यवाही और जाँच के योग्य है। सरकार को इस पूरे मामले में कहीं न कहीं गड़बड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए इसे जाँच के योग्य मान रही है।

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो पंचकूला के अंदर प्लॉट्स का आंवटन हुआ है उनमें। कुछ प्लॉटस तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के रिश्तेदारों को दिए गये है। अध्यक्ष महोदय, इनमें से कुछ एम्पलाईज जो उनके अंडर काम करने वाले थे, क्या उनको भी प्लॉट अलॉट हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या सारी की सारी प्रक्रिया पारदर्शी रूप में हुई है?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अभी तक फाईलों के अध्ययन करने से इतना तो अवश्य पता चला है कि कहीं न कहीं प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आई है। अध्यक्ष महोदय, प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में

डिटेलड प्रोजैक्ट रिपोर्ट दी थी, उससे तो यह पता चलता है कि सारा का सारा मामला सांठ-गांठ से किया गया है लेकिन जो जानकारियाँ रिकॉर्ड के अनुसार आनी चाहिए थी वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहना उचित होगा कि अभी तक किन-किन लोगों को प्लॉटस दिये गये हैं और उनके साथ किस-किस की रिश्तेदारियाँ थी। अध्यक्ष महोदय, इससे साफ पता लगता है कि तत्कालीन सरकार के प्रभावशाली लोग ही प्रतीत हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, याचिकाकर्त्ता ने इस बात को उच्च न्यायालय में भी उजागर किया है । यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए यह सदन के पटल पर लाना उचित नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस मामले में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है।

Condition for Allotment of 100 Yards Plots

***237. Shri Udai Bhan** : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state -

(a) the criteria for allotment of 100-100 yards plots to the poor people in villages under the Mahatma Gandhi Basti Sudhar Yojana; and

(b) the number of such villages in Hodel Assembly constituency in which even a single plot has not been allotted togetherwith the time by which the plots will be allotted in those villages where such plots have not been allotted so far?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

(क) श्रीमान जी, 100 वर्ग गज के मुफ्त रिहायशी प्लाट आबंटन के लिए पात्रता निम्न प्रकार हैं :-

गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए :

(i) परिवार गरीबी रेखा से नीचे का परिवार होना चाहिए।

(ii) परिवार सम्बन्धित गांव का निवासी होना चाहिए।

(iii) परिवार एक इकाई होगी। इस उद्धेश्य के लिए परिवार का अभिप्राय वर्ष 2007 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए बी0पी0एल0 सर्वेक्षण में अभिज्ञान एक पृथक इकाई से है।

(iv) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणी (वर्ग-ए) के अलावा अन्य जातियों के परिवारों का बी0पी0एल0 परिवार होना आवश्यक है तथा उस परिवार की आय 45000/- रु0 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की आय का प्रमाण पत्र परिवार के मुखिया द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जाएगा।

(v) परिवार के पास अपनी एक एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए।

(श्री ओम प्रकाश धनखड़)

(vi) परिवार या परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

(vii) परिवार का कोई सदस्य सरकार या बोर्ड/निगम या नगरपालिका कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार परिवार का कोई सदस्य उद्योग, वाणिज्यिक स्थापन, समिति इत्यादि में समकक्ष रोजगार में नहीं होना चाहिए।

(viii) परिवार के किसी सदस्य को पंचायत या सरकार द्वारा इससे पहले किसी भी स्कीम के तहत 100 वर्गगज या इससे अधिक का प्लाट आबंटित न किया गया हो।

अनुसूचित जाति परिवारों के लिए :

(i) परिवार अनुसूचित जाति का परिवार होना चाहिए।

(ii) परिवार सम्बन्धित गांव का निवासी होना चाहिए।

(iii) परिवार एक इकाई होगी। इस उद्देश्य के लिए परिवार का अभिप्राय वर्ष 2007 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए बी0पी0एल0सर्वेक्षण में अभिज्ञात एक पृथक इकाई से है।

(iv) परिवार के पास अपनी एक एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं चाहिए।

(v) परिवार या परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

(vi) परिवार का कोई सदस्य सरकार या बोर्ड/निगम या नगरपालिका कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार परिवार का कोई सदस्य उद्योग, वाणिज्यिक स्थापन, समिति इत्यादि में समकक्ष रोजगार में नहीं होना चाहिए।

(vii) परिवार के किसी सदस्य को पंचायत या सरकार द्वारा इससे पहले किसी भी स्कीम के तहत 100 वर्गगज या इससे अधिक का प्लाट आबंटित न किया गया हो।

पिछड़ी श्रेणी वर्ग 'ए' परिवारों के लिए :

(i) परिवार हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़ी श्रेणी वर्ग 'ए' से सम्बंधित होना चाहिए लेकिन क्रीमी लेयर (creamy layer) में शामिल नहीं होना चाहिए।

(ii) परिवार सम्बन्धित गांव का निवासी होना चाहिए।

(iii) परिवार एक इकाई होगी। इस उद्देश्य के लिए परिवार का अभिप्राय वर्ष 2007 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए बी0पी0एल0 सर्वेक्षण में अभिज्ञात एक पृथक इकाई से है।

(iv) परिवार के पास अपनी एक एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं चाहिए।

(v) परिवार या परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

(vi) परिवार का कोई सदस्य सरकार या बोर्ड/निगम या नगरपालिका कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार परिवार का कोई सदस्य उद्योग, वाणिज्यिक स्थापन, समिति इत्यादि में समकक्ष रोजगार में नहीं होना चाहिए।

(vii) परिवार के किसी सदस्य को पंचायत या सरकार द्वारा इससे पहले किसी भी स्कीम के तहत 100 वर्गगज या इससे अधिक का प्लाट आबंटित न किया गया हो।

(ख) होडल निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कोई प्लाट आबंटित ना किया गया हो। हालांकि, दो गांवों, नामत : बिदुकी (312) और पैगलतु (227) में प्लाटों के कब्जे अदालती मामलों के चलते तथा आबंटित स्थल गांव से 4 किलोमीटर दूर होने के कारण लाभार्थियों ने कब्जा लेने से इन्कार करने के कारण नहीं दिए जा सके।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 100-100 वर्ग गज के प्लॉटस आवटन में मानदंड के बारे में सवाल पूछा है और उसके साथ-2 यह भी पूछा है कि होडल निर्वाचन क्षेत्र में भी कितने-कितने प्लॉट बांटे गये हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस प्रश्न के उत्तर में बताना चाहता हूँ कि इसका जवाब सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने लोगों को प्लॉट आबंटित हुए और कितने लोगों को पोजैशन दी गई है । इसके साथ ही साथ अभी तक कितने प्लॉटस बकाया हैं और वे कब तक दे दिये जायेंगें ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने (ख) प्रश्न के जवाब में बताया कि होडल निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पर प्लॉटस आबंटित न किया गया हो। अध्यक्ष महोदय, यह तथ्यों से परे है। मेरे ग्राम पंचायत हसनपुर में जहाँ पर 50 प्रतिशत आबादी एस.सी.और बी.सी वर्ग के लोगों की है, अभी तक वहाँ पर एक भी प्लॉट आबंटित नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में सत्वागढ़ी गाँव मुर्तजाबाद गाँव और लहरपुर गाँव में कोई भी प्लॉट आवटित नहीं हुआ है। इनके बारे में माननीय मंत्री जी को विभाग ने गलत सूचना दी है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस गाँव में कब तक प्लॉट आबंटित किये जाऐगें ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय ध्यान में लाया है, वह जायज है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विभाग से जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दी जायेगी । जो भी ऐसी कोई कोताही माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र के गांव की लिस्ट में से जानकारी इक्ट्ठा करने में हुई है उसको दुरूस्त किया जायेगा।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कितने प्लॉट आबंटित हुए हैं और कितने लोगों को कब्जा दे दिया गया है ? जिनको अब तक कब्जा नहीं मिला है उनको कब तक कब्जा दे दिया जायेगा? अध्यक्ष महोदय, हसनपुर और जो तीन और गांव हैं उनकी जानकारी ली जाये, जिनमें अब तक एक भी प्लॉट अलॉट नहीं हुआ है।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, होडल विधान सभा क्षेत्र के 55 गांव में 6,689 योग्य परिवारों को प्लॉट की अलॉटमैंट की गई है, उनमें से 6150 परिवारों को प्लॉट्स का पोजैशन मिल गया है बाकी 539 परिवारों को पोजैशन नहीं मिला है। ऐसे दो गांव हैं जिनमें land is available but possession could not be delivered.

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में ग्राम पंचायत के पास जमीन नहीं है, क्या वहाँ जमीन को एक्वायर करके प्लॉट्स दिये जायेंगे? क्योंकि वो परिवार भी क्राईटेरिया में आते हैं, उनका भी अधिकार बनता है, इसलिए उनको भी प्लॉट्स मिलने चाहिए। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने क्या नीति बनाई है?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसे देखते हुए पूरे हरियाणा के अन्दर 1544 गांवों के पास शामलात की भूमि नहीं है, इस नाते से जो भूमि लेनी है वह कई हजार एकड़ होगी । यह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला है, इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, फिर हम इस पर विचार करेंगी ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, यह मामला होडल विधान सभा से जुड़ा होने के कारण आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिनको 100-100 वर्ग गज के प्लॉट अलॉटस हो चुके हैं क्या सरकार ने उनके नाम से रजिस्ट्री करवाई है ? अगर सरकार ने रजिस्ट्री नहीं करवाई तो उनकी रजिस्ट्री कब तक करवा दी जायेगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर के मुताबिक प्रदेश भर में 4859 गांवों में प्लॉटस अलॉट कर दिये हैं जिनमें से 3,85,994 सदस्यों को प्लॉटस अलॉट हो चुके हैं उनमें से 3,69,550 प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाई जा चुकी है, बाकी प्लॉटों की रजिस्ट्री भी सरकार जल्दी से करवा रही है ।

Water Supply up to Tail End

***149. Shri Rahish Khan** : Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the Irrigating water does not reach upto tail end indistrict Mewat.

(b) If so, steps being taken by the Government to ensure water upto tail end ?

@ Asked by Shri Naseem Ahemad

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) हां श्रीमान जी,। जिला मेवात में 14 नहरे हैं जिनमें से चार, अर्थात भिरोटी रजवाहा, गंगोला माईनर, करेका माईनर और कालन्जर रजवाहा के अंतिम छोर तक पानी पहुंचता है और तीन में अर्थात उलेटा रजवाहा, गंगवानी माईनर और उमरा माईनर में अंतिम छोर तक पानी आंशिक रूप से पहुंचता है।

(ख) नूंह सब ब्रांच की गाद निकालने के लिए तथा इसके हैड रैगुलेटर तथा गुड़गांवा नहर बुर्जी संख्या 75886 के क्रास रैगुलेटर के गेटो की मुरम्मत करने के लिए निवादाएं आंमत्रित की जा चुकी है। दबालू माईनर के नये पम्प हाउस में बिजली का कनैक्शन लगाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (D.H.B.V.N.) को आवेदन किया गया है। बनारसी रजवाहे और शादीपुर माईनर की मोटरों और पम्पों के बदलने की प्रक्रिया चल रही है। बनारसी पम्प हाउस के लिए बिजली विभाग से स्वंतत्र फीडर प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है। हरियाणा को अपने अधिकृत हिस्से से कम पानी मिल रहा है तथा सरकार अपने अधिकृत हिस्से को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर अथक प्रयास कर रही हैं। अपने हिस्से का पूरा पानी मिलने पर तथा कार्यों के पूर्ण होने पर इन सभी रजवाहों के अंतिम छोर पर पानी पहुंच जायेगा।

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, जिस माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। चूंकि यह प्रश्न मेवात से जुड़ा हुआ है इसलिए अगर आप इजाजत दें तो तारांकित प्रश्न संख्या 149 मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इजाजत है।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष जी, उलेटा रजबाहा, बनारसी रजबाहा, शादीपुर माईनर मेरे क्षेत्र में आते हैं। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह सही नही है। पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है। उलेटा माईनर में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इनमें टेल एण्ड तक पानी पहुंचाया जाए। मेरे क्षेत्र के अन्दर ये रजबाहे केवल 20-25 गांवों को ही टच करते हैं जबकि मेरे हल्के में लगभग 185 गांव हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में और ज्यादा माईनर तथा रजबाहे खुलवाए जाएं ताकि किसानों को पानी उपलब्ध हो जाए और उन्हें इसका लाभ मिल सके।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी,। मैंने इनके प्रश्न का उतर आंशिक रूप से अपनी रिप्लाई में दे दिया है। हमें कम मात्रा में पानी मिलने की वजह से पानी की दिक्कत है। हमें ओखला बैराज से 850 क्यूसिक पानी मिलना चाहिए लेकिन हमें केवल सिर्फ सौ से पांच सौ क्यूसिक पानी ही मिल रहा है। यह मैं मानता हूं कि हम टेल एण्ड तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं इस गरिमामय सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी कुल 1333 टेल हैं और हमारी सरकार बनने के बाद हम कुल 998 टेल तक पानी पहुंचाने में सफल रहे हैं। सिर्फ 335 ऐसी टेल्स बची हैं जिनमें पानी पहुंचाने में अभी कठिनाई है हमारा यह कमिटमेंट है कि अगर यह पानी की उपलब्धता का मामला सुलझ जाता है तो हम सम्पूर्ण हरियाणा प्रदेश में आगामी 6 महीने में हर टेल तक पानी पहुंचाएंगे।

Facilities of Sewerage, Water Supply and Streets

***226. Smt. Shakuntala Khatak** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the village Khokhra Kot has been inhabited on the land of Archaeological Department of Rohtak and the NOC has also been issued by the said Department for sewerage, water supply and streets in the said village; and

(b) If so, time by which abovesaid amenities are likely to be provided?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां श्रीमान जी,। नगर निगम रोहतक के अनुरोध पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मूलभूत सुविदाएं जैसे कि सीवर व पानी की लाईन बिछाने, गलियां पक्की करने व बिजली के खम्बे लगाने इत्यादी के कार्य इस प्रतिबन्धित क्षेत्र गांव खोखरा कोट में करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है।

(ख) सरकार के निर्णयानुसार इस क्षेत्र में सीवर व पीने के पानी की व्यवस्था जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाई जानी है, जिनके लिए 2 अनुमान बनाऐ जा रहे हैं। सैनिटरी बोर्ड द्वारा अनुमानों की स्वीकृति व धन उपलब्ध कराने के उपरान्त ये

[श्री अनिल विज]

कार्य 1-1/2 साल में करवा दिए जाएंगें। इसके उपरान्त नगर निगम, रोहतक, उक्त क्षेत्र की गलियों व सड़कों का निर्माण करेगा। नगर निगम, रोहतक द्वारा गांव खोखरा कोट में गलियों व नालियों के 9 निर्माण कार्य करवाऐ जा रहे हैं तथा 14 अनुमान तैयार कर दिऐ हैं, इन कार्यों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरान्त करवा दिये जाएंगे।

श्रीमती शकुन्तला खटक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जिस एन.ओ.सी. की माननीय मंत्री जी बात कर रहे हैं वह एन.ओ.सी. चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय में लिया गया था । खोखरा कोट गाँव में सौ प्रतिशत बहुत ही गरीब तबका बसा हुआ है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि वे चाहे इस बारे में अपने विभाग से सर्वे करा लें। इस गाँव की सीवरेज, पानी आपूर्ति तथा गलियों को बनवाने के लिए श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, संसद सदस्य और श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के प्रयास से पुरातत्व विभाग से बहुत मुश्किल से केन्द्र सरकार से लिया गया था । इस बारे में चाहे मंत्री जी सर्वे करा लें । इस गाँव का कुछ काम कम्पलीट भी हो गया है। कई जगह पानी भी पहुँच गया है। इसके बारे में कुछ टैण्डर भी लगा दिए गये थे लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो अधिकारियों को बुलाकर जो पुराने टैण्डर्ज थे उनको कैन्सिल कराने का काम किया गया है । मंत्री जी ने अपने जवाब में यह आश्वासन दिया है कि इस गाँव को एक-डेढ़ साल में पानी दे दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि वे इस गाँव की गलियों और सड़कों को बनाने की समय सीमा तय कर दें और फिर चाहे दो साल में, तीन साल में या पांच साल में बनवा दें। इसलिए इस काम की समय सीमा के बारे में मंत्री जी मुझे सदन में बताने का कष्ट करें। इस बारे में मंत्री जी इसके लिए भूमिका न बनायें मुझे टू दि प्वायंट बता दें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह बात कही है कि सरकार बदलने के बाद इस गाँव के काम करने के लिए जो टैण्डर फ्लोट किये गये थे उनको कैन्सिल कर दिया गया है यह सरासर गलत बात है। वर्तमान सरकार किसी भी क्षेत्र में ऐसा काम नहीं करती। स्पीकर सर, 14.67 लाख रूपये पहले ही इस गाँव के काम के लिए खर्च किये जा चुके हैं और 35 लाख रूपये सड़कों के काम पर खर्च किये जा चुके हैं। 22.50 लाख रूपये नालियों को बनाने के काम के लिए खर्च किये जा रहे हैं। कोई टैण्डर कन्सील नहीं हुए हैं। यह माननीय सदस्य की भ्रान्ति है।

श्रीमती शकुन्तला खटक : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि वे इस बारे में सर्वे करा लें, कारपोरेशन में जाकर पता करवा लें या वहां की प्रजा से पता करवा लें । सारी बात क्लीयर हो जायेगी ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्या को ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस बताना चाहता हूँ कि उस गाँव में 75.69 लाख रूपये का काम प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जो अनुमान प्रक्रिया पास की जानी है वह 189.93 लाख रूपये की है । यह पैसा जैसे ही पास हो जायेगा उस पर काम शुरू करवा देंगे ।

स्पीकर सर, 301.89 लाख रूपये के सड़कों के अनुमान स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में हैं । जैसे ही अनुमानों की स्वीकृति प्राप्त होगी, उन सड़कों के कार्य को भी subject to availability of

funds पूरा कर लिया जायेगा । सभी विकास कार्य राज्य सरकार से अनुदान प्राप्ति के अनुसार ही किये जाते हैं मगर मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि विषयाधीन क्षेत्र नगर निगम, रोहतक में राज्य सरकार से अनुदान राशि प्राप्ति के बाद प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य करवाये जायेंगे ।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या बहन शकुन्तला खटक जी ने जो सवाल उठाया है उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में और केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी की इनकी अपनी सरकार थी । (विघ्न) मैं कहना चाहूंगा कि आज ये जो विकास कार्यों का श्रेय ले रहे हैं वह उचित नहीं है । अब केन्द्र में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ही इस मामले में स्वीकृति मिली है । (विघ्न)

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ हमेशा ही भेदभाव क्यों किया जाता है ? पहले तो मेरे साथ एम.एल.ए. फ्लैट देने में भेदभाव किया गया। सभी विधायकों को फ्लैट दिए गये लेकिन मुझे फ्लैट नहीं दिया गया। मेरे बच्चे भी चण्डीगढ़ में पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे फ्लैट की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष : आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया । आपने 3 सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछे थे तथा तीनों सप्लीमैंटरी प्रश्नों का जवाब सदन में आपको दिलवाया गया है। इसके अलावा जो आप एम.एल.ए. फ्लैट की बात कर रही हैं, इस बारे में मैं क्लीयर करना चाहूंगा कि हमारे पास विधायकों के फ्लैटों की संख्या केवल 36 है जो बहुत ही कम है जबकि हरियाणा विधान सभा में 90 विधायक हैं, इसलिए सभी विधायकों को फ्लैट देना संभव नहीं है। आपकी सरकार ने भी अपने समय में विधायकों के लिए फ्लैट नहीं बनवाये। (हंसी) बहन जी, अभी तो प्रश्नकाल चल रहा है, आप कृपया इस बारे में बाद में बात कर लेना।

Problem of Stray Animals

***272. Sh. Ranbir Singh Gangwa** : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to save the crops of farmers from the Stray Animals; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, वर्तमान में आवारा पशुओं को 408 गऊशालाओं, जिन्हे नगर निकायों तथा निजी संगठनों द्वारा संचालित किया जा रहा है, में रखा जाता है। हालांकि, इस समस्या की जटिलता को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा एक विस्तारयुक्त नीति बनाने का प्रस्ताव है, इसके अतिरिक्त, गऊ अभ्यारणों, गऊ सदन, गऊ गृहों की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। जो इस समस्या का निदान करने में दूरगामी साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आवारा पशुओं को लेकर सवाल पूछा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर गौ संरक्षण विधेयक पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। प्रदेश के अंदर 1.17 लाख आवारा पशु हैं जिनमें से लगभग 84,500 आवारा पशु ग्रामीण क्षेत्रों में और 32,500 आवारा पशु शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में 408 गौशालायें हैं

(श्री ओम् प्रकाश धनखड़)
जिनमें 3 लाख से भी अधिक पशु रहते हैं। इन पशुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए हमारे पास गऊ अभ्यारण बनाने के प्रस्ताव आये हैं। मुझे सदन को यह बताने में आनंद महसूस हो रहा है कि कई ग्राम पंचायतों ने हमारे पास ऑफर भेजे हैं कि उनके यहाँ गऊ अभ्यारण बनाये जायें जिसके लिए वे पर्याप्त जमीन देने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस कानून के तहत यह प्रस्ताव लेकर आई है कि शहरों और गाँवों में पशुओं के लिए एक नया मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ेगा । अभी जो पुराना मैकेनिज्म चला आ रहा था जिसको हम फाटक कह देते थे जिसमें पशुओं को रखा जाता था । पहले तो क्या होता था कि गाँवो अथवा शहरों में आवारा पशुओं को 2-3 दिन के लिए एक फाटक में बंद कर देते थे तथा यदि उन पशुओं का कोई मालिक मिल जाता था तो वह आकर अपने पशुओं को वापिस ले जाता था। लेकिन अब हम आवारा पशुओं को गऊ अभ्यारणों में भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ायेंगे। हमारा विभाग तो इससे भी आगे एक और कदम बढ़ाने की प्रक्रिया में अग्रसर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग इन अभ्यारणों में अपने पशु भेजना नहीं चाहते हैं तथा जिनके पास अपनी जगह भी नहीं है व किसी न किसी प्रकार से वे लोग उन पशुओं को प्रयोग में ला रहे हैं उनके लिए कोई स्थान बनाने की योजना भी चल रही है परिणामस्वरूप जो आवारा पशुओं की वजह से खेतों में नुक्सान होता है अथवा कोई दुर्घटना हो जाती है मैं समझता हूं भविष्य में निश्चित रूप से इन समस्याओं से हमें निजात मिलेगी।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो आवारा पशुओं का मामला है वह केवल किसानों का ही मामला नहीं बल्कि आम आवाम का भी मामला है। ये पशु शहर के अंदर भी लोगों के एक्सीडैंट्स का कारण बनते हैं। हमारे हिसार में एक बुजुर्ग औरत को आवारा पशु ने टक्कर मार दी जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की घटनाएं शहरों में रोज हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों की बात है तो हमारे यहां आज किसानों की हालत यह है कि उनको पूरी रात अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। अगर एक भी दिन यदि वह किसान बीमार पड़ जाए या उसको कोई काम पड़ जाए और वह अपने खेतों की रखवाली करने न जा पाए तो ये आवारा पशु उसकी 6 महीने की पूरी फसल साफ कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन आवारा पशुओं के लिए सरकार कह रही है कि हर पंचायत ने जगह देने की ऑफर की है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप मिनीमम नहीं तो मैक्सीमम बता दें कि इतने समय में हम यह काम कर देंगे ताकि इन आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिल सके । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बैलों का जो मेला लगता था उस मेले को बंद कर दिया गया जिसके कारण किसान आज परेशान हैं और उनकी इस मेले को खुलवाने की लगातार मांग रही है। पिछले दिनों हिसार में सचिवालय के अंदर किसान इस बात के लिए धरने पर भी बैठे थे। बैलों का जो मेला लगता था उसमें आपस में बैलों का आदान प्रदान हो जाता था और बैल बिक जाया करते थे। यहां तक कि रूसी सांड जिनसे हम खेती करते थे वे भी बिक जाया करते थे। अब किसान की हालत यह है कि जो अच्छी अच्छी बैलों की जोड़ी होती हैं उनको भी वे छोड़ देते हैं । खेतों को जोतने के लिए किसान को बैलों की जरूरत होती है उस समय तो वे बैलों को ले आते हैं और बाद में काम हो जाने के बाद उनको छोड़ देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज किसान का नुकसान हो रहा है इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस समस्या का निदान कब तक करवा देंगे तथा क्या सरकार पशु मेले को खोलने पर विचार करेगी ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की कंसर्ड बिल्कुल वाजिब है। हम में से अनेक लोगों के लिए यह चिंता का विषय है। कलानौर में मेरी गाड़ी के सामने भी पटरी के दूसरी तरफ से सांड इधर आ गए थे। ये सांड वास्तव में मक्खियों से बचने के लिए या मच्छरों से बचने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं जिसकी वजह से निश्चित रूप से दिक्कत है। मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आवारा पशुओं के लिए अभियारण्य बनाने के काम की इम्पलीमैंटेशन हम अगले इक्नोमिक इयर में शुरू कर रहे हैं लेकिन कितनी जगह की उपलब्धता है और कितने स्थानों पर हम इस काम को प्रफैक्टली कर लेंगे या कितने स्थानों पर और आगे ले जाना पड़ेगा इस समय मैं इसके बारे में अभी पूरा नहीं बता सकता लेकिन आंशिक रूप से जरूर कह रहा हूं कि इस आर्थिक वर्ष में कुछ अभियारण्य बनाकर इनकी शिफ्टिंग का काम हम शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय सदस्य ने मेले के बारे में पूछी है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि गौसंरक्षण कानून की इंस्ट्रक्शंज के कारण पशुओं के मेले में गाय और बैलों को ले जाना बंद किया गया था। गौसंरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वसम्मति से इस सदन में सख्त कानून पास किया गया है जिसकी देशव्यापी प्रशंसा हो रही है इसलिए जो प्रशंसा मुझे मिल रही है उस प्रशंसा को आप तक पहुंचाना भी मेरा दायित्व है। इस कानून के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस कानून के इम्पलीमैंट हो जाने के बाद हम पशु मेले में गाय बैलों पर लगी पाबंदी को खोल रहे हैं। अब किसी प्रकार के क्रय विक्रय पर कठिनाई नहीं होगी क्योंकि बहुत सख्त कानून हम ला रहे हैं। जैसे झोटा बुग्गी गाड़ी होती है और एक बैल की भी बुग्गी होती है, उसी तरह इसी कानून के तहत बैलों के लिए हम एक अच्छी टैक्नोलोजिकल गाड़ी बना रहे हैं ताकि लोग पहले वाली झोटा बुग्गी गाड़ी की बजाय इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लें और इस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पशु मेले पर लगी पाबंदी को कब तक खोल देंगे।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जैसे ही कानून नोटिफाईड हो जाएगा हम पशु मेले की इस पाबंदी को भी खोल देंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सचमुच में यह गंभीर विषय है और आवारा पशुओं की वजह से हमारे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। एरियावाईज किसान इकट्ठे होकर आवारा पशुओं से निपटने का इंतजाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की हुई है जिसके तहत 50 रूपये प्रति कैटल प्रति दिन दिए जाते हैं। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यदि वहां पर आवारा पशुओं के रख-रखाव के लिए 50 रूपये प्रति कैटल प्रति दिन दिए जाते हैं तो क्या हरियाणा सरकार भी उसी तर्ज पर अपने यहां आवारा पशुओं के रख-रखाव के लिए 50 रूपये प्रति कैटल प्रति दिन देने का प्रावधान करेगी ताकि किसानों की जेब से पैसे न लगें और उनकी फसल को भी नुकसान न हो। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लैटर भी लिखा है कि राजस्थान की तर्ज पर हमारे यहां भी 50 रूपये प्रति कैटल प्रति दिन दिए जायें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, ज्ञान जो है वह वट वृक्ष के नीचे बैठने के बाद आता है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध जी बैठे थे। किरण जी जिस समय मंत्री थी और 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय उनको यह ज्ञान नहीं आया और आज ये इस तरह की

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

बात कर रही हैं। (विघ्न) मान्यवर मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि 15 रूपये प्रति गाय देने के आदेश आये थे। उसके पीछे इनकी सरकार हाई कोर्ट में चली गई थी ताकि 15 रूपये प्रति गाय के हिसाब से न दिए जायें। सुप्रीम कोर्ट तक भी इनकी सरकार गई थी। यह ज्ञान माननीय सदस्या को उन बैंचिज पर बैठने के बाद आया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि अब हम तो इधर हैं लेकिन सरकार अब राजस्थान की तर्ज पर पैसे देगी या नहीं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या इतने कम समय में इतनी बदल गई । उस समय इनकी सरकार 15 रूपये के खिलाफ भी हाई कोर्ट में चली गई थी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुत अच्छा बिल गौ संरक्षण के लिए लेकर आई है। यदि 50 रूपये आवारा पशुओं के रख-रखाव और चारे के लिए दिए जायेंगे तो यह किसानों के लिए बहुत राहत की बात होगी । आज के दिन किसान भाई अपनी जेब से पैसे एकत्रित करके आवारा पशुओं को रोकने के लिए शैड व उनके चारे का इंतजाम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से यही जानना चाहती हूं कि सरकार राजस्थान की तर्ज पर 50 रूपये प्रति कैटल प्रति दिन के हिसाब से पैसे देने का काम करेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। (शोर एवं व्यवधान)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Check the Discease of Jaundice

***408. Sh. Ravinder Singh Baliala** : Will the Health Minister be pleased to state to whether there is any proposal under consideration of the Government to check the disease Jaundice (Hepatitis-C) in Ratia Constituency caused due to contaminated water of Ghaggar River ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं श्रीमान जी, रतिया निर्वाचनक्षेत्र में पीलिया (हेपाटाइटस-सी) घग्गर नदी के दूषित पानी के कारण नहीं होता है।

विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

पीलिया की बीमारी (हेपेटाइटिस सी) को रोकने बारे

रतिया निर्वाचन क्षेत्र में, पीलिया रोग (हेपेटाइटिस सी) घग्गर नदी के दूषित पानी की वजह से नहीं है। हैपेटाइटिस जिगर की सूजन है, जो वायरल संक्रमण के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस पांच प्रकार का होता है ए,बी,सी,डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित खाना खाने और दूषित पानी पीने से होता है। हेपेटाइटिस बी,सी और डी शरीर के संक्रमित तरल पदार्थों के साथ संपर्क में आने से, दूषित रक्त या रक्त उत्पादों की प्राप्ति से, दूषित सूई और सीरिंज के उपयोग से होता है।

- तीव्र हेपेटाइटिस में बहुत ही सीमित या कोई भी लक्षण नहीं हो सकता अथवा इसमें पीलिया (त्वचा व आखों का पीला होना) गहरा पीला मूत्र आना, अत्याधिक थकान, उबकाई, उल्टी व पेट में दर्द हो सकता है।
- हेपेटाइटिस एवं अन्य जल जनित रोगों के प्रकोप की रोकथाम के लिये, मानव उपभोग के लिये के लिए पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिये ओर्थोटोलिडीन परीक्षण और जीवाणू परीक्षण के लिये नियमित रूप से पानी के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। यदि पानी के नमूने इस परीक्षण में असफल हो जाते हैं तो उस जिले के जिला प्रशासन, जनस्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया जाता है ताकि तुरंत अपेक्षित कार्यवाही की जा सके। स्वास्थ्य विभाग उस क्षेत्र में आई0ई0सी0 गतिविधियों तथा पानी की क्लोरीनेशन के लिये क्लोरीन की गोलियों का वितरण शुरू करता है।
- हेपेटाइटिस-बी के लिए टीका उपलब्ध है और यह भी टीकाकरण अनुसूचित में शामिल किया गया है।
- जहां तक हेपेटाइटिस-सी का सम्बन्ध है, दिसंबर 2011 में, स्वास्थ्य अधिकारियों के ध्यान में आया कि कई लोग हेपेटाइटिस-सी के कारण बीमार पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बिमारी की रोकथाम के लिए आई0ई0सी0 गतिविधियों को शुरु कर दिया गया। इसके बाद पी0जी0आई0एम0एस0 रोहतक और पी0जी0आई0एम0ई0आर0 चण्डीगढ़ के विशेषज्ञों द्वारा रतिया निर्वाचनक्षेत्र के हर घर का सर्वेक्षण किया गया।
- सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि हेपेटाइटिस-सी में वृद्धि के कारण अनस्टेरिलाईजेड सूईयों का उपयोग तथा निजी चिकित्सकों द्वारा लगभग सभी मरीजों पर एक ही सूई का प्रयोग के माध्यम से, यौन मार्ग से, नसों में नशीली दवाईयां लेने से तथा उस समय अपंजीकृत ब्लड बैंक जोकि अब अस्तित्व में नहीं है, के अपरीक्षित खून से।
- स्वास्थ्य विभाग, अलर्ट के आधार पर शीघ्र और सक्रिय कार्यवाही कर रहा है और हरियाणा में सभी ब्लड बैंक नियमित रूप से हेपेटाइटिस-बी और सी के लिए जांच कर रहें हैं। हेपेटाइटिस-सी की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग और जिला स्तर पर आई0ई0सी0 गतिविधियों द्वारा की जा रही है।
- इन सभी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा हेपेटाइटिस सी के प्रबन्धन के लिए एक नीति तैयार की गई। इस नीति के अनुसार हेपेटाइटिस-सी का उपचार हरियाणा डोमिसाइल के अनुसूचित जाति/बी0पी0एल0 वर्ग के रोगियों को नि :शुल्क प्रदान की जाती है।
- पी0जी0आई0एम0एस0 का गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग हेपेटाइटिस सी रोगियों के प्रबन्धन के लिए नोडल केन्द्र हैं। डा0 प्रवीण मल्होत्रा विभागध्यक्ष, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग, पी0जी0आई0एम0एस0, रोहतक को उपचार चिकित्सक के रूप में नामित किया गया हैं।
- हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार 900 रोगी जो कि बी0पी0एल0 और अनुसूचित जाति वर्ग के हैं को नोडल केन्द्र से नि :शुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है तथा सामान्य श्रेणी के रोगियों के लिए उपचार रियाती दरों (जो कि हरियाणा के दर अनुबन्ध पर है) पर उपलब्ध है। लगभग 200 रोगियों का उपचार पूरा किया जा चुका है।

Railway Bridge

***446. Sh. Ved Narang** : Will the PW (B & R) Minister be pleased to state to whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Railway over bridge on the Barwala (Hisar) National Highway; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां श्रीमान जी, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के चारमार्गीय कार्य को शुरू करने की तिथि अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानी है, इसलिए बरवाला में रेलवे उपरगामी पुल को पूर्ण करने की समय सीमा, इस कार्य का हिस्सा होने के कारण, इस समय निर्धारित नहीं की जा सकती।

Water Supply upto Taill

***287. Sh. Makhan Lal Singla** : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply water upto the tail in Klusumbi minor and Mandauri minor and to check water theft in Sirsa Constituency; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, बलमंदोरी रजबाहा और कुसुम्बी माईनर के अन्तिम छोर तक, ज्यादा जरूरत और अधिक चोरी की अवधि को छोड़कर, ज्यादातर दिनों में पानी पूरा रहता है। सिरसा निर्वाचन क्षेत्र में पानी की चोरी रोकने के लिए और रात को गश्त लगाई जाती है। और पानी चोरी करने वालों पर कारवाई की जाती है।

To Open a Sub-Depot

***376. Sh. Om Parkash** : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sub-Depot of Haryana Roadways in Siwani Town of Loharu Constituency; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी,

To Open the Veterinary Hospital

***251. Sh. Rajdeep Phogat** : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Veterinary Hospitals in the villages Loharwara, Mirch, Sahuwas, Narsingwas, Dohki, Khatiwas and Kasni; if so, the time by which the said Veterinary Hospitals are likely to be opened ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी, गांव लोहरवाड़ा, मिर्च, साहुवास, नरसिंहवास, खातीवास तथा कासनी में पशुचिकित्सालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। हालांकि गांव डोहकी में राजकीय पशु औषधालय पहले से ही है।

Supply of Water by Haryana Government to Delhi

***328. Sh. Jaswinder Singh Sandhu :**

Sh. Parminder Singh Dhull :

Sh. Naseem Ahmed : Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) the quantum of water supplied to Delhi by Haryana Government during the year 2014-2015 togethewith the actual share of water settled to be supplied; and

(b) the quantum of excess water supplied to Delhi by the Haryana Government together with the date wise full detail thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) सरकार यह सुनिश्चित करती है कि दिल्ली को उसके अधिकृत हिस्से से अधिक पानी न छोड़ा जाए एवम् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना हो।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में मान्य नहीं हैं।

To Regularzie the Unauthorized Colonies

***123. Sh. Mahipal Dhanda** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the unauthorized colonies in Panipat (Rural) Constituency ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं श्रीमान जी,

To Open a Women College

***322. Sh. Nagender Bhadana** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Women College in NIT Faridabad; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी,

Lift Irrigation System

***442. Sh. Om Parkash Yadav** : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is a fact that Lift Irrigation System on JLM Canal is not working properly as the water Pumps/Motors are very old; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the old Pumps/Motors for proper functioning of abovesaid Lift Irrigation System?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां, श्रीमान जी, जवाहर लाल नेहरू फीडर प्रणाली पर कार्यक्षमता बहाल करने के लिए पुराने पम्पों तथा मोटरों का पुनरोद्धार तथा बदलाव की परियोजना सरकार के विचाराधीन है।

Supply of Drinking Water Through Canal

***346. Smt. Prem Lata** : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) the total number of tubewell based water works in the rural areas of the state;

(b) the total number of tubewell based water works where the quality of water is not upto the standard of drinking water;

(c) whether there is any proposal to change these tubewell base water works to canal based; and

(d) if so, the time by which this scheme will be implemented?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4904 नलकूप आधारित जलघर हैं।

(ख) इनमें से 55 जलघर ऐसे हैं जो जरूरी मानक अनुसार पेयजल उपलब्ध नहीं करते हैं।

(ग) व (घ) हां, श्रीमान जी, 73 नलकूप आधारित जलघरों को मार्च, 2017 तक नहर आधारित जलघरों में बदलने का प्रस्ताव है।

To Open a Sub-Depot in Guhla Cheeka

***353. Sh. Kulwant Ram** : Will theTransport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sub-Depot of Haryana Roadways in Guhla Cheeka ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी,

New Sabzi Mandi at Ganaur

***366. Sh. Kuldeep Sharma** : Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal to shift the New Sabzi Mandi of Ganaur if so, the time by which the new Sazi Mandi at Ganaura Town will be shifted; and

(b) the time by which the shops are liked to be allotted in the abovesaid Subzi Mandi togetherwith the price thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड) :

(क) जी हां, श्रीमान। परन्तु इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती।

(ख) स्थानान्तरण के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता। हालांकि मण्डी के स्थानान्तरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया जायेगा। अनुमोदित फार्मूला के अनुसार 20.5.2014 को 15'x27'-6" आकार की दुकान का अरक्षित मूल्य 69 लाख रुपये निर्धारित किया गया था। यद्यपि, आवंटन की तिथि वाले दिन प्रचलित आरक्षित कीमत ही चार्ज की जायेगी।

Use of Red/Amber/Blue Beacon

***506. Sh.Aseem Goel** : Will the Transport Minister be pleased to State whether it is a fact that unauthorized persons are using Red/Amber/Blue Beacon on the vehicles; if so, the steps taken by the Government to check the misuse of Red/Amber/Blue Beacon togetherwith details thereof ?"

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में एक तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

तालिका

श्रीमान् राज्य सरकार ने राज्य के गणमान्य व्यक्तियों/वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी के समय लेकर जाने वाले सरकारी वाहनों पर उपयोग हेतू विभिन्न प्रकार की बत्तियों के बारे में पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में हाल ही में अधिसूचना क्रमांक 24/17/81-3 टी (II), दिनांक 10.7.2014 तथा अधिसूचना क्रमांक 24/17/81-3टी (II), दिनांक 22.8.2014 सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की है। इसके अतिरिक्त रोगियों को लेकर जाने वाली एम्बुलैंस और आपात स्थिति कार्य के लिए विशेष रूप से नामित वाहनों यानि अग्नि शमन वाहन, बचाव वाहन इत्यादि, पर प्रयोग की जाने वाली बत्तियों को भी उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बत्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपयुक्त निर्देश संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने पत्र क्रमांक 9420-40/ टी-3/एएस-II, दिनांक 29.3.2013 द्वारा सभी सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को बत्तियों के दुरुपयोग के संबंध में संयुक्त जांच का एक विशेष अभियान आरम्भ करने के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक के साथ सम्पर्क करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, राज्य में सभी उपायुक्तों, उपसंभागीय अधिकारियों (ना0) तथा सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को पत्र क्रमांक 14449/टी-3 डीएसटी, दिनांक 30.5.2014 द्वारा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित जिलों में उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारी अपने सरकारी वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए प्राधिकृत स्टीकर एवं प्रमाण-पत्र के अनुसार ही बत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों और सभी सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों से एकत्रित की गई सूचना के अनुसार लाल/एम्बर/नीली बत्तियों के अनधिकृत प्रयोग के लिए 244 चालान वर्ष 2013 से 2015 यानि 1-1-2013 से 28-2-2015 तक जारी किए गए हैं। अनाधिकृत व्यक्तियों बत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Repair of Roads

80. Smt. Renuka Bishoni : Will the PW (B&R) Minister be pleased to State—

(a) whether the Government is aware of the fact that all the roads of Hansi Constituency particulaly Hansi to Umra and Shekhpura to Thurana are in dilapidated condition; and

(b) if so, the steps taken by the Government to repair and reconstruct all the roads falling in Hansi Constituency ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान जी। कुल 211.69 कि0मी0 सड़क लम्बाई में से केवल 96.31 कि0मी0 सड़क लम्बाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 96.31 कि0मी0 लम्बाई में से 39.78 कि0मी0 सड़क लम्बाई की निविदाए तीन भागों में 06/2014 के दौरान प्राप्त हो चुकी थी परन्तु बैंक आफ सैंक्शन निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण अनुमोदित नहीं की जा सकी।

हांसी से उमरा सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा गढ्ढों को भरकर यातायात योग्य रखा जा रहा है। जबकि शेखपुरा से थुराना सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

(ख) पूरे राज्य की सड़कों की दशा का सर्वेक्षण किया जा चुका है ताकि सड़कों की मरम्मत की प्राथमिकता धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सके।

Upgradatoin of Hospital

81. Sh. Nayab Saini : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the hospital of Naraingarh upto 100 beds and to provide the Trauma Centre therein; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

नहीं, श्रीमान जी।

Provision of Toilets and Drinking Water in School

99. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Education Minister be pleased to State—

(a) the total number of Government schools in Hansi Constituencey together with the total number of schools in which the facilities of toilets have been provided to the Boys and Girls students separately;

(b) whether the Government has formulated any scheme for providing separate facility of toilet for boys and girls students and for the provision of pure drinking water in all the school of the State; and if so, the details of the steps taken by the Government to provide the above said facilities ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

श्रीमान जी,

(क) हांसी, विधान सभा क्षेत्र में 136 राजकीय विद्यालय हैं, तथा सभी 136 राजकीय विद्यालयों में लड़के व लड़कियों के लिये पृथक-पृथक शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) हां, सरकार ने पहले से ही राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में लड़के तथा लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था की योजना बना ली है।

(ग) राज्य सरकार ने लड़के तथा लड़कियों के पृथक-पृथक शौचालय के लिये पहले से ही कदम उठाए हैं और राज्य के सभी विद्यालयों में यह व्यवस्था अति शीघ्र कर ली जायेगी। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 41.73 करोड़ रुपये की राशि, शौचालयों के निर्माण एवं मरम्मत और पीने के पानी के प्रावधान हेतु आंबटित की जा चुकी है। जन स्वास्थ्य विभाग को शेष विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था के लिये लिख दिया गया है।

Canal in Naraingarh

82. Sh. Nayab Saini : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a canal in Naraingarh; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

नहीं, श्रीमान जी,

Construction of Water Works

100. Smt. Renuka Bishoni : Will the Public Health Minister be pleased to State-

(a) whether the foundation stone was laid down by the Government for the construction of water works for providing the drinking water in villages Hajampur, Dhani Sakri, Dhani Gujrat, Dhani Raju Dhani Thakria of Hansi;

(b) if so, the details thereof together with the reasons for delay; and

(c) the steps taken by the Government to ensure the construction work of the above mentioned water works?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान जी !

(ख) हाजमपुर तथा ढाणी राजू, जिसमें ढाणी सकरी, ढाणी गुजरात, ढाणी ठाकरिया ढाणी पुरिया सम्मिलित हैं, का शिलान्यास 21.8.2014 को किया गया था। हाजमपुर में जलघर के निर्माण का कार्य 5.3.2015 को आवंटित किया जा चुका है। ढाणी राजू में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के कारण जलघर के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है।

(ग) हाजमपुर में जलघर के निर्माण का कार्य पहले ही आवंटित किया जा चुका है और यह कार्य 31.3.2016 तक पूरा होने की संभावना है। ढाणी राजू में जल घर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है और भूमि के कब्जे की तिथि के बाद डेढ़ वर्ष में कार्य पूरा होने की संभावना है।

Declaration of Shiwalik Area as Backward Area

83. Sh. Nayab Saini : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare the Shiwalik Area of Naraingarh as Backward Area; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : जी नहीं।

Reconstcuction of Road

84. Sh. Nayab Saini : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the Raiwali road in the Naraingarh Constituency; if so, the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

श्रीमान जी, यह सड़क दो भागों में निहित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग-72 से बोड़ा खेड़ा गांव तक का सड़क भाग मिलिटरी इन्जीनियरिंग सर्विस (एम0ई0एस0) से सम्बन्धित है तथा लम्बाई लगभग 1.00 कि0मी0 है। इस सड़क भाग की स्थिति खराब है।

(ii) गांव बोड़ा खेड़ा से बरवाला कस्बा वाया रायवाली लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) से सम्बन्धित है तथा लम्बाई 14.67 कि0मी0 है। लोक निर्माण विभाग की सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य 0.755 कि0मी0 लम्बाई के दो भागों में (आर0डी0 0.253 कि0मी0 से 0.648 कि0मी0 व आर0डी0 5.37 कि0मी0 से 5.73 कि0मी0) में प्रगति पर है तथा इसे 31.5.2015 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है। वर्तमान, में शेष सड़क के सुधार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल तो समाप्त हो गया लेकिन आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक गांव में एक महात्मा रहता था। वह बहुत अच्छे प्रवचन करता था । वहां पड़ोस में एक किसान का खेत था जिसमें किसान ने खरबूजे लगा रखे थे । किसान ने देखा कि खरबूजे रात के समय में रोज कम हो रहे हैं। उस किसान ने रखवाली शुरू कर दी कि मामला क्या है। किसान पैरों के निशान देखने लग गया। किसान ने देखा कि रोज पैरों के निशान महात्मा की कुटिया की तरफ जा रहे हैं और जूतियों के निशान हैं। महात्मा जी तो पैरों में कुछ पहनते नहीं थे और नंगे पैर रहते थे। किसान को जिज्ञासा थी कि पूरी जानकारी लेनी है। किसान को मालूम हो गया कि रात के समय में महात्मा ही जूती पहनकर आता है। उस गांव में एक सिद्ध महात्मा पहले हुए थे। अगले दिन किसान उनके प्रवचन सुनने चला गया। प्रवचन के दौरान महात्मा ने किसान से पूछा बोलो बच्चे क्या बात है। किसान ने कहा कि महात्मा जी आपकी बातें तो जो पहले महात्मा सिद्ध हुए थे उन जैसी हैं और आपकी जूतियां खदड़ू जैसी हैं जो गांव में सबसे ज्यादा गड़बड़ी करता है। (हंसी) अगर इसी तरह मैं विपक्ष के साथियों के पहले के पैरों के निशान देखता हूं तो कहीं ओर जा रहे हैं लेकिन वाणी श्रवण करता हूं तो सिद्ध महात्मा जैसी है। (हंसी)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अतिथि अध्यापकों पर कल लाठियां बांजी गई उसको लेकर कालिंग अटैंशन मोशन दिया था। उसका क्या फेट है ? बहुत से अतिथि अध्यापक घायल हो गए हैं उनकी दवाई-गोली का इंतजाम भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) कम से कम अतिथि अध्यापकों को रैगुलराईज किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आपका कालिंग अटैंशन मोशन आज ही प्राप्त हुआ है। यह विचाराधीन है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में दलित वर्ग की लड़कियों के साथ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर और प्रदेश में स्वच्छ पीने के पानी को लेकर दो कालिंग अटैंशन मोशन दिए थे उनका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : ये अभी विचाराधीन हैं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गन्ना मिलों द्वारा गन्ने की अदायगी न किए जाने सम्बंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री परमिन्द्र सिंह ढुल, एम0एल0ए0 द्वारा शुगर मिल्ज द्वारा किसानों के गन्ने का भुगतान न किए जाने संबंधी कालिंग अटैंशन प्राप्त हुआ है वह मैंने स्वीकार कर लिया है। परमिन्द्र सिंह ढुल जी आप अपना नोटिस पढ़िये।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के गन्ना उगाने वाले किसान जो अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करने के बावजूद गन्ना उत्पादन करने में सक्षम रहे लेकिन आज प्रदेश का गन्ना उत्पादक किसान विशेषकर मेरे अपने जिले जीन्द का किसान दर दर की ठोकरें खाकर अपनी फसल के पैसे लेने के लिए प्रदेश की चीनी मिलों में निरंतर गुहार लगा रहा है परन्तु बेबस किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। किस तिथि तक किसानों की धनराशि दी जा रही है। इस गम्भीर स्थिति के दृष्टिगत, सरकार को सदन के पटल पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

वक्तव्य

सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री विक्रम सिंह यादव) : श्री मान जी,

1. वर्तमान में हरियाणा में सहकारी क्षेत्र में 11 चीनी मिलें एवं 3 निजी क्षेत्र में कार्यरत है। 11 सहकारी चीनी मिलों की पिराई क्षमता 27300 टन प्रतिदिन है तथा निजी क्षेत्र की 3 चीनी मिलों की पिराई क्षमता 18000 टन प्रतिदिन है। 2014-15 के सत्र में गन्ने का कुल क्षेत्र 358062 एकड़ है, जिसमें से 212805 एकड़ सहकारी क्षेत्र एवं 145257 एकड़ निजी चीनी मिलों के क्षेत्र में है।

2. चालू सत्र 2014-15 (10.3.2015 तक) के दौरान सभी चीनी मिलों में 1234.05 करोड़ की कीमत का 404.34 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा है जिसके विरुद्ध 621.44 करोड़ रुपये राशि का भुगतान कर दिया गया है। हरियाणा में 431.55 करोड़ रुपये (10.3.2015 तक) सहकारी चीनी मिलों के पास बकाया देय हैं। पिछले पिराई सत्र 2013-14 में भी, इसी दौरान (10-3-2014 तक) 317.45 करोड़ रुपये का बकाया देय था। निजी क्षेत्र की मिलों के पास 470.41 करोड़ रुपये के पिराई किए गन्ने के मूल्य के विरुद्ध 181.06 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है।

(श्री विक्रम सिंह यादव)

3. पिछले सत्र में भी पिराई सत्र की समाप्ति पर सहकारी चीनी मिलों ने सभी गन्ना राशि के बकाया का भुगतान कर दिया गया था। पिछले तीन वर्षों में सहकारी चीनी मिलों ने निम्न अनुसार तिथियों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान किया था :-

पिराई सत्र	पूर्ण भुगतान की तिथि
2011-12	16.8.2012
2012-13	12.7.2013
2013-14	24.6.2014

4. मिलानुसार वर्तमान पिराई सीजन 2014-15 व पिछले सीजन 2013-14 में खरीदे गये गन्ने, गन्ना राशि के भुगतान एवं बकाया गन्ना राशि का विवरण (10 मार्च तक) निम्न प्रकार हैं-

सहकारी चीनी मिलें

मिलों के नाम	खरीदे गये गन्ने की मात्रा (लाखक्विं0)	कुल कीमत (रु0 करोड़ों में)	गन्ने की अदा की गई कीमत (रुपये करोड़ों में)	भुगतान तिथि	बकाया राशि 10.3.2015 (रुपये करोड़ो में)	पिछले वर्ष की बकाया राशि 10.03.2014 को (रुपये करोड़ों में)
पानीपत	18.24	56.26	16.14	25.12.14	40.12	30.57
रोहतक	31.16	95.08	29.18	31.12.14	65.91	53.03
करनाल	21.44	66.04	22.01	31.12.14	44.03	30.90
सोनीपत	16.29	50.00	18.89	10.01.15	31.11	26.01
शाहाबाद	44.66	137.92	92.94	31.01.15	44.98	21.67
जींद	15.07	46.21	11.67	31.12.14	34.54	29.70
पलवल	13.67	41.66	13.72	10.01.15	27.94	23.83
महम	21.37	65.18	17.60	05.01.15	47.58	31.05
कैथल	21.91	67.11	24.66	10.01.15	42.45	31.48
गोहाना	21.36	65.21	17.47	31.12.14	47.74	33.16
असंध	23.68	72.97	67.81	10.03.15	5.16	6.15
कुल	**248.87**	**763.64**	**332.09**		**431.55**	**317.45**

निजी चीनी मिलें

मिलों के नाम	खरीदे गये गन्ने की मात्रा (लाख क्विं0)	कुल कीमत (रु0 करोड़ों में)	गन्ने की अदा की गई कीमत (रुपये करोड़ो में)	भुगतान तिथि	बकाया राशि 10.3.2015 (रुपये करोड़ो में)	पिछले वर्ष की बकाया राशि 10.03.2014 को (रुपये करोड़ों में)
यमुनानगर	96.83	292.04	194.96	10.02.15	97.08	42.09
भादसों	26.78	81.72	57.69	31.01.15	24.03	9.95
नारायणगढ़	31.86	96.65	36.70	12.01.15	59.95	27.46
कुल	**155.47**	**470.41**	**289.35**		**181.06**	**79.50**

5. वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान गन्ने की अगेती, मध्यम व पछेती वर्ग की सभी किस्मों के राज्य सुझावित मूल्य (SAP) का विवरण निम्न प्रकार है :-

पिराई सीजन		किस्मानुसार गन्ने की मूल्य (रु0 प्रति क्वि0)		9.5 चीनी प्राप्ति (प्रतिशत) के आधार पर FRP (रु0 प्रति क्वि0)
	अगेती	मध्यम	पछेती	
2010-11	220	215	210	139.12
2011-12	231	226	221	145.00
2012-13	276	271	266	170.00
2013-14	301	295	290	210.00
2014-15	**310**	**305**	**300**	**220.00**

6. राज्य सरकार ने पिराई सीजन 2014-15 के लिए गन्ने की अगेती किस्मों में 9/- रु0 प्रति क्विंटल तथा मध्यम एवं पछेती किस्मों में 10/- रु0 प्रति क्विंटल की बढ़ौतरी की है। यह मूल्य देशभर में गन्ने का सर्वाधिक राज्य सुझावित मूल्य हैं। 2010-11 में 220/- प्रति क्विंटल की दर से राज्य सुझावित मूल्य को 40.91 प्रतिशत बढ़ाकर 2014-15 में 310/- प्रति क्विंटल कर दिया गया। दूसरी ओर चीनी के मूल्य जोकि 2010-11 में घोषित थे वे अब भी उसी मूल्य पर है। वर्ष 2010-11 में 2708/- प्रति क्विंटल की दर के विरूद्ध चालू वर्ष (दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015 तक) 2660/- प्रति क्विंटल की दर से चीनी की औसत कीमत मिल रही है।

7. चीनी मिलों को चीनी की कीमतों में हाल ही के महीनों में जबरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय बाजारों में चीनी का मूल्य कई कारको नामत : चीनी का उत्पादन, रख रखाव, स्थानीय मांग, अंतराष्ट्रीय चीनी मूल्यों तथा बाजार की भावनाओं पर निर्भर करता है। घरेलू चीनी कीमतें (औसत फरवरी 2015 में 2640/- रुपये प्रति क्विंटल) है जोकि अप्रैल 2014 में 3200/- रु0 प्रति क्विंटल के विरुद्ध 17.50 प्रतिशत कम है।

8. राज्य सरकार ने चीनी क्षेत्र को तुरन्त राहत देने के लिए निम्नलिखित पग उठाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रार्थना की है :-

1. पूर्व पांच पिराई सत्रों में चीनी मिलों द्वारा भुगतान किये गये उत्पादन शुल्क के समकक्ष ब्याज रहित ऋण प्रदान करना।

2. अधिक घरेलू उत्पादन के दृष्टिगत वर्तमान आयात शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना।

3. घरेलू भंडार पर दबाव कम करने तथा घरेलू कीमतों को प्रोत्साहित करनें के लिए कच्चे माल पर निर्यात सब्सिडी में वृद्धि करना।

9. राज्य सरकार नियमित रूप से चीनी मिलों की तरफ बकाया गन्ना राशि की स्थिति की निगरानी कर रही है। राज्य सरकार ने गन्ना भुगतान के लिए वर्ष 2014-15 के बजट में 190.00 करोड़ की प्रस्तावित पूर्ण राशि को जारी कर दिया है। इसके इलावा राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में 290.00 करोड़ रु0" सहकारी चीनी मिलों को ऋण" मद के अन्तर्गत प्रदान करं दी गई है ताकि पिराई सत्र 2014-15 की समाप्ति के उपरान्त मिलों के लिये गन्ने की राशि का भुगतान संभव हो सके।

(श्री विक्रम सिंह यादव)

गन्ना किसानों द्वारा चीनी मिलों को प्रदान किये गये गन्ने का समय पर भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, लिखित जवाब सदन के पटल पर रख दिया गया है मेरे माननीय साथी श्री परमिन्द्र ढुल जी ने किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की है। इसके चलते मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछली सरकारों में सहकारिता शुगर मिलों ने गन्ने की पिराई सत्र के बाद में गन्ने की अदायगी की है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार चेयर पर पदासीन हुये)। उसी प्रकार से इस बजट में 290 करोड़ के ऋण का प्रावधान किसानों की पेमैंट देने के लिए रखा है। जिस समय पिराई का सीजन 2014-15 समाप्त होगा उसके तुरंत बाद किसान की गन्ने की पेमैंट का भुगतान करवा दिया जायेगा।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से किसी भी रूप में संतुष्ट नहीं हूं। मेरे मोशन का जवाब नहीं आया है। प्रदेश के अंदर गन्ने की पेमैंट लेने के लिए किसान शुगर मिलों के एम.डीज. के पैर पकड़ रहे हैं फिर भी उनको पेमैंट नहीं मिल रही है। मेरे पास किसानों की पूरी लिस्ट है। जनवरी से आज तक एक पैसा किसानों को नहीं मिला है। 40-40 लाख रूपये एक-एक किसान के शुगर मिलों की तरफ बकाया हैं। वह किस प्रकार से अपने खर्च चलायेगा। किसानों को भात भरना है और दूसरे कार्य भी करने हैं इसलिए किसान अपनी पेमैंट लेने के लिए शुगर मिल्ज के एम.डीज. के पैर तक पकड़ रहे हैं लेकिन उनको पेमैंट नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त सुनने में आ रहा है कि सरस्वती शुगर मिल को भी बंद करने की तैयारी चल रही है। उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और कोई भी उसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की जो धान की खरीद हुई उससे आढ़ती भी इतना कमजोर हो चुका है कि उसकी भी बहुत सी पेमैंट पैंडिंग पड़ी हैं। आज आढ़ती ने भी पैसे देने में असमर्थता जाहिर कर दी है, उसने भी हाथ उठा दिये हैं। बैंक कर्जा नहीं दे रहा है, किस प्रकार से किसान चलेंगे? मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि एक आदमी जिसका नाम प्रताप पुत्र श्री धूपे, गांव सिवाय, जिला जीन्द का रहने वाला है। उसकी पेमैंट रुकी हुई थी उसने पैर भी पकड़ लिए कि मुझे दो लाख रूपये की सख्त जरूरत है। मुझे भात भरना है और लड़की का पीलिया देना है लेकिन उसको पैसे नहीं मिले। वह 10 दिन से पैसे के लिए भटक रहा था वह मुझे 13 तारीख को आ कर मिला था। इसके अतिरिक्त हमारे राजपुरा और गुलकनी गांव की लिस्ट है जिसके कुछ नाम मैं सदन के सामने बताना चाहता हूँ जो इस प्रकार हैं :- रामफल, राजा, लीला, प्रवीन, परमिन्द्र, प्रकाश, राजेन्द्र, बनीसिंह, प्रवीण, नरेन्द्र, हवा सिंह तथा जयवीर। सभापति महोदय, इन लोगों के लाखों रूपये की पेमैंट रुकी हुई है। ये तो केवल कुछ ही नाम हैं इसके अलावा भी बहुत से किसान हैं जिनकी पेमैंट पैंडिंग है। इसी प्रकार से आज आपकी नाक के नीचे सरस्वती शुगर मिल बंद कर दी गई, उसके बाहर बंद करने का नोटिस चिपका दिया गया है और लोगों की पेमैंट बकाया है। किसान जायें तो जायें कहाँ? आप किसानों की नहीं सुन रहे हैं तो किसकी सुनेंगे। पिछली सरकार के समय में अगर शुगर मिल किसानों की पेमैंट करने में अक्षम होती थी तो सरकार फौरी तौर पर उनको सहायता प्रदान करती थी ताकि किसानों को मरने न दिया जाये। सभापति महोदय, आज किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है इसलिए सरकार की तरफ से इसका स्पष्ट जवाब आना चाहिए। जिस समय चौटाला जी की सरकार थी उस समय मिलों की विशेष रूप से आर्थिक सहायता की गई ताकि किसानों का पैसा समय पर मिल सके।

श्री विक्रम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से पिराई का सीजन खत्म हो गया था तो किसानों को उनका भुगतान वर्ष 2011-12 में 8वें महीने की 16 तारीख तक किया गया । वर्ष 2012-13 में 7वें महीने में किया गया और जो 2013-14 का आखिरी भुगतान किया गया वह 24.6.2014 तक किया गया । उसी के तहत मैं बताना चाहता हूँ कि 2013-14 में सरकार से 190 करोड़ रूपये का ऋण लेकर गन्ने का पूर्ण भुगतान किया गया। उसी प्रकार से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2015-16 के लिए हमने 290 करोड़ रुपये ऋण का प्रावधान रखा है तथा जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों को गन्ने का भुगतान किया है उसी प्रकार किसानों का पाई-पाई का भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : सभापति महोदय, मैं जो बात मंत्री जी से पूछना चाहता था उसका जवाब नहीं दिया गया है।

श्री सभापति : ढुल साहब, आप दो सप्लीमैंट्री पूछ चुके हैं ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : सभापति महोदय, गन्ने की फसल किसान की पूरे साल की मेहनत की कमाई होती है और किसान को अपने हर प्रकार के काम करने के लिए जैसे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनकी शादी वगैरह और मकान आदि के काम के लिए पूरे सालभर तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद गन्ने की सप्लाई होती है और उसके बाद उसकी पेमैंट न हो तो किसान को बहुत तकलीफ और समस्या का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने जो पूर्ववर्ती सरकार का जिक्र किया है किस तारीख तक किसानों को उनके गन्ने का भुगतान किया जाता था तो मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ और यह रिकॉर्ड की बात है कि पिछली सरकार में हर 15वें दिन किसान का गन्ने का भुगतान कर दिया जाता था, कभी भी 16वां दिन नहीं हुआ।15वें दिन हर शुगर मिल में हर किसान की गन्ने की पेमैंट की जाती थी। अगर आज की बात की जाये तो किसानों की अब तक गन्ने की केवल एक पेमैंट हुई है और मिलें बंद होने को जा रही हैं । अब मिलें 15-20 दिन और चल पायेंगी उसके बाद बंद ही हो जायेंगी। किसानों का मिल मालिकों की तरफ लाखों रूपये का बकाया पड़ा हुआ है और पिछली सरकार का नाम लेकर सदन को बरगलाने की कोशिश न की जाये। जो हकीकत है उसके बारे में बताने की कोशिश करें कि अब तक किसानों को उनके गन्ने का बकाया का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? हर 15वें दिन किसान की पेमैंट होती है। किसान का इतना लम्बा समय बिना पैसे के काम कैसे चलेगा ? सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसान सारा साल बहुत मेहनत करके गन्ने की फसल पैदा करता है और सारे साल की मेहनत की अगर समय पर पेमैंट न मिले तो यह बड़े दुख की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके किसान की पेमैंट की जाये।

श्री विक्रम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि अब भी हमारी सभी मिलों की हालत यह नहीं है कि लम्बे समय की पेमैंट बकाया है।

फरवरी 2015 तक हमारी कुछ शुगर मिलों ने पैमेंट कर दी है और जीन्द की जहां तक बात है वहां की शुगर मिल ने 31.12.2014 तक की पेमेंट क्लीयर कर दी है और उनकी जो पेमैंट बाकी रह गई है उसका भी प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि मई मास में जो पिराई का सीजन समाप्त होगा उसके तुरन्त बाद उसकी पेमैंट कर दी जाएगी।

श्री आनन्द सिंह दांगी : सर, शुगर मिलों को चलते हुए पांच महीने हो गये क्योंकि सारे शुगर मिल नवम्बर में चलने शुरू हो जाते हैं और 15 अप्रैल तक सारे बन्द हो जाते हैं। पांच महीने के अन्दर अब तक किसानों के गन्ने की केवल एक पेमैंट हुई है जबकि अब तक दस पेमेंट हो जानी चाहिए थी और फिर भी इस तरह की बात करके सदन को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है जिसकी वजह से किसान के गन्ने की पेमैंट नहीं हो रही ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड) : सभापति महोदय, मान्यवर सदस्यों की जो चिन्ताएं हैं वह स्वाभाविक और व्यवहारिक हैं। कल भी एक बार कादियान साहब ने इस सवाल को उठाया था तो उस समय भी मैंने उत्तर दिया था। सर, इस बार हमको दो-तीन कठिनाइयां हैं। एक कठिनाई यह है कि बाजार में चीनी के जो भाव मिलने चाहिएं थे वह भाव आज बाजार में नहीं हैं। इसी कारण आज देश भर में चीनी का बाजार डाऊन है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या केवल अपने प्रदेश की है। यह सभी प्रदेशों की समस्या है। सभी चीनी मिलों की समस्या है। उत्तर प्रदेश में किसानों का 8 हजार करोड़ रूपया बकाया हो गया है। हमारे साथ इसके अतिरिक्त और भी एक संकट है और इस बात की खुशी भी है कि देश में सबसे अच्छे भाव हम दे रहे हैं। वह भाव का डिफरैंस चीनी मिलों के लिए और भी ज्यादा समस्या बना हुआ है। सरकार इस बात पर अडिग है कि जो भाव घोषित हुआ है निश्चित रूप से उसी भाव से किसानों की पेमैंट का भुगतान हो। अभी तक जो को-आपरेटिव मिलें हैं उसमें 763 करोड़ रूपये का गन्ना आया है जिसमें से 332 करोड़ रूपये का भुगतान हो गया है। एक-दो मिल तो बहुत अच्छा भुगतान कर रहे हैं । जिस प्रकार से असंध के शुगर मिल ने तो मार्च की 10 तारीख तक का भुगतान भी कर दिया है लेकिन कुछके मिल्ज ऐसी हैं जिनका भुगतान दिसम्बर के बाद का नहीं हुआ है केवल एक-दो मिल का भुगतान जनवरी तक आया है जिसमें से 431 करोड़ रूपये अभी बकाया हैं। पिछले साल भी इस समय तक 317 करोड़ रूपये बकाया थे लेकिन मैं उसको कोई मानक नहीं मान रहा। मैं बताना चाहता हूं कि जो प्राईवेट मिलें हैं उन्होंने इस समय 470 करोड़ रूपये का गन्ना खरीदा है जिसमें से 289 करोड़ रूपये की पेमैंट हो गई है और 181 करोड़ रूपये की पेमैंट अभी बकाया है। पिछले साल भी इस समय तक लगभग 80 करोड़ रूपये बकाया थे और 100 करोड़ रूपये और अतिरिक्त इस बार का बकाया है लेकिन सरकार इस मामले में पूरी कंसर्ड है। आप सबको जानकारी है कि सरकार मिल्स को सहयोग करती है। हमारी मिल्स जिस प्रकार अपने आप जिस मुनाफे पर चलनी चाहिए वैसी उन सब मिलों की स्थिति नहीं है। जैसा कि माननीय वित मंत्री जी ने बताया कि उन मिलों के लिए पैसे का प्रावधान किया है और उन मिलों को सहयोग किया जाएगा। पंजाब सरकार ने भी कल एक उपाय किया है और उस उपाय का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जिस प्रकार से कई मामलों में अपनी स्टेट दूसरी स्टेटों से काफी अच्छी है क्योंकि बाकी सब राज्य उस लैवल पर हमारी बराबरी नहीं कर पाते। मान लो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के भाव में ज्यादा गड़बड़ होती है तो उसका असर हमारे यहां नहीं आना चाहिए। अगर वहां का भाव 52 रूपये प्रति क्विंटल है तो उसका असर हमारे यहां न आए। ऐसे कुछ उपायों पर भी सरकार ने विचार किया है। हम भी उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं कि हम हमेशा कुछ अच्छी चीजें बढ़ाएं। जिस रास्ते से हमारे प्रदेश में चीनी आती है वह उतनी सस्ती न पड़े हम इस रास्ते पर भी आगे बढ़ रहे हैं जिससे अपने यहां के उद्योगों को और किसानों के हितों को संरक्षित किया जा सके। इसी तरह से हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपने राज्य की जो खपत है

हम अपनी चीनी मिलों से करें जिससे उनको कुछ आर्थिक मदद मिल जाए और वह उसको जल्दी खरीद सके। इस उपाय पर भी सरकार आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त भी कुछ उपायों पर जाना पड़ेगा उस पर भी सरकार विचार कर रही है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर रहा हूं कि किसानों के बारे में बिल्कुल भी चिन्ता न करें। एक-एक किसान का पूरा भुगतान किया जायेगा और सारी की सारी चीनी मिलें अनवरत रूप से चलेगी ।

श्री घनश्याम दास : माननीय सभापति महोदय, इस गरिमामय सदन में कुछ सम्मानित सदस्यों ने गन्ने का भुगतान न होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं भी उनके साथ इस चिन्ता में चिन्तित हूँ परन्तु जो एक किसान, गन्ना मिल और उपभोक्ता आदि इस कड़ी के तीन महत्वपूर्ण अंग है यदि हमने सारी स्थिति को अच्छी तरह से न समझा........... (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : सभापति महोदय, मैंने इसके बारे में सप्लीमैंट्री दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे पता है। प्लीज, आप बैठ जाईये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति महोदय, कॉलिंग अटेंशन मोशन के ऊपर जिन सदस्यों के साईन होते हैं वे ही पूछ सकते हैं। श्री घनश्याम दास जी के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर साईन ही नहीं है। सभापति महोदय, जिन्होंने कॉलिंग अटेंशन मोशन दे रखा है पहले उनको बोलने का मौका दीजिए। यह किसान से जुड़ा हुआ मामला है। जिन लोगों ने कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया है, आप पहले उनको बोलने का मौका दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : ठीक है। प्लीज, बैठ जाईये।

श्री घनश्याम दास : सभापति महोदय, मेरे बारे में यह बात कही गई है कि मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूँ! मैं इस विषय पर बिल्कुल भी भाषण नहीं देना चाहता हूँ। मैं सभी सम्मानित सदस्यों को तथ्यों की जानकारी देना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि गन्ने का मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। आज जो मूल्य किसानों को दिया जा रहा है वह हरियाणा प्रदेश में भारतवर्ष के सभी प्रदेशों से गन्ने का मूल्य सबसे अधिक है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के साथ लगते जो दूसरे प्रदेश हैं, उनकी क्या स्थिति है, मैं उसके बारे में आपके माध्यम से थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति महोदय : घनश्याम जी, आप अपना सुझाव दें या सप्लीमैंट्री पूछें। आप क्या कहना चाहते हैं? परमिन्द्र सिंह ढुल जी, प्लीज बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री घनश्याम दास : सभापति महोदय, किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर होना चाहिए और उसके लिए सरकार जो कदम उठा रही है उसमें कुछ और कदम जोड़ दिए जायें तो मुझे लगता है कि किसानों को जो भुगतान की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, वह नहीं होना पड़ेगा और इसके साथ ही मैं गरिमामय सदन में बताना चाहता हूँ कि जब-जब चीनी के दामों में कमी आई है तब-तब पिछला इतिहास यह बताता है कि......... (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : मलिक जी, प्लीज बैठ जाईये। घनश्याम दास जी, आप कंक्लयूड करके अंतिम सुझाव दे दें कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदय, माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : मलिक जी, प्लीज बैठ जाईये । घनश्याम जी आप सुझाव दें।

श्री घनश्याम दास : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को मेरे बोलने पर आपत्ति है और उनको ऐसा लगता है कि मैं विषय से हटकर बात कह रहा हूँ । सभापति महोदय, मैं निष्कर्ष रूप से यह कहना चाहूँगा कि किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर हो। सरकार को ऐसी चिन्ता करनी चाहिए।

श्री सभापति : मैं प्रतिपक्ष नेता को कहना चाहता हूँ कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है उस पर केवल माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र ढुल के हस्ताक्षर हैं, बाकी किसी माननीय सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। उस हिसाब से दो सप्लीमैंट्री पूछी जा सकती हैं। एक माननीय सदस्य सरदार जसविन्द्र सिंह संधू और उसके बाद माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल ने बड़े अहम मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की है। जब प्रदेश के अन्दर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो पिछला 16 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार ने आते ही किया था और जो नारायणगढ़ की शुगर मिल बिल्कुल ही बंद हो गई थी, सरकार ने फाइनैंस करके किसानों की बकाया पेमैन्ट दिलाने का काम किया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो शुगर मिल्ज बंद हैं और किसानों की बकाया पेमैन्ट नहीं कर सकी, मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे फाइनैंस करके या फंडिंग करके किसानों का भुगतान करें, इस बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दें।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ कि जितनी भी हमारी 11 को-ओपरेटिव मिल्ज हैं सबको लोन सरकार देती है और अब तक 290 करोड़ रुपये का लोन आवंटित किया है, उसमें एक किस्त किसानों को मिल चुकी है। सरकार बकाया लोन दे रही है, किसी भी को-ओपरेटिव मिल में किसी भी प्रकार के भुगतान की कोई कमी नहीं रहेगी । इसके अलावा प्राईवेट मिल्ज के मामले में जो रेट का अन्तर 17 प्रतिशत है उस नाते से उनको भी किसी न किसी प्रकार से प्रोटैक्ट करने की आवश्यकता है। टोटल चीनी के व्यवसाय को प्रोटैक्ट करने में सरकार तीनों उपाय अपना रही है। एक जो बाहर से चीनी आये वह यहां महँगी होकर आए उस पर कुछ एक्साइज ड्यूटी लगा दें, दूसरा उपाय अपना रही है कि जो प्रदेश की चीनी की खपत है वह अपनी चीनी मिल्ज से जल्दी ले ली जाये और तीसरा उपाय जो अपने यहां से चीनी बाहर भेजते हैं उसमें अगर सब्सिडी बढ़ती है तो बढ़ाई जाये। सभापति महोदय, इस व्यवसाय की जो अंतिम कड़ी किसान हैं उसके सारे सिस्टम को वॉयबल बनाकर रखा जा सके, इस प्रकार के उपायों पर सरकार सोच रही है और आगे भी बढ़ रही है। मैं इसके अलावा कुछ बातें संकेत में कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था में सरकार की मदद करनी है तो आगे बढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति महोदय, माननीय सदस्य सरदार जसविन्दर सिंह संधू ने जो सवाल उठाया है, उसके सम्बंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि पीछे हमारी सरकार ने जिस ढंग से हरियाणा फाईनैंस कॉरपोरेशन से पैसा लेकर जो नारायणगढ़ शुगर मिल बिल्कुल ठप्प हो गई थी और बंद होने के कगार पर खड़ी थी, किसानों से यह कहा गया था कि शुगर मिल भुगतान करने में असमर्थ है, इसलिए इस शुगर मिल को कुर्क कर लें, हमारी सरकार ने उस शुगर मिल मालिक को बुलाकर सरकार की तरफ से पैसे

दिये गये और, कहा कि आप इस शुगर मिल को चलाकर किसानों का भुगतान करने का काम करें। सभापति महोदय, क्या सरकार इसी तरह से जो सरस्वती शुगर मिल बंद हो रही है उसके मालिक को बुलाकर उससे बातचीत करके किसानों का भुगतान कराने का प्रयास करेगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : सभापति महोदय, शुगर मिल अभी चल रही है । अगले सीज़न के लिये बंद करने की बात कही गई थी लेकिन सरकार ने पूरी तरह से शुगर मिल के ऊपर निगाह रखी हुई है, इसलिए शुगर मिल ना अब बंद है और ना ही आगे बंद होगी, इस तरीके के की जा चुकी है। उपाय सरकार कर रही है। यमुनानगर सरस्वती शुगर मिल को 292 करोड़ रुपये का भुगतान करना है जिसमें से लगभग 195 करोड़ रुपये की अदायगी है और बकाया अदायगी 97 करोड़ रुपये की है।

सभापति महोदय, मुझे इस मिल की सबसे ज्यादा चिंता है क्योंकि यह बहुत बड़ी मिल है और यह आधी कॉ-आपरेटिव मिल जितना गन्ना अकेली पिराई करती है। इस मुद्दे पर हमारे साथी घनश्याम जी और माननीय अध्यक्ष जी भी कंसर्न्ड थे। अध्यक्ष जी इस वक्त सदन में मौजूद नहीं है। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों यमुनानगर जाकर उसको देखकर आए थे। हमने वहां के किसानों से इस बारे में बातचीत की है। हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) इस विषय पर सरकार स्टैप बाई स्टैप आगे बढ़ रही है। मैं सदन के माध्यम से अपने किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी पिछले कैलेंडर के महीनों के हिसाब से पूरी पेमेंट की जाएगी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। यह किसानों से जुड़ा हुआ बड़ा ही अहम मुद्दा है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने आदरणीय ढुल साहब द्वारा दी गई कालिंग अटैंशन मोशन को असैप्ट किया और उस पर चर्चा कराई। काबिल मंत्री श्री धनखड़ जी ने सरकार की मजबूरियों को भी बताया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, इसमें पेमैंट की भी एश्योरेंस हुई है। यह पहली बार हुआ है कि किसी प्राइवेट शुगर मिल के मालिक ने यह घोषणा की है कि वह अगले साल मिल को बंद कर देगा। इस मिल की पिराई क्षमता सवा लाख क्विंटल प्रति वर्ष के करीब है। स्पीकर सर, प्राइवेट कन्सर्न्ड ओरगनाइजेशन की इस तरह की स्टेटमैंट से किसान बड़ा भयभीत हो जाता है। वह सोचता है कि अब मेरे गन्ने की फसल का क्या होगा, मैं आगे गन्ना लगा पाऊंगा या नहीं, इस गन्ने की फसल को मैं उजाडूंगा या रखूंगा, अगर गन्ना नहीं लगाऊंगा तो कौन-सी फसल पैदा करूंगा। इस तरह के विचार उसके मन को विचलित कर देते हैं। चूंकि मंत्री जी शुगर कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं अत : मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि इन मिलों को ग्रांट दी जाए या प्राइवेट शुगर मिल मालिकों को समझाया जाए कि अगर वे इस तरह के बयान देंगे तो सरकार मिल को टेक ओवर कर लेगी। ये मिलें 15-15 साल से लगी हुई हैं। अगर आप चैक करें तो इनकी डैप्रिसिएशन वैल्यू जीरो आएगी। इनको टेक ओवर करने में सरकार का पैसा भी नहीं लगेगा और किसान को भय से भी निकाला जा सकेगा। अत : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति आई तो क्या सरकार इसको टेक ओवर करने की प्रोसिडिंग लांच करेगी?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी डॉ. कादियान ने मिल के बंद होने के विषय में बताया है तो मैं भी इनके साथ अपनी बात जोड़ना चाहता हूं। आज जो किसान गन्ना पैदा

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

करता है वह प्राइवेट मिल मालिकों की मिल न चलाने की स्टेटमैंट से बहुत दुविधा में है कि मेरे गन्ने का क्या होगा, मैं आगे गन्ने की बिजाई करूं या नहीं, अगली बार मिल चलेगी या नहीं । इस तरह से किसानों को बड़ा भारी नुक्सान हो रहा है । इस तरह के हालात यू.पी. समेत कई और प्रदेशों में भी पैदा हुए थे लेकिन यू.पी. सरकार ने प्राइवेट मिल मालिकों से 40 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को सीधे पेमेंट करने का फैसला किया है। आज देश में किसानों के गन्ने के 15 हजार करोड़ रूपये बकाया हैं। आज हरियाणा सरकार कम से कम एक बात का तो आश्वासन दे कि या तो सरकार मिल को टेक ओवर करे या उनको सब्सिडाइज्ड करे जैसे यू.पी. सरकार ने किया है ताकि मिल चलती रहे और किसानों का गन्ना बिके।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की चिंता से सरकार पूरी तरह से वाकिफ है। मैं मानता हूं कि हमारी प्राइवेट चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की बजाय अच्छी चल रही हैं । उत्तर प्रदेश का इतिहास ज्यादा बुरा है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की हालत हम से ज्यादा खराब है। इस प्रकार की स्थिति वर्ष 2002 में भी आई थी जब चीनी के भाव ज्यादा डाऊन चले गये थे । उस समय सरस्वती मिल ने भी दिसम्बर के महीने तक गन्ने की पिराई शुरू नहीं की थी। उस समय ऐसा विषय था और सरकार ने उस मिल को टेक ओवर करने की बात कही थी। अब भी जितनी समस्या है जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस समस्या के समाधान के हिसाब से सरकार ने हर संभव स्टैप्स उठाये हैं। फिलहाल ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली है। अध्यक्ष जी, आप तो स्वयं जानते हैं क्योंकि आप भी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यमुनानगर मिल मालिकों से मिलकर उनको पूरी तरह आश्वस्त करवाया कि किसानों को ऐसी कोई नौबत नहीं आयेगी। मैं आपके माध्यम से गरिमामय सदन को बताना चाहूंगा कि किसानों के हित के लिए सरकार की हर ऑप्शन खुली है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब मैंने किसानों के बारे में कालिंग अटैंशन मोशन सदन में प्रस्तुत किया था उस समय मेरे मन में यह बात जरूर आई थी कि इस कालिंग अटैंशन मोशन के बारे में जब चर्चा होगी तो उस चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से कोई ऐसा आश्वासन आयेगा जो कोआप्रेटिव शुगर मिलों की किसानों की पेमैंट बकाया है उसका भुगतान सैशन के दौरान ही कर दिया जायेगा। आज किसान बहुत परेशान हैं। मैं इस बारे में मंत्री जी को दोबारा से फिर वही बात बताना चाहता हूं क्योंकि वे ओरीजनल जवाब नही दे रहे थे। आज मेरे अपने जिले का गन्ना उत्पादक किसान गन्ने की पेमैंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपनी फसल के पैसे लेने के लिए प्रदेश की चीनी मिलों से निरन्तर गुहार लगा रहा है लेकिन उस बेबस किसान की बात कहीं पर भी नहीं सुनी जा रही। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस महीने तक किसानों के गन्ने का भुगतान किया गया है। आपने अपने जवाब में बहुत बढ़िया बात बताई हैं लेकिन उसमें आपने कोई तिथि नहीं बताई कि कब तक इस पैसे को दे दिया जायेगा। मेरे जिले जीन्द के किसानों को तीन दिसम्बर, 2014 को पेमेंट दी गई थी। 31 दिसम्बर, 2014 तक बहुत थोड़ी एमाउंट थी वह तो दे दी गई लेकिन 1.1.2015 से लेकर आज तक किसान का एक पैसा भी रिलीज नहीं किया गया है सिर्फ असन्ध की शुगर मिल का मार्च तक का पैसा रिलीज कर दिया गया है। अगर आप किसान के हमदर्द हैं तो आपका वह नजरिया सामने आना चाहिए और इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी का एक स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वे सदन में आश्वासन दें कि प्रदेश के किसानों को उनके गन्ने की फसल का पैसा तुरन्त रिलीज कर दिया जायेगा।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ढुल साहब को बताना चाहूंगा कि प्रदेश की सभी कोआप्रेटिव चीनी मिलों ने किसानों की पेमेंट दिसम्बर, कुछ की जनवरी और असन्ध शुगर मिल ने मार्च महीने की भी पेमेंट कर दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह आश्वासन देता हूं कि शुगर मिलों को सरकार द्वारा जो भी लोन वगैरह देना है वह देकर एज अरली एज पोसिबल तुरन्त किसानों की पेमेंट कर देंगे। इसके बारे में निश्चित तिथि बताना तो कई बार अच्छा नहीं रहता। हम तुरन्त किसानों की अगली किश्त रिलीज कर देंगे। इसके अलावा जुलाई, अगस्त और सितम्बर तक हम किसानों का पूरा भुगतान कर देंगे और अगले कलैण्डर तक उनकी पेमेंट नहीं जाने देंगे।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण होगा।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप पांच मिनट के लिए बोलने का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, काफी जवाब आ चुके हैं । अब बजट पर चर्चा भी तो जरूरी है। अब श्री बलवन्त सिंह सढ़ौरा जी बोलेंगे।

श्री बलवन्त सिंह (सढ़ौरा) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह अपना पहला बजट सदन में प्रस्तुत किया है। पूर्व की सरकारों के क्षेत्रीय भेदभाव के कारण और भाई-भतीजावाद के कारण जो विकास हमारे हल्के का होना चाहिए था वह विकास पिछली सरकार के समय में नहीं हो पाया। पिछले कई सालों से हरियाणा के कुछ इलाके हरियाणा के मानचित्र से गायब हो गये थे। मौजूदा सरकार ने 'सबका साथ सबका विकास' के नारे का साथ लेते हुए आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। आज हम जो भी बात पिछली सरकार के बारे में कहते हैं तो कांग्रेस के माननीय सदस्य उस बात को यह कहकर टाल देते हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया था और आप अब क्या करेंगे ? पिछली सरकार ने अपने दस सालों का हिसाब तो आज तक दिया नहीं और वर्तमान सरकार का पांच महीने का हिसाब लेने के लिए आमादा हैं। मेरी उन माननीय सम्मानित सदस्यों से एक ही प्रार्थना है कि समय आने पर हिसाब भी दे दिया जायेगा और हरियाणा प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। इसमें भी कोई शंका की बात नहीं है कि वर्ष 2015-16 के बजट में खर्चों का अनुमान वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों की तुलना में तकरीबन 16.44 प्रतिशत् ज्यादा है। राजस्व प्राप्तियाँ भी इस बजट में ज्यादा हैं। इस बजट में राजस्व प्राप्तियाँ 52,312 करोड़ रूपये की हैं जबकि पिछले वर्ष राजस्व प्राप्तियाँ 45,419 करोड़ रूपये की थी जो इस वर्ष 15.18 प्रतिशत् ज्यादा हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह जो बजट सदन में पेश किया है यदि इसके एक-एक हैड पर दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि चाहे कृषि विभाग की मद हो, चाहे पशुपालन विभाग, मछली

[श्री बलवन्त सिंह]

विभाग, बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति कल्याण विभाग अथवा विकास एवं पंचायत विभाग की मद हो, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने हर मद पर 3 प्रतिशत् से लेकर 132 प्रतिशत् तक ज्यादा खर्च करने का प्रावधान किया है। इस बज़ट में कहीं भी ऐसी बात नहीं झलकती है कि यह एक निराशाजनक बज़ट है। सभी बातों को देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह एक संतुलित बज़ट है जिसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप घड़ी की तरफ भी देख रहे हैं और मेरी तरफ भी देख रहे हैं। यदि मैं एक-एक पहलू पर चर्चा करूंगा तो सदन का बेशकीमती समय बर्बाद हो जाएगा। मैं एक विशेष बात सदन के सम्मुख कहना चाहूंगा कि आपका विधान सभा क्षेत्र और मेरा विधान सभा क्षेत्र, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। चण्डीगढ़ से यमुना नगर जाने के लिए जो रास्ता है वह सढौरा, बिलासपुर व छछरौली से होकर जाता है जिसकी हालत बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में मेरे हल्के सढौरा की बड़ी अनदेखी हुई है। सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, वहां पर सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेरे हल्के की सभी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाये। इसके अलावा मेरे हल्के में पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर है। अभी मेवात के माननीय सदस्य भी अपने हल्के की पीने के पानी की समस्या को सदन में उठा रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि पीने के पानी का सारा सिस्टम पब्लिक हैल्थ ट्यूबवैल्ज़ पर आधारित है लेकिन बड़ी निराशा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार द्वारा नये ट्यूबवैल लगाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उस सरकार ने पिछले 3-4 वर्षों से मेरे हल्के में जो 32 ट्यूबवैल्ज़ खराब पड़े हैं, उनको भी ठीक नहीं करवाया है। यदि एक-एक ट्यूबवैल की मैं डिटेल बताऊंगा तो बहुत समय लग जायेगा। अभी तो सर्दी का मौसम है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आयेगा तो मेरे हल्के के निवासियों के समक्ष कितनी भारी दिक्कत आयेगी इसका आप भलीभांति अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि मेरे हल्के में पीने के पानी का जल्द से जल्द प्रबंध किया जाये। बिजली की गंभीर समस्या पर बोलते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में लाहरपुर एक गाँव है। यदि काला अम्ब से हम चलें तो लगभग 80-90 किलोमीटर दूरस्थ स्थान से वहां पर बिजली आती है। कुछ समय पहले भी इस बारे मे बात हुई थी तथा बिजली की इस समस्या के निदान के लिए एक प्रपोजल भी बनाई गई थी लेकिन पता नहीं किन कारणों से यह प्रपोजल सिरे नहीं चढ़ पाई। वहां पर साथ लगते हिमाचल प्रदेश राज्य में एक तरफ तो 24 घण्टे बिजली जगमगाती हुई दिखती है वहीं दूसरी ओर हमारे यहां बिजली तो आती है लेकिन एक घण्टे में ही फॉल्ट पड़ जाता है तथा इस प्रकार से लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर एक 33 के.वी.ए. का सब-स्टेशन लगवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सढौरा हल्के में बिलासपुर एक ऐसा कस्बा है जिसके सराऊंडिंग में 20 गाँव बिल्कुल देहात क्षेत्र में आते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर एक 50-बैड का अस्पताल बनाया जाये क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो जाये तो उसको यमुनानगर के किसी अस्पताल में पहुंचने के लिए काफी समय लग जायेगा। यमुनानगर बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा इस प्रकार से वह मरीज यमुनानगर पहुंचते-पहुंचते ही अपना दम तोड़ देगा। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि पिछले 10 सालों में पिछली सरकार ने जो मेरे हल्के की अनदेखी की है, उसकी तरफ यह सरकार अवश्य ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, पूरे शहर के बारे में तो मैं नहीं कहता लेकिन मुस्तफाबाद, बिलासपुर और सढौरा ये तीनों तकरीबन ऐसी टाउनशिप हैं जिनकी आबादी 14-14 या 15-15 हजार से ज्यादा है इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इन तीनों शहरों में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने की व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विनती करूंगा कि हरियाणा के हमारे हल्के के भाई बहन काला अम्ब यानि दूसरी स्टेट में रोजगार के लिए जाते हैं। कई हजार बच्चे वहां नौकरी के लिए और दिहाड़ी के लिए जाते हैं इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां कोई इंडस्ट्री स्थापित की जाए ताकि हमारे बच्चे दूसरी स्टेट में न जाकर अपनी ही स्टेट में रोजगार प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष ग्रोवर (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आशा छोड़ चुका था कि शायद आप मुझे सदन में बोलने के लिए समय देंगे। पूरे प्रदेश में यह चर्चा हो रही है कि रोहतक में विकास, रोहतक में विकास इसलिए मैं समझा कि मुझे न राज्यपाल के अभिभाषण पर और न ही बजट पर बोलने के लिए समय मिलेगा। इसलिए मैं विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं।1971 में चौधरी मुख्त्यार सिंह मलिक जन संघ पार्टी से दीपक के निशान से चुनाव लड़े थे और डा. मंगल सैन ने मुझे पर्चिया बांटने का काम दिया। डा. मंगलसैन ने 9 बार चुनाव लड़ा और 7 बार वे रोहतक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए। उनकी वजह से ही मैं यहां बैठा हूं। डा. मंगल सैन जी यहां बैठते थे इसलिए मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूं कि जिनकी वजह से मैं आज यहां सदन में बैठा हूं और मै उनका शुक्रगुजार हूं। अध्यक्ष महोदय, लोग रोहतक में विकास की बात करते हैं और पूरे हरियाणा के अंदर भी बात हो रही है और हमारी पार्टी के नेता भी कहते हैं कि रोहतक में विकास हुआ। जैसे हरियाणा को तीन भागों में बांटा गया है उसी प्रकार रोहतक को भी तीन भागों में बांटा गया है। सर छोटूराम चौंक से लेकर मेरा पुराना शहर जहां मेरा दिल बसता है और जहां व्यापारी रहते हैं शोरी मार्किट, भिवानी स्टैंड और किला रोड पर तीन-तीन घंटे तक जाम लगा रहता है। गांव से जब कोई महिला बाहर आती है तो वहां कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली रोड पर काम हुआ है इस बात को मैं भी मानता हूं। जहां भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का निवास स्थान है वहां से लेकर पूरी दिल्ली तक विभाग के अफसरों द्वारा अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में 4-4 या 5-5 बार सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप को किसानों के मसीहा कहते हैं और किसानों की रक्षा करने वाले कहते हैं जबकि इन्होंने खेड़ीसाध के किसानों की उपजाऊ धरती के ऊपर चौधरी रणबीर सिंह के नाम से आई.एम.टी. बनाने का काम किया और उस पर करोड़ों रूपया खर्च कर दिया। रोहतक में मातुराम के नाम का प्रयोग कम्युनिटी सैंटर, रोहतक यूनीवर्सिटी और पी.जी.आई. रोहतक में किया गया है। हरियाणा में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने से पहले मुझे पता नहीं था कि मातुराम कौन था। मैं समझता था कि मातुराम जलेबी वाला है लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मातुराम जी तो मेरे दादा जी हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं उनको आदरणीय दादाजी बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार से पहले मुझे पता नहीं था कि मातुराम कौन है लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आने के बाद मुझे पता चला कि वे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे दादा आदरणीय चौधरी मातु राम जी के नाम से रोहतक शहर में करोड़ों और अरबों रूपये खर्च कर दिये। मैं आपसे इतना निवेदन

[श्री मनीष ग्रोवर]

करना चाहता हूं कि जो मेरा रोहतक है यहां से डॉ. मंगल सैन जी 9 में से 7 बार इलैक्शन जीते। इस बारे में बी.बी.सी. से भी समाचार आते थे और पाकिस्तान से भी समाचार आते थे लेकिन आज मेरे रोहतक के सम्बन्ध में समाचार आते हैं भ्रष्टाचार के नाम से और सी.एल.यू. के नाम से। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के समय में रोहतक की पूरे देश और विश्व में ऐसी पहचान बन गई है। स्पीकर सर, मेरे रोहतक को तीन भागों में बांटा गया। रेलवे लाईनों के दूसरी ओर जहां पर पूरी रोहतक कांस्टीचुएंसी का 1.50 लाख वोटर रहता है वहां पर न तो कम्युनिटी सैंटर बनाया गया और न ही पेशैंट के लिए किसी दूसरी प्रकार की सुविधा का बंदोबस्त किया गया। अगर किसी मरीज़ को रात को कोई तकलीफ हो जाती है तो उसे रात के समय में ही पी.जी.आई., रोहतक लेकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से सर छोटू राम चौंक से लेकर किला रोड और शोरी मार्किट तक जो कि रोहतक के साथ-साथ मेरा भी दिल है वहां पर भी न तो कोई कम्युनिटी सैंटर है और न ही वहां कोई अन्य व्यवस्था की गई है। मेरे गांव से नौजवानों को नौकरी नहीं दी गई है जिससे वे रोहतक शहर में आटो चलाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्पीकर सर, इसी प्रकार से मैं यह बताना चाहूंगा कि रोहतक शहर में लगभग 6 हज़ार आटो रजिस्टर्ड हैं और ऐसे ही लगभग 6 हज़ार आटो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इस प्रकार से पूरे रोहतक शहर में लगभग 12 हज़ार ऑटो रिक्शा चल रहे हैं इनमें से ज्यादातर डीज़ल और यहां तक कि मिट्टी के तेल से भी चल रहे हैं । इनसे पूरे रोहतक शहर में ध्वनि और वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है और प्रदूषण की यह समस्या दिन प्रति दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो ट्रैफिक की व्यवस्था अस्त-व्यस्त है उसको सुव्यवस्थित किया जाये और जो आटो चल रहे हैं जो कि प्रदूषण का मुख्य कारण है इनसे तरह-तरह की भयानक बिमारियां फैल रही हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रोहतक शहर के साथ-साथ पूरे शहर में सी.एन.जी. से चलने वाले ऑटो रिक्शा के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रपोज़ल जानी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं एक समस्या और आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि रोहतक शहर के साथ-साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में यह समस्या है कि सीवर बंद हो जाते हैं और सीवरेज़ का पानी सड़कों पर आ जाता है। इसके लिए भी सरकार द्वारा कोई न कोई कारगर कदम उठाया जायें। इसी प्रकार से रोहतक शहर में डेयरियों के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि डेयरियों के लिए सही जगह की व्यवस्था करके इनको वहां पर जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाये। मैं एक बात का यहां पर और जिक्र करना चाहता हूं कि जब श्री अनिल विज जी ने यहां पर महात्मा गांधी जी और श्री अम्बेडकर जी की फोटो के नीचे से नेम प्लेटों को हटाने की बात कही तो उस समय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे कि मैं कांग्रेस में रहूंगा और ये पत्थर भी यहीं रहेंगे। उनकी इस बात पर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब से हरियाणा बना है पिछले 48-50 साल के अंदर जब-जब हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना है उन्होंने कांग्रेस से बाहर निकलकर अपने दल बनाये हैं इसके सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाला समय भी यह याद रखेगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कभी भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और ये सी.एल.यू. दल के नाम से अपनी नई पार्टी बनायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश मे इनकी नई पार्टी सी.एल.यू. पार्टी

होगी। यही कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का इतिहास रहा है। (शोर एवं व्यवधान) यह बात मैं आज भी कहना चाहता हूं कि मार्च की 21 तारीख को हरियाणा प्रदेश में श्रीमती सोनिया गांधी जी आ रही हैं वे चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कहने पर नहीं अपितु वे श्रीमती किरण चौधरी के कहने पर उनके एरिया में ही आ रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे रोहतक शहर के अंदर काफी कमियां हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे रोहतक के साथ-साथ पूरे हरियाणा में जो ट्रैफिक की अव्यवस्था के साथ-साथ जो दूसरी समस्यायें हैं उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाये और सही व सच्चे अर्थों में पूरे हरियाणा प्रदेश को विकास के पथ पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाये। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldeep Sharma (Ganur) : Speaker Sir, it is the prerogative of the Member to speak and we can not direct him as to what he should speak. But at the same time, you are presiding over this House as Hon'ble Speaker. The Hon'ble Speaker should take note whether a Member is making a directionless speech or whether the speech pertains to the Budget. We want that kind of ruling should come from the Hon'ble Speaker and the time of the House should not be wasted on personal agendas. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगण कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। अब श्री सुभाष सुधा जी बजट पर बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष सुधा (थानेसर) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, वित्त मंत्री जी सदन में नहीं है और बजट पर सामान्य चर्चा हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, सरकार के बहुत से मंत्री यहां पर बैठे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, मैं भी सरकार में मंत्री हूं और यहां पर बैठा हूं क्या इनको मैं दिखाई नहीं देता। मेरे साथ कविता जी और बिक्रम सिंह जी भी सदन में मौजूद हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma : Sir, in the Indian Parliament recently the day was fixed for discussion on Budget. Hon'ble Finance Minister Shri Arun Jaitely Ji was not present in the House. He had gone to England for unveiling of Gandhi Ji's statue. Mrs. Sonia Gandhi Ji took up the objection in the House that the general discussion on the Budget shall not take place until and unless the Finance Minister himself is not present in the House. The same thing is here which Dr. Kadian wants to raise. Of course, the Hon'ble Ministers are present but because the Finance Minister is to reply to the quarries raised by the Members, therefore, it is a proprietary and he should be present in the House. (Interruption) I am just pointing out that this Government probably does not take the discussion on Budget seriously and that is why the minister is absent. The minister should come to the House.

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, वित्त मंत्री जी यहीं हैं। वे सारा कुछ सुन रहे हैं और अभी हाऊस में भी आ जायेंगे ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, विपक्ष ने यह बात यहां पर उठाई है कि वित्त मंत्री महोदय यहां पर मौजूद नहीं हैं। स्पीकर सर, मैं इनको कलैक्टिव रिसपॉसीबिलिटी का सिद्धांत याद दिलाना चाहता हूं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी को यह बात याद दिलाना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों किसी मामले में एक आदेश जारी किये थे जिनको सुपरसीड कर दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस कलैक्टिव रिस्पांसीबिलिटी की ये अब बात कर रहे हैं उस समय वह कहां चली गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं यह बात कह रहा था कि मैं हाऊस में प्रेजैंट हूं और हमारे दूसरे आदरणीय मंत्री जी भी हाऊस में प्रेजैंट हैं। मैं विपक्ष के साथियों को यह बताना चाहूंगा कि जो इनके द्वारा बातें कही जा रही हैं हम उनको नोट कर रहे हैं। मैं इनको इनके समय की एक बात बताना चाहता हूं कि इनके समय में जो वित्त मंत्री थे वे तो भाषण पढ़कर घर पर जाकर सो जाया करते थे। यह बात जानने के लिए आप पिछले 10 साल का रिकार्ड निकलवाकर देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, हमने तो अभी एक दो दिन पहले अखबार में छपा फोटो देखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी सी.एम. हाऊस के लॉन में सो रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप यह बताओ कि क्या यह सैशन के दौरान की बात है? (शोर एवं व्यवधान) या फिर सैशन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री सो रहे थे।

डॉ० अभय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को यह बात बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय धरती पर सो रहे थे न कि किसी फाईव स्टार होटल में सो रहे थे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े अफसोस की बात है कि इस प्रकार के विषय को लेकर इस सदन में इस ढंग से चर्चा हो रही है।

Shri Kuldeep Sharma : Sir, your Minister pointed out it first. (Interruption)

श्री मनोहर लाल : माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर मेरा जिक्र आया है इसलिए मैं अपने विषय में बताना चाहता हूं कि मेरी जिस फोटो को दैनिक भास्कर में दिखाया जा रहा है, मैंने भी उस फोटो को देखा है। जो काम मैंने किया है मैं उस काम से भाग थोड़े ही रहा हूं। संयोग ऐसा हुआ कि जिस दिन बजट पेश किया गया क्योंकि मैं नया सदस्य हूं और मैं अपने से सम्बंधित प्रत्येक विषय को स्वीकार करता रहा हूं इसलिए अब भी मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि मुझे यह ज्ञान नहीं था कि सदन में बजट पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही वहीं पर स्थगित हो जायेगी। इस प्रकार से लगभग ढ़ाई घंटे का समय मेरे पास अतिरिक्त बच गया था। मुझे जो काम करने होते हैं मैंने उन रूटीन के कामों को किया। दोपहर बाद 02.00 से 03.00 बजे का समय मैंने जनता से मिलने के लिए निश्चित किया हुआ है। मैंने यह काम भी पूरा किया। दोपहर का भोजन करने के बाद 15-20 मिनट का विश्राम कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री और कोई

भी व्यक्ति करना चाहेगा और जहां तक मेरे विश्राम करने की बात है मुझे विश्राम करने के लिए किन्ही मखमली गद्दों की आवश्यकता नहीं थी मेरा जीवन जैसा मुख्यमंत्री बनने से पहले था वैसा ही मेरा जीवन आज भी है इसलिए मैंने एक चादर मैदान में बिछाई और लेटकर विश्राम कर लिया। इससे विश्राम भी हो गया और जो साथी कार्यकर्ता हैं जो काफी लम्बे समय से साथ हैं इससे उनको भी अच्छा लगा। किसी ने उस समय मोबाईल से मेरा फोटो खींच लिया और उसे वट्स-अप पर डाल दिया जिससे वह दुनिया भर में फैल गया। अगर इसमें भी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को आपत्ति है तो मैं इससे बड़ा हैरान हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं इससे बड़ा हैरान हुआ कि इस विषय को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। अगर मेरी इस सादगी की चर्चा इस सदन में और सारे देश व दुनिया में हो तो इससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Kuldip Sharma : Sir, he is Hon'ble Leader of the House. If he wanted to have some moment to take rest after the session time is over. absolutely, there is no objection but his own Minister, who is sitting on his back seat and he has the habit of intervening in matters which do not pertain to him and do not concern of him, he was mentioning that. At every time he has to go dig into the history for no reason that in our term our Finance Minister goes to his house and sleep. I simply pointed out that everybody has got a right to sleep and Chief Minister was also found sleeping and his photo became viral on Whatsapp and media. So, it is absolutely nothing but if such thing is mentioned for no reason that is not good. Why he mentioned the former Finance Minister ? (Interruption).

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया था। मैं तो जो वित्त मंत्री जी के बारे में बात की थी केवल उससे रिलेटिड बात कर रहा था। सर, इररैलिवेंट ये होते हैं, आउट ऑफ ट्रैक ये होते हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सत्ता जाने से जिस आदमी की खुद की नींद उड़ जाये वह दूसरे को चैन से सोते हुये कैसे देख सकता है?

Smt. Kiran Choudhry : Sir, he is not relevant to the issue what he has discussed.

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार हरियाणा में ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जो जन-कल्याणकारी है। इस बजट में प्रदेश के हर तबके का ख्याल रखा गया है व किसी एक विशेष क्षेत्र का ख्याल न रख कर पूरे प्रदेश का ख्याल रखा गया है। मैं इस सदन के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु व दानी पुरूष हैं। कुछ समय पहले पानीपत में पंचनंद ट्रस्ट द्वारा एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री जी विशेष अतिथि थे। ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी कुछ मांगें रखी थी। तब मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार भी एक ट्रस्ट है और एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में कभी भी आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं अपनी पुश्तैनी तीन एकड़ जमीन में से एक एकड़ जमीन पंचनंद ट्रस्ट को दान देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही सदन के माध्यम से सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि मौजूदा सरकार ने कुरूक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के पवित्र जल का

[श्री सुभाष सुधा]
पुनर्चक्रण किया है। सरकार ने कुरूक्षेत्र के आस-पास के लगते क्षेत्रों जैसे पेहवा, नरकातारी आदि स्थानों के तीर्थ स्थलों के विकास का भी निर्णय लिया है। इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्योतिसर भगवान श्रीकृष्ण की भूमि है जहाँ उन्होंने गीता का उपदेश दिया था उसके सरोवर के जल का भी पुनर्चक्रण किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बजट में कुरूक्षेत्र में राज्य संग्रहालय के निर्माण का निर्णय लिया है व वर्ष 2015-16 में इसके लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुरूक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए और यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसी सेलेब्रिटी को ब्रांड ऐम्बैसडर बनाया जाये। इसी के साथ-साथ जैसे जयपुर पिंक सिटी है उसी प्रकार कुरूक्षेत्र भी श्री कृष्ण भगवान जी की भूमि है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जयपुर में जैसे श्री कृष्ण भगवान की प्रतीमा का पीताम्बर कलर है वैसे ही जयपुर की तर्ज पर कुरूक्षेत्र में भी श्री कृष्ण भगवान की प्रतीमा का कलर पीताम्बर किया जाए। मैंने इसमें पूरे शहर का रैजोल्यूशन दिलवा दिया है इसके साथ ही मैं एजुकेशन पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बार बजट में एजुकेशन पर खर्च करने के लिए वर्ष 2014-15 के बजट की राशि से 12.91 प्रतिशत अधिक राशि दी गई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किया जाए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो कॉलेज है उसको डिपार्टमैंट का दर्जा दिया जाए क्योंकि पहले भी दो कॉलेज जो एक सोनीपत में और एक रोहतक में है इन दो कॉलेजों को डिपार्टमैंट का दर्जा दिया गया है इसलिए कुरूक्षेत्र के युनिवर्सिटी कॉलेज को भी डिपार्टमैंट का दर्जा दिया जाए। इसके साथ-साथ मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि कुरूक्षेत्र में एक महिला कॉलेज का निर्माण भी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि ज्योतिसर में एक संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए क्योंकि वह श्री कृष्ण भगवान जी की भूमि है। कुरूक्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां पर एक सरकारी कॉलेज का निर्माण किया जाए। इसके साथ-साथ मैं अनुरोध करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी में 1400 कर्मचारी ठेके पर लगे हुए हैं उनको अभी तक वेतन नहीं मिला। वह वेतन किन कारणों से नहीं मिला यह मैं बताना चाहता हूं कि उनके जो टैंडर किए गये हैं उन टैंडरो की कंडीशन ठेकेदार ने पूरी नहीं की। इस कारण वे 1400 कर्मचारी सड़कों पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उनको सैलरी दिलवाई जाए और उन ठेकेदारों के टैंडरों को भी चैक किया जाए कि किसका कहां पर फाल्ट है। उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र का जो सामान्य अस्पताल है वह 50 बैड का है और उसकी सैंक्शन 100 बैड की हुई है ? मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको 300 बैड का बनाया जाए क्योंकि वहां पर बहुत पेशेंट आते हैं। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि गांव के अन्दर जो हमारी माता-बहनें पशुओं का गोबर उठाती हैं उनके हाथों में स्किन प्रॉब्लम होती है तो मैं चाहूंगा कि ऐसे गांवों के अन्दर हैल्थ सैन्टर बनाया जाए और वहां पर स्किन स्पैशलिस्ट डॉक्टरों को भेजा जाए। क्योंकि गांवों के अन्दर यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि नगर परिषद में जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनका वेतन समय पर नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पहले तो नगर पालिकाओं को जो स्टाम्प ड्यूटी मिलती थी वह डी.सी. लेवल पर ही मिल जाती थी लेकिन

अब वह टोटल स्टाम्प ड्यूटी बंटकर ऑफिस में आती है और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है जिसकी प्रक्रिया में कम से कम दो महीने लग जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जैसे पहले डी.सी. ऑफिस से स्टाम्प ड्यूटी मिलती थी वैसे ही स्टाम्प ड्यूटी मिले। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि कुरूक्षेत्र में देश-विदेश से बहुत टूरिस्ट आते हैं तो मैं चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र में इन्टरनल बस सर्विस शुरू की जाएं मैंने कल भी अनुरोध किया था कि कुरूक्षेत्र में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इसलिए कुरूक्षेत्र के हर चौक पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएं जिससे कुरूक्षेत्र सिक्योरिटी प्रूफ शहर बनें अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रोहिता रेवड़ी (पानीपत शहर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट 2015-16 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने टैक्स फ्री बजट पेश करके हरियाणा की जनता को जो राहत देने का कार्य किया है मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं। मैं वित मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहती हूं कि उन्होंने 4 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला 800 मेगावाट का क्रिटीकल थर्मल प्लांट पानीपत में स्थापित करने का निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। पानीपत जो एक औद्योगिक नगरी है जहां पर पूर्व सरकार ने व्यापारियों पर जो कर लगाया है उससे वहां का व्यापार लुप्त होने के कगार पर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि व्यापारियों को फालतू कर से छुटकारा दिलवाया जाए ताकि वहां पर हैण्डलूम का व्यापार फिर से पूर्ण रूप से जीवित हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि पिछली सरकार ने पानीपत शहर के अंदर ड्रेन नम्बर-1 बनवाने का निर्णय लिया था और वह ड्रेन बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इस ड्रेन को एक नाली का रूप दे दिया है जोकि अधिकतर ओवर फ्लो रहती है जिससे यह पता नहीं चल पाता है कि सड़क कहाँ है और नाली कहाँ है जिसके कारण निरन्तर हादसे होते रहते है और जिसकी वजह से कई मौतें हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसे चण्डीगढ़ एवं करनाल की तर्ज पर कवर करवा दिया जाये ताकि पानीपत की जनता को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, पानीपत शहर में कोई भी कन्या महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण लड़कियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि पानीपत में एक नये कन्या महाविद्यालय का निर्माण किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पानीपत का बस अड्डा काफी पुराने समय से बना हुआ है। जिसकी इमारत जर्जर हालत में है। जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बसों की संख्या में इजाफा हुआ है इससे प्रतिदिन पानीपत में जाम की स्थिति बनी रहती है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत में बस अड्डा पुराना होने के कारण बारिश के मौसम में यह एक झील का रूप ले लेता है। मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि बसे अड्डे के लिए सैक्टर-13 और सैक्टर-17 में जगह अलॉट हो चुकी है। इसलिए वहाँ पर बस अड्डे को शिफ्ट किया जाये। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय........... (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविंदर सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने 1 घंटे 45 मिनट चर्चा की। इंडियन नैशनल लोकदल के माननीय सदस्यों ने 1 घंटे 37 मिनट चर्चा की और कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने1 घंटे 27 मिनट चर्चा की है। सत्ता पक्ष के जो-जो नये माननीय सदस्य हैं वे कृपा करके अपनी बात 5-5 मिनट में समाप्त करें। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया। अब जो नये मैम्बर हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाये। प्लीज सभी बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के भी कुछ नये सदस्य हैं उनको भी बजट पर 5-5 मिनट के लिए बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है उनको भी बोलने का मौका दिया जायेगा।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, आपने हाउस को जानकारी दी थी कि किस-किस पार्टी को चर्चा करने के लिए समय मिलेगा। तब आपने अपील भी की थी। अध्यक्ष महोदय, जो दोनों पार्टियों के दल के नेता हैं, उन्होंने समय के वितरण का ठीक प्रकार से न्याय नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आपने सभी पार्टियों को समान रूप से बोलने के लिए समय दिया है और उसी बात को बार-बार कहना कि हमें और समय दिया जाये ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टियाँ अपने दल में भी थोड़ा सा लोकतांत्रिक ढंग से समय का वितरण करेंगे तो सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चल पायेगी।

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल) : अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण भी आपने मुझे बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि सरकार ने हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन बजट दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट उस समय दिया जब हरियाणा प्रदेश हजारों करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़खल विधान सभा क्षेत्र से आती हूँ और इससे पहले कि मैं अपने हल्के की बात रखूँ, कोई भी माननीय सदस्य अपने दिल से यह बात न लगाये जो बात मैं कहने जा रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से यह प्रथा चली आ रही है। मैं मानती हूँ कि जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस जगह पर विकास हुआ है उसके लिए मैं बधाई देती हूँ और जिस जगह पर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है उसके लिए तो मुझे सदन में आवाज उठानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूँ। मैंने पहले विधान सभा सत्र में यह बात रखी थी कि बड़खल विधान क्षेत्र में कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वहाँ पर लॉ कॉलेज और एक महिला कॉलेज खोला जाये क्योंकि बड़खल विधान सभा क्षेत्र के आस-पास बहुत सारे गाँव आते हैं। वहाँ से हमारी बेटियाँ दूर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, बेटियों का प्रोपर बेस बने और वे अपने जीवन में स्वावलम्बी बन सकें। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया गया है जिससे हमारी बेटियों को बल मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर दो

महत्वपूर्ण अस्पताल आते हैं। एक बादशाह खान अस्पताल है जिसे बी.के. अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा ई.एस.आई. अस्पताल है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से जो बी.के. अस्पताल है, उसमें वेंटीलेटर पर लेटे हुए मरीज की हालत बद से बदतर हो जाती है। उसने 13.00 बजे जिंदगी तो क्या जीनी है वह तो मर भी नहीं सकता है। वहाँ पर न तो पूरे डॉक्टर्ज हैं और न ही ऐसी समुचित व्यवस्था है, जिसके तहत हम मरीजों का सही उपचार करवा सकें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है क्योंकि ये बातें पहले ही उनके संज्ञान में भी हैं कि हरियाणा के अन्दर ई.एस.आई. (हॉस्पिटल) मेडिकल कॉलेज इसके साथ दो और मेडिकल कॉलेज हैं, जो वर्ष 2012 में शुरू हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बातें दिल को छू जाती हैं कि एक चीज सामने होने के बावजूद हमारे वहां के नागरिकों और बच्चों को इन सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत ही उचित मुद्दा सदन में उठाया है। फरीदाबाद ई.एस.आई. कॉरपोरेशन ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया था, उनको ही इस हॉस्पिटल को चलाना और इस काम को करना था लेकिन अब वे इच्छानुसार कॉलेज और हॉस्पिटल को हमारी सरकार को ट्रांसफर करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने सहमति भी दे दी है और इसको टेकिंग ओवर का प्रोसैस भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही टेकिंग ओवर और हैंडिंग ओवर हो जायेगा, हम उस कॉलेज को जल्दी चलाने का काम करेंगे क्योंकि वह हरियाणा सरकार के हैल्थ डिपार्टमैंट का कॉलेज हो जायेगा।

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं माननीय मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ फरीदाबाद हमेशा से बिजली के असंतुलित वितरण का शिकार रहा है जिसका स्वरूप हम ऐसे देख सकते हैं कि फरीदाबाद से बहुत सारी इन्डस्ट्रीज पलायन कर चुकी हैं। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन लाखों लोगों की भावना को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का काम करती हूँ। फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता रहा है, इसलिए शायद हरियाणा का बहुत बड़ा विकास का हिस्सा फरीदाबाद से जुड़कर आता रहा है। आज कोई इन्डस्ट्री वगैरह नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा खराब हालात हैं, इसलिए आज लोग फरीदाबाद से कहीं दूसरी जगह नौकरी करने के लिये विवश हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से नम्र निवेदन है कि फरीदाबाद के अन्दर एक मदर यूनिट के साथ-साथ छोटी-2 इन्डस्ट्रीज के लिये भी एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाये जिससे वहां दोबारा से एक बहुत बड़ी क्रांति लाकर मौजूदा इन्डस्ट्रीज को फायदा पहुँचे और लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। अध्यक्ष महोदय, बोलते-बोलते मेरे मन में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही गई दो लाइनें याद आ गई हैं। शायद मैं सोचती हूँ कि उसी भावना को लेकर हम आगे चलेंगे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि "छोटे मन से कोई बड़ा हो नहीं सकता, टूटे मन से कोई खड़ा हो नहीं सकता" दूसरों को सहारा देने के लिये जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी अपेक्षाएं करके आगे लाने का काम किया है, इसलिए हमारा कर्त्तव्य भी है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। इसके साथ-साथ हमारा बहुत बड़ा इश्यू यह है कि हमारा युवक वहां पर बेरोजगार है। अगर हम पीछे के ऐसे तथ्य सदन के पटल पर लाकर रख देंगे तो ये तथ्य साबित कर देंगे कि फरीदाबाद को सरकारी नौकरियों में कोई हिस्सा नहीं मिला है। इसका क्या कारण रहा ? इन कारणों के ऊपर मैं नहीं जाना चाहती पर जब हमारे बेरोजगार युवाओं को सड़कों पर घूमते हुए देखते हैं, तो यह

[श्रीमती सीमा त्रिखा]

देखकर आत्मा दुखी होती है। अध्यक्ष महोदय, एक बात का दुख मुझे पहले भी था और जिस दिन मैंने विधान सभा में शपथ ली थी उस दिन भी हुआ कि बड़खल विधान सभा क्षेत्र का नाम बड़खल झील हुआ करता था, इसमें वहां की जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं जिसका मैं बार-बार जिक्र भी करती हूँ और बार-बार यह निवेदन करती हूँ कि हम कम से कम एक मिसाल कायम करें। माना कि पीछे कोई ना कोई चूक रही होगी या कोई अनदेखी रही होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे पिछली सरकार के कामों को गिनाने में कोई संकोच नहीं क्योंकि न हमारा रेत छोड़ा, न पहाड़ों के पत्थर छोड़े और न ही जनता के पीने का पानी छोड़ा उसे भी व्यापार के लिये इस्तेमाल किया गया। बहुत सारी चीजें सीधी जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि बड़खल झील को भरने के लिए एक विशेष टीम बनाकर विशेष व्यवस्था की जाए। इसको टूरिज्म स्पॉट के रूप मे विकसित किया जा सकता है जिससे फरीदाबाद शहर को बहुत बड़ा राजस्व क्लैक्ट होगा। बड़खल और सूरजकुण्ड ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टियों के बड़े-बड़े सेमिनार्स और आयोजन हो चुके हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि उसी से जुड़ा हुआ एक इलाका है लकड़पुर जो दिल्ली से सटा हुआ है। वहां पर आज तक सीवरेज पाईप नहीं बिछाई गई हैं। आज जब मैं यहां इस विषय पर बोल रही हूँ अब भी वहां के मकानों के ग्राऊंड फ्लोर एक-एक, डेढ़-डेढ़ फुट पानी में डूबे हुए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि उस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे उनकी अपेक्षाएं पूरी हो सकें और उसके साथ-साथ मैं पूरे बजट का समर्थन करती हूं और मैं अंत में दो लाईनें कहना चाहती हूं-

माना कि फसल महंगी बिकी किसान की,
पर बेटी फिर भी न ब्याही जा सकी किसान की ।
चंद खुदगर्ज लोगों ने कुर्सी की खातिर,
सूरत बदल दी हिंदुस्तान की ।

श्री नायब सैनी (नारायणगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस बजट में हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग की बात कही गई है। इसमें 'सबका साथ सबका विकास' समान विकास, समान रोजगार का विचार स्पष्ट झलक रहा है। सरकार द्वारा 'मेक इन इण्डिया' की तर्ज पर 'मेक इन हरियाणा' कार्यक्रम चलाया गया है। इससे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए रोजगार के साधन मिलेंगे और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदेश में समान रूप से विकास होगा और हरियाणा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हरियाणा प्रदेश के लिए विकासोन्मुखी साबित होगा। इस बजट सत्र से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया था जिसमें डिटेल में बताया था कि किस तरह हरियाणा प्रदेश भारी कर्ज के मकड़जाल में उलझा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में बहुत-सी समस्याएं हैं । पिछली सरकार के शासनकाल में मेरे क्षेत्र नारायणगढ़ की बहुत अनदेखी हुई थी। हमें घोषणाओं के सिवाय कुछ नहीं मिला। आदरणीय अध्यक्ष जी, नारायणगढ़ के अंदर एक कन्या महाविद्यालय बनाने की घोषणा हुई थी । उसके लिए वहां पर पत्थर भी लगाया गया था। वह कन्या महाविद्यालय तो बना नहीं कुछ दिन के बाद उस पत्थर का भी नही पता चला कि वह किस

साइड में चला गया है। हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया है। सरकार कन्याओं के प्रति बहुत गम्भीर है कि प्रदेश में उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या योजनाएं चलाई जाएं। अतः मेरा माननीय अध्यक्ष के माध्यम से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अन्दर पानी बहुत डीप में चला गया है। वहां पर 4 सौ से 5 सौ फुट गहराई तक पानी चला गया है और आने वाले 2-4 साल में वहां पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः नारायणगढ़ को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वहां पर एक नहर बनवाई जाए। नहर बनने से किसानों को काफी लाभ होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे नारायणगढ़ के अंदर एक बहुत पुराना सिविल अस्पताल बना हुआ है जिसको मिनी पी.जी.आई. कहा जाता है। पिछली सरकार के समय में मुख्यमंत्री जी ने वहां पर 24 घंटे इमरजैंसी की सुविधा देने की बात कही थी परन्तु आज तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे हल्के नारायणगढ़ में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एक्सीडैंट हुआ था जिसमें एक बस पलट गई थी और उस एक्सीडैंट के दौरान काफी बच्चे जख्मी हो गये थे जिनमें चार बच्चे मारे भी गये थे परन्तु जब वे बच्चे नारायणगढ़ के सरकारी अस्पताल में आये तो उस अस्पताल की स्थिति देखने लायक थी। अगर किसी बच्चे को एक भी खरौंच आई थी उस एक चोट के कारण भी उनको पी.जी.आई. चण्डीगढ़ के लिए रैफर किया गया। उन बच्चों को नारायणगढ़ के अस्पताल में नहीं रखा गया। नारायणगढ़ का अस्पताल लगभग 200 गाँवों को कवर करता है और उसके साथ ही नारायणगढ़ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ सटा हुआ है इसलिए हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी काफी पेशैंट नारायणगढ़ के अस्पताल में आते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि नारायणगढ़ अस्पताल का नवीनीकरण किया जाए और साथ में मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि उस अस्पताल में एक ट्रामा सैंटर भी चलाया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। मेरे हल्के नारायणगढ़ में पिछली सरकार के समय में मनरेगा स्कीम के तहत एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया था और उस डैम को देखने के लिए केन्द्र से काफी सांसदों का एक शिष्ट मण्डल आया था। उस डैम में बरसात के पानी का कटाव होने के कारण जहां किसानों को उसका लाभ होना था उसकी बजाए वह डैम टूट गया और पानी किसानों के खेतों में चला गया जिसके कारण किसानों को बहुत नुक्सान हुआ। मनरेगा स्कीम के तहत उस डैम पर करोड़ों रुपये सरकार के खर्च हुए थे। मैं इस बारे में सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले की सरकार द्वारा जाँच करवाई जाए जिस प्रकार से आदरणीय विज साहब ने मनरेगा का एक घोटाला अम्बाला के बारे में बताया था और उसकी जाँच करवाने के लिए सरकार से कहा था। पिछली सरकार के समय में मनरेगा का लाखों रूपया पता नहीं किन लोगों की जेब में गया है इसलिए इस मामले की जाँच करवाई जाए। पिछली सरकार के समय में तत्कालीन मंत्री जो आजकल कांग्रेस पार्टी की नेता हैं उन्होंने मेरे हल्के के गाँव खतौली में मारकण्डा नदी पर एक चैक डैम बनाने का उद्घाटन किया था। चैक डैम तो इसलिए बनाया गया था कि उस पानी से किसानों को लाभ मिलेगा। (विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने अम्बाला में मनरेगा के घोटाले का जिक्र किया है मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वह एक बहुत बड़ा घोटाला था और उसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी और हमारी लड़ाई लड़ने के बाद उस मामले की विजिलैंस की जाँच तत्कालीन सरकार द्वारा करवाई गई लेकिन विजिलैंस की जाँच की रिपोर्ट ढ़ाई साल से तीन

[श्री अनिल विज]

साल तक पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के दफ्तर में पड़ी रही। जैसे ही हमारी सरकार आई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि zero tolerance for corruption. माननीय मुख्यमंत्री जी ने वह फाईल मंगा कर उस मामले में दोषियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी है। मैं माननीय सदस्य श्री सैनी साहब ने जो कन्सर्न दिखाया है मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में जो भी कसूरवार पाये जायेंगे उन दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गाँव दधौली में मारकण्डा नदी के अन्दर एक चैक डैम बनाया गया था। कहां तो उस का पानी किसानों के खेतों में जाना था लेकिन वह डैम रेत से अंट गया और किसानों को इससे बहुत भारी नुक्सान हुआ। उनको इस डैम से पानी तो क्या मिलना था उल्टे मारकण्डा नदी में जब पानी रूक गया और पानी ने डाईवर्ट होकर किसानों की जमीन को काटना शुरू कर दिया जिसके कारण किसानों का बड़ा भारी नुक्सान हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इस चैक डैम को बनाने में सरकार का कितना पैसा लगना था और क्या वह पैसा उस काम के लिए लगा या नहीं, इस मामले की पूरी जाँच होनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे हल्के में एक रहवाली गाँव पड़ता है। हमारे आदरणीय सभासद श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी सदन में बैठे हैं। बरवाला से लेकर हण्डेसरा तक जो सड़क आती है उस सड़क की हालत बहुत खराब है। उसके अंदर 2 किलोमीटर का एरिया एम.ई.एस. का भी है। इस सड़क पर मोटरसाईकिल तक नहीं चल सकती है तो गाड़ी चलने की तो दूर की बात है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस सड़क की रिपेयर बहुत जल्द करवाई जाये। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार से माँग है कि नारायणगढ़ में इसी सैशन से महाविद्यालय में एम.ए. व एम.कॉम. की क्लासिज़ शुरू की जायें । इस बारे में मुझे कॉलेज के छात्र मिले थे तथा उन्होंने मुझे चालू सदन में उनकी यह बात उठाने के लिए प्रार्थना की थी। इसके साथ ही साथ मेरी यह भी माँग है कि नारायणगढ़ में एक होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाये ताकि मेरे हल्के नारायणगढ़ ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा प्रदेश को इस यूनिवर्सिटी का लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नारायणगढ़ में एक बस पलट गई थी जिस वजह से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी तथा कई बच्चे जख्मी हुए थे। उन बच्चों के परिवार वाले अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। मीडिया भी लगातार इस घटना को उठाता रहता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन बच्चों की मौत हुई है तथा जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके परिवारों को हरियाणा सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को बोलना है। कृपया आप समय भी देख लीजिए कि एक माननीय सदस्य कितने समय के लिए बोल रहा है। आज बजट पर चर्चा 12.23 बजे शुरू हुई थी तथा अब सांय 1.06 बजे तक काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं । सबसे ज्यादा समय आपको दिया गया है। आपने यदि बोलने के लिए ज्यादा समय खुद ले लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं।

(शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाना है। आप भी अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों को इसी अनुपात में 5-5 मिनट का समय बाँटकर दे सकती थी ताकि वे भी बोल सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा (पानीपत ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने समय की माँग को देखते हुए इस सदन में यह बज़ट पेश किया है। (विघ्न) माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बज़ट प्रस्तावों के विवरण प्रस्तुत करने से पहले सदन में कहा था कि कुछ चुनौतियों को वे उजागर करना चाहते हैं तथा हरियाणा प्रदेश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है उनका उन्होंने इस बज़ट में जिक्र भी किया था। उन्होंने ठीक कहा था कि हरियाणा में कृषि की उत्पादकता स्थिर हो गई है तथा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान काफी कम हो गया है जिसकी वजह से हरियाणा के किसान के सिर पर कर्जा भी बढ़ गया है तथा उसकी आमदनी का हिस्सा भी घट गया है। जब उनकी आमदनी का हिस्सा घटा तभी स्वामीनाथन आयोग चर्चा में आया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की चर्चा इस सदन में भी हुई थी। मैं पूर्व सरकार के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को छुआ तक भी नहीं लेकिन आज यहां इस सदन में ये खड़े होकर किसानों के हित के लिए घड़ियाली आँसू बहा रहे हैं। अब इन साथियों को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट स्टैप बाई स्टैप लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश कर दी है। 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' स्कीम के तहत हरियाणा के सभी किसानों के खेतों को पानी मिले, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो योजना लागू की है इस योजना से हरियाणा के सभी किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त मैं एक गंभीर समस्या की तरफ इस महान का सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर के कारण किसानों के लिए संकट और अधिक गहराता जा रहा है। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बज़ट भाषण में यह कहा है कि भू-जल के दोहन के कारण आज प्रदेश में यह संकट पैदा हो रहा है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि हम 1 करोड़ एकड़ फुट पानी जमीन से निकाल रहे हैं। और 60 लाख एकड़ फीट पानी रिचार्ज होता है। 40 लाख एकड़ फीट का गैप आया है जिसके कारण हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। पूर्ववर्ती सरकारों ने वर्षा के पानी को रिचार्ज करके उसके संरक्षण के सिस्टम को ठीक किया होता तो आज यह इतना बड़ा गैप न रहता। अध्यक्ष महोदय, इस काम को करने के लिए इनके पास फुर्सत ही नहीं थी कि ये सारा काम कर सकते। हमारे कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या की ओर चिंता व्यक्त की है । जिस खुली खेती में पानी ज्यादा लगता है उसका उपाय करने के लिए टपका सिंचाई के माध्यम से और फव्वारा सिंचाई के माध्यम से पर ड्राप और मोर क्रॉप आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है जिसके लिए मैं कृषि मंत्री महोदय का और कृषि विभाग का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसानों की मूलभूत समस्या, मार्किटिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। किसान फसल पैदा तो कर लेता है लेकिन उसको बेचने के लिए मंडियां नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं पूर्व की सरकारों की केवल आलोचना ही करूं। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैंने उसमें एक चीज पाई कि ऐसे किसान समूह हैं जो मार्किट में अपना ब्रांड स्वयं बेच सकें और उस पर पूर्व की सरकारों ने कुछ काम भी किए हैं।11 जिलों में ये

[श्री महीपाल ढांडा]

काम शुरू हो पाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के किसान समूह खड़े किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ किसान की राजनीति करता आया हूं इसलिए मैं किसानों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनको हरियाणा में अपने भरोसे से यह बाजार खड़ा करना चाहिए। कृषि मंत्री जी ने इस ओर पहल भी की है। अभी गुड़गांव में एग्री लीडरशिप समिट करके इस चीज की पहल की गई है और उसमें डारेक्ट मार्किटिंग के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। किसान पैवेलियन वहां लगाया गया और उसमें हजारों किसानों को इसका लाभ मिला। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि 11 किसानों ने अपने ब्रांड वहां रजिस्टर्ड कराए हुए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे यहां पर पशु ब्रांड भी बना हुआ है। उस गौलोक की चर्चा किए बगैर मैं नहीं रुक सकता जिसके विविधिकरण की चर्चा हमारे वित्त मंत्री जी भी कर रहे थे कि विविधिकरण की तरफ आज कृषि विभाग बढ़ रहा है। उस सम्मेलन में हम लोगों से मिले तो हमें वहां फूल की खेती करने वाला एक किसान मिला। मैंने उससे पूछा कि आपका टर्न ओवर कितना है तो मुझे जानकर खुशी हुई जब उसने कहा कि 3 एकड़ जमीन पर उसका एक करोड़ 70 लाख रुपये का टर्न ओवर है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बात जचती तो नहीं है लेकिन मुझे बहुत अद्‌भुत लगी इसलिए मैंने इसका जिक्र यहां किया है। पिछली सरकारों का किसान की बजाय जमीनों के साथ ज्यादा जुड़ाव रहा है। मैंने आदरणीय कृषि मंत्री माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ गुड़गांव से झज्जर जिले की साइकिल यात्रा की तो वहां बहुत से किसान हम लोगों से मिले। उन्होंने हमें कहा कि हमारे यहां की हजारों एकड़ जमीन एक पूंजीपति से खरीदवाकर उस पर एक लैंड बैंक बनवा दिया गया, यह सुनकर हमें बड़ा अद्‌भुत लगा। हमने पूछा कि और क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि जो इस पर स्टॉम्प डयूटी थी वह भी माफ कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उसका हिसाब लगाकर प्रदेश की जनता को बताया जाए कि यह स्टाम्प ड्यूटी जो पूरी माफ की गई है वह कैसे माफ की गई। यह स्टाम्प ड्यूटी की राशि केवल सेठ के पास ही रही या फिर आधी-आधी बांट ली गई। मैं यह बात इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि इसका श्वेत पत्र में कहीं जिक्र नहीं किया गया। पिछली सरकार ने एक गजब का काम किया इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के साथी तो कम से कम किसान के नाम पर न बोलें। वह क्या गजब का काम किया था, वहां के एक किसान ने मुझे कहा कि आप हमारे इलाके को देख रहे हैं। यहां पर जो झाड़-बोझड़े खड़े हैं क्या आप इनको देख रहे हैं? मैंने कहा हां मैं देख रहा हूं। वहां आस पास गांव हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसको इन्होंने अर्बन इलाका घोषित कर दिया है ताकि वहां के लैंड बैंक को बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मै एक निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथियों ने तो किसानों की सोची न सोची लेकिन हम लोग किसानों के बारे में जरूर सोचें। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां की जो पंचायतें हैं उनसे पूछें कि आप लोग अर्बन एरिया में रहना चाहते हैं या रूरल में रहना चाहते हैं। वहां के लोगों ने मांग भी की हुई है कि उस एरिया को अर्बन एरिया से निकालकर रूरल एरिया घोषित कर दिया जाये तथा जो सरप्लस जमीन है वह वापस की जाये या सरकार अपने पास रख ले। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है और दूसरे सदस्यों को भी आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया। सभी ने बड़ी-बड़ी समस्याएं आपके माध्यम से सदन में रखी हैं। आदरणीय रघुबीर सिंह कादियान जी जो कि हमारे बड़े सम्माननीय हैं। पिछली सरकार में भी विधायक रहे हैं। इन्होंने भी अपने हल्के की समस्याओं की लम्बी चौड़ी लिस्ट पढ़

डाली। अध्यक्ष महोदय, आपने कादियान साहब को कहा कि आप अपनी लिस्ट लिखित में दे दें वह रिकार्ड में डाल दी जायेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक भी सम्मानित सदस्य ऐसा नहीं है जिसने यह कहा हो कि मेरे क्षेत्र में सभी समस्याओं का हल हो गया है। जब किसी भी हल्के में समस्याओं का हल नहीं हुआ है तो किस प्रकार से हरियाणा नम्बर-1 बन गया तथा विकास के क्षेत्र में आगे कैसे चला गया ? सदन में जो भी माननीय सदस्य खड़े होते हैं वे उनके यहां सड़कें, नालियां, हास्पिटल्ज, स्कूल अपग्रेड, टीचर्स की कमी, डाक्टर्ज की कमी और किसानों आदि के बारे में बोलते हैं। जब प्रदेश में इस तरह की व्यथाएं हैं तो वह कलाकार कौन था जिसने यह कलाकारी सिखाई कि हरियाणा नम्बर-1 बताना शुरू कर दिया जाये । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमारे नये-नये साथी भाई महिपाल जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं । इन्होंने कहा कि हरियाणा नम्बर-1 कैसे बन गया जबकि रोहतक, झज्जर, सोनीपत के विधायक भी कह रहे हैं कि उनके यहां काम नहीं हुआ । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सही है और इसमें मुश्किल यह है कि कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं कि उनके यहां काम नहीं हुआ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि पिछली सरकार ने हरियाणा नम्बर-1 की एडवर्टाईजमैंट का प्रचार करने के लिए एक साल में 131 करोड़ रूपये का खर्चा किया। आर.टी.आई. के तहत यह जानकारी ली गई है। ये लोग तो केवल हरियाणा नम्बर-1 की मार्केटिंग कर रहे थे, ब्रांडिंग कर रहे थे। प्रदेश की जनता का कहीं कोई काम नहीं हुआ। यही वजह है कि आज सत्तापक्ष और विपक्ष के साथी भी कह रहे हैं कि उनके यहां कोई काम नहीं हुए। इन्होंने तो हरियाणा नम्बर-1 का केवल प्रचार ही किया। जब भी कभी हम टी.वी. खोलते थे तो यही एडवरटाईजमैंट आती थी कि हरियाणा नम्बर-1, हरियाणा नम्बर-1 और बाहर निकलकर देखते थे तो गलियां और सड़कें वैसे की वैसे ही मिलती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले दस सालों के दौरान हिन्दुस्तान को बर्बाद किया है, हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया है और आज सदन में आपने मुझे बोलने के लिए दस मिनट का समय दिया है उसको भी कांग्रेस के साथी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महिपाल जी, प्लीज, आप दो मिनट में वाईंड अप करें।

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की बातें कर रहा हूं। मैं पानीपत ग्रामीण से चुनकर आया हूं। अब मैंने वहां लोगों से पूछा कि क्या पिछली सरकार के समय में कोई मंत्री आपके यहां आया, कभी किसी ने ईंट या पत्थर लगाया है तो मुझे जवाब मिला नहीं लगाया गया। अध्यक्ष महोदय, चाहे तो मेरे हल्के का पांच साल का रिपोर्ट कार्ड निकलवाकर देख लिया जाये अगर आप यह रिकार्ड निकलवाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे हल्के में पिछले पांच साल के दौरान पिछली सरकार द्वारा विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगवाई गई। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा नम्बर 1 कहां से हो गया? (विघ्न) मान्यवर, इसके अलावा मेरे हल्के के साथ एक और बहुत ज्यादा बड़ी ज्यादती हुई है। (विघ्न) सर, मैं पानीपत ग्रामीण हल्के की बात कर रहा हूं कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। सरकार इस बात की इंक्वायरी करवा ले तो दूध का दूध और पानी

[श्री महीपाल ढांडा]

का पानी अभी हो जायेगा। (विघ्न) सर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे हल्के में जो कालोनियां हैं वे सारी की सारी अनअप्रूव्ड हैं क्योंकि ये कालोनिया अनअप्रूव्ड हैं इसलिए वहां पर लोगों को पीने का पानी देने के लिए ट्यूबवैल नहीं लग सकता। वहां पर कोई भी गली इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि वे कालोनियां अनअप्रूव्ड हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और सरकार को एक बात यह बताना चाहता हूं कि समालखा के अंदर ऐसी 14-15 कालोनियां हैं जो कालोनियां बसी भी नहीं थी उन कालोनियों को तो पिछली सरकार द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया और जो मेरे हल्के की कालोनियां 90 प्रतिशत बसी हुई हैं उनको अनअप्रूव्ड कर दिया। मेरे हल्के की इन कालोनियों के अनअप्रूव्ड होने के कारण वहां के लोगों को पीने का पानी देने में दिक्कत हो रही है। वहां के सभी निवासी मेरे निवास स्थान पर आकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे लिए पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाये। इसी प्रकार से उनको आने-जाने के लिए कम से कम रास्ता तो दिया जाये। मैं लम्बी-चौड़ी और पक्की गली की बात नहीं कर रहा हूं कि आप वहां के रास्तों को लम्बा-चौड़ा और पक्का बनायें लेकिन मैं यह चाहता हूं कि उनको पैदल चलने के लिए रास्ता तो उपलब्ध करवाया ही जाना चाहिए। पिछली सरकार तो यह काम नहीं कर पाई। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी यह काम अवश्य करवायेगी। पिछली सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पर पत्थर लगाये हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इनके लगाये हुए पत्थर हमें तो नहीं मिले फिर वे पत्थर कहां पर चले गये । अभी यहां पर सामने बैठे हुए एक माननीय सदस्य यह बता रहे थे कि पहले उनके यहां पर कोयल बोलती थी और अब उनके यहां पर कौवे बोलते हैं । यही बात मैं कहना चाहता हूं कि यही पोजीशन पिछली सरकार की कारगुजारियों के कारण मेरे हल्के में पैदा हो गई है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार की अनदेखी के कारण जो मेरे हल्के में समस्याएं पैदा हो गई हैं उनका जल्दी से जल्दी समाधान करवाया जाये। मेरा एक निवेदन यह है कि मेरे हल्के में जो अनअप्रूव्ड कालोनियां हैं कि मेरे हल्के की इन सभी कालोनियों को जल्दी से जल्दी अप्रूव्ड घोषित किया जाये ताकि उनको पीने के लिए पानी और चलने के लिए रास्ता उपलब्ध होने के साथ-साथ इस प्रकार की दूसरी समस्याओं से छुटकारा मिले। इसके अलावा मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के की इन कालोनियों में एक से दो पी.एच.सीज़. का भी निर्माण करवाया जाये ताकि इन कालोनियों में जो ज्यादातर मज़दूर तबका रहता है उनको स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके। स्पीकर सर, मेरा एक बहुत बड़ा काम है। वह यह है कि पानीपत में जितने भी हुडा के सैक्टर हैं उनमें से सिर्फ 11 और 12 दो सैक्टरों को छोड़कर चाहे वे इंडस्ट्रियल एरिया के सैक्टर हों, रिहायशी एरिया के सैक्टर हों या फिर दूसरे सैक्टर हों वहां के निवासियों की यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि पिछली सरकार के समय में वहां पर भ्रष्टाचार की दुकानें सजाई हुई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे सरकार द्वारा ई-रजिस्ट्रेशन के माध्यम से तहसीलों में से भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया है उसी प्रकार से हुडा डिपार्टमैंट की भी ई-कनैक्टिविटी हो जाये तो बहुत अच्छा हो जायेगा। वहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर ट्रांसफर और कम्पलीशन के हज़ारों-हज़ारों केस पैंडिंग पड़े हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर सरकार इसकी भी ई-कनैक्टिविटी कर देगी तो इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होने के साथ-साथ भ्रष्टाचार का खात्मा भी स्वतः ही हो जायेगा। मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है। (विघ्न) इसके

साथ ही मेरा एक निवेदन यह भी है कि मेरे हल्के में सैक्टर 29 में शहर की डाई यूनिटों को पिछली सरकार द्वारा शिफ्ट किया गया था जब इन डाई यूनिटों को वहां पर शिफ्ट किया गया था उस समय इनको वहां पर सभी प्रकार की सुविधायें मुहैया करवाने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था। उनमें से एक वायदा यह भी किया गया था कि सरकार उनको भू-जल के साथ न जोड़कर इरीगेशन का पानी देंगे। अब वह पानी जहां पर इकट्ठा होना था वहां तक तो आ गया लेकिन जब वहां से आगे इस पानी को चलाने के लिए इण्डस्ट्रिअलिस्ट ने सरकार से आग्रह किया तो फिर उस ट्यूबवैल को चलाया गया जब वह ट्यूबवैल चलाया गया तो उसके चलते ही आगे की पाइप फट गई। हमने पूछा कि यह पाइप क्यों फट गई तो हमें बताया गया कि उससे आगे के पाइप ही गायब हैं इसलिए आगे पानी ही नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसकी भी जांच करवाई जाये कि यह जो इतना बड़ा गोलमाल हुआ यह किस प्रकार से हुआ। माननीय स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बलकौर सिंह कालांवाली (कालांवाली) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कल सरकार का एक बहुत बढ़िया नारा हाउस में आया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उस पर चर्चा भी हुई लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उस पर कल बहुत चर्चा हो चुकी है लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ और कल एक माननीय साथी ने यह सुझाव भी दिया था कि जब भी किसी घर में बेटी का जन्म हो तो वहाँ पर सरकार का एक अधिकारी बधाई देने के लिए उनके घर जाये तथा सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब 22 जनवरी, 2015 को पानीपत में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था तो आपकी बेटी हमारी बेटी नाम से एक योजना शुरू की थी जिसके तहत अनुसूचित जाति और बी.पी.एल. कार्ड धारकों के घर पहली बेटी के जन्म के समय सरकार की तरफ से 21 हजार रूपये उसके खाते में डाल दिये जाते हैं तथा यह योजना 22 जनवरी, 2015 से ही लागू हो चुकी है । (विघ्न)

श्री बलकौर सिंह कालांवाली : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ । दूसरी बात यह है कि लड़कियों की शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। लड़कियाँ आज के दिन स्कूल और कॉलेजों में आते-जाते समय सुरक्षित नहीं हैं। हर एक कॉलेज में एक पुलिस चौकी बनाई जाये जहाँ पर महिला पुलिस कर्मी तैनात की जाये ताकि लड़कियों को सुरक्षा मिल सके। लड़कियों के आने-जाने के लिए महिला पुलिस की पी.सी.आर. उपलब्ध करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हलके की कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे हलके में मेरे गांव में ही एक लड़कियों का स्कूल है जिसका बहुत बुरा हाल है। लड़कियों के बैठने के लिए कोई टाट या डैस्क वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। जब भी दोपहर का खाना बनता है तो दीवार न होने के कारण खाने की खुशबू से कुत्ते स्कूल में आ जाते हैं और एक तरफ तो लड़कियाँ खाना खा रही होती है और दूसरे तरफ से वे आवारा कुत्ते भी छीनने को तैयार रहते हैं। सरकार को इस समस्या का समाधान अवश्य करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का पिछली सरकार की

[श्री बलकौर सिंह कालांवाली]

अनदेखी और बेरूखी का शिकार रहा है। चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो हर फील्ड में मेरे हल्के की अनदेखी की गई है। मेरे हल्का में लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं है जबकि अकेले कालांवाली की 55 हजार की आबादी है। इसके अलावा हल्का में जो 82-85 गांव पड़ते हैं उनमें भी कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे हलका के किसी भी गांव में लड़कियों के लिए एक कॉलेज अवश्य बनवाया जाये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ मेरा हल्का पंजाब के नजदीक लगता है। मेरे हल्के में बसों की सुविधा बहुत कम है। वहां से न ही तो दिल्ली की तरफ और न ही चण्डीगढ़ की तरफ कोई सीधी बस सेवा है। इस बारे में मैंने प्रश्न भी लगाया था लेकिन किसी कारण से वह नहीं लग पाया। जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार थी तो उन्होंने एक बस डबवाली से चण्डीगढ़ के लिए शुरू की थी जो कालांवाली भी हो कर आती थी। इसलिए एक बस सीधी चण्डीगढ़ और दिल्ली के लिए जरूर चलवाने की कृपा करें। मेरे हल्के में कालांवाली एक कस्बा है जो मेरे हल्के का मेन पिण्ड है उसमें बस अड्डे की बहुत बुरी हालत है। आज भी मुझे बहुत फोन आए कि वहां पर पानी भरा हुआ है और वहां पर बस खड़ी नहीं हो सकती। वहां पर सवारियों के रूकने के लिए कोई शैड नहीं है। जैसे अब आगे गर्मी का मौसम आ रहा है वहां पर कोई पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है, बिजली का इन्तजाम नहीं है और लड़के-लड़कियों के लिए बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां के बस अड्डे की बहुत बुरी हालत है उसको ठीक करवाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की सड़कों का बहुत बुरा हाल है मेरे पास पूर्व मंत्री भी बैठे हुए हैं और पिछली सरकार के जिम्मेवार आदमी भी बैठे हुए हैं उन्होंने बीच-बीच में बोलने की भी कोशिश की कि हमने यह किया है, वह किया, लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने किया ही कुछ नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सड़क चौटाला साहब ने बनवाई हुई हैं, पिछली सरकार के 10 सालों में आज तक उनकी मरम्मत भी नहीं हो सकी। पंजाब में एक गुरूगोबिन्द सिंह मार्ग है जिसका मैंने शुरू में प्रश्न भी लगाया हुआ था लेकिन मंत्री जी ने मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि उस मार्ग के बीच में जो पिण्ड आ रहा है उसकी जगह गलती से कोई सिंहपुरा पिण्ड डल गया जबकि वहां केवल पिण्ड डालना चाहते थे। उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सर, जो गोबिन्द सिंह मार्ग है वह पंजाब ने पिछली सरकार में ही पूरा कर दिया था। वह साढ़े हरियाणा दे केवल पिण्ड विच ही रूका हुआ है। पिछली सरकार ने इस क्षेत्र के साथ बहुत राजनीति किती, बहुत ही घोषणाएं किती। हुड्डा साहब खुद सिरसा में जाकर बोलकर आए थे कि इस मार्ग के टैंडर लग चुके हैं। सर, आज तक यह पता नहीं लगा कि वह मार्ग कागजों में कहां है, उसका टैंडर हुआ है, पैसा आया है या नहीं आया ? उस मार्ग का काम ज्यों का त्यों वहीं खड़ा है। इसी प्रकार तलवंडी साबो जोकि साढ़ा धार्मिक स्थल है वह भी इस मार्ग के विच ही पड़ता है जो खासकर पंजाब नूं और सारे हरियाणा नूं जोड़ता है। इसलिए सरकार कृपा करके इस तरफ भी ध्यान दे और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का आश्वासन दे। सर, जिनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह बिल्कुल ठप्प पड़ी हैं। न तो किसी पी.एच.सी. में डॉक्टर है और न ही किसी सी.एच.सी. में डॉक्टर है। मंत्री जी डॉक्टरों की कमी का तो पहले ही विश्वास दिला चुके हैं कि वह उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। सर, कोई भी, कहीं भी सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. में फोर्थ कलास कर्मचारी नहीं है। यहां तक कि स्वीपर भी नहीं

है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आगे जो गर्मी का मौसम आ रहा है जिसमें मलेरिया फैलने का भी डर होता है। सारे सिरसा में केवल एक मलेरिया वर्कर है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसका भी इन्तजाम करने की कोशिश करें। डॉक्टरों की कमी है लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं जिनकी बहुत जरूरत है। क्योंकि सफाई कर्मचारी न होने से सरकार ने जो स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है उसके ऊपर भी प्रश्न चिह्न लगता है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, मलेरिया के बारे में सदस्य ने बात की है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार पानी से मच्छर मारने का काम करती थी। पिछली सरकार ने मच्छरों को मारने के लिए जो दवाई खरीदी हुई थी उस दवाई का हमने हिन्दुस्तान की जो सबसे ज्यादा रैंकिंग की लैबोरट्री है श्री राम लैबोरट्री उससे टैस्ट करवाया तो उसमें बताया गया कि उसमें दवाई निल है खाली पानी सप्लाई हुआ है और जिसकी कीमत कागजों में लगभग 21 लाख 90 हजार रूपये की है। अब हमने उसके खिलाफ मुख्यमंत्री के आदेश से कल एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। सर, अभी हम जाँच करेंगे हो सकता है ये 10 साल तक पानी से ही मच्छर मारते रहे हों। उसकी हम जाँच करेंगे कि इन्होंने उस फर्म से कितनी दवाई सप्लाई करवाई। अध्यक्ष महोदय, मैं भी हैरान होता था कि वह धुआँ तो छोड़ जाया करते थे क्योंकि उसमें समैल तो थी मगर उसमें मैडिसन नहीं होती थी तो मच्छर कैसे मरते। हां, उसमें डिजल डालकर धुआँ जरूर छोड़ जाते थे और मच्छर वहीं के वहीं कूदते रहते थे। अब हम इसका इन्तजाम करेंगे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : सर, धुआँ छोड़ने वाली दवाई में पानी कहां से आया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास श्री राम लैबोरट्री की रिपोर्ट हैं, यदि आपकी सहमति हो तो मैं माननीय सदस्य को दे देता हूँ। कांग्रेस सरकार ने मच्छर मारने की दवाई दिनांक 21 जून, 2014 को खरीदी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, ये सब बातें गलत है। सही नहीं हैं। सरकार चाहे तो इसकी इन्क्वायरी करवा लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसमें गलत क्या है । दिनांक 21 जून, 2014 को दवाई खरीदी गई थी। इसकी जाँच होने से पता चलेगा क्या कि सभी ड्रमों में दवाई की जगह पानी भरा हुआ था या नहीं अध्यक्ष महोदय किसी भी ड्रम में मच्छर मारने की दवाई नहीं थी बल्कि पानी से मच्छर मारते थे, इसलिए मलेरिया की बीमारी से हरियाणा प्रदेश की जनता की हालत बिगड़ रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, पानी से मच्छर नहीं मरता है बल्कि वह उभरता है।

श्री बलकौर सिंह कालांवाली : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार ने हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है। एक सिख को दूसरे सिख भाई से लड़ाने का काम किया है (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस सरकार में जितने भी एस.जी.पी.सी. के स्कूल बने थे, उनको एन.ओ.सी. नहीं दी। एस.जी.पी.सी. के कारण सिखों को आपस में लड़ाने का

[श्री बलकौर सिंह कालांवाली]

काम किया और यहाँ तक कि झूठे एफिडेविट लेकर सिखों को आपस में बांटने की भी कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी एस.जी.पी.सी. के स्कूल बने हैं उनको एन.ओ.सी. दें जिससे कि हरियाणा प्रदेश की जनता को फायदा हो सके। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में पंजाबी भाषा को अमली रूप दिया जाये। हरियाणा प्रदेश में पंजाबी टीचर की जल्दी से जल्दी भर्ती किए जायें ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता को सहूलियतें मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन(नूँह) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नूँह मेडिकल कॉलेज सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से अटैच है परन्तु वहाँ पर इलाज के लिए इतनी सुविधा नहीं है जितनी कि एम्स दिल्ली में है, इसलिए इसको भी एम्स दिल्ली से अटैच किया जाये। अध्यक्ष महोदय, एम्स की ओ.पी.डी. बल्लभगढ़ में शिफ्ट होने जा रही है और इसके साथ नूँह मेडीकल कॉलेज में भी एम्स की ओ.पी.डी. का प्रावधान किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर ने भी माना है कि वहाँ पर पानी की किल्लत है। वहाँ पर रोजाना 8 लाख लीटर पानी की मात्रा चाहिए लेकिन कई दिन तक तो रोजाना एक लाख लीटर ही पानी मिला है जबकि ढाई लाख लीटर पानी की एवरेज रोजाना की है। मेवात के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रैनीवैल के नाम से 425 करोड़ रूपये की बहुत बड़ी पेयजल योजना दी थी। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर मैन बुस्टिंग स्टेशन हौजपुरी में बनना था लेकिन कांग्रेस सरकार ने मैन बुस्टिंग स्टेशन हौजपुरी की बजाय कौंडल में ही बनाकर खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उसके कारण मेडीकल कॉलेज, नूँह को और 21 गाँव को पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ की जनता टैंकरों से पानी पीने के लिए विवश है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने नई स्कीम बनाई थी कि इस स्कीम के तहत नूँह और नल्लड़ मेडिकल कालेज की वाटर सप्लाई ऑग्युमैंटशन के लिए पैसा आना है यह पैसा एन.सी.आर.पी.बी. से आना है। अध्यक्ष महोदय, बादली से प्लाँट लगकर सीधा नूँह के लिए लाइन जानी थी। उसको भी डिस्टर्ब कर दिया जैसे इन्होंने रैनीवैल प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब किया था। अध्यक्ष महोदय, फरूखनगर और पटौदी को पाइप लाइन से जोड़ दिया गया। आज इनमें जरूरतें बहुत बढ़ चुकी हैं जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज नूँह तक पानी नहीं पहुँच रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि मेडिकल कॉलेज के लिए पानी की लाइन बादली से सीधी आनी चाहिए। नल्लड़ मेडिकल कॉलेज को ट्यूबवेल के द्वारा पानी की सप्लाई होती है। किसी भी समय ट्यूबवेल खराब हो सकता है, जिससे मेडिकल कॉलेज पानी के लिये खड़ा का खड़ा रह जायेगा इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि पानी के लिये सीधी लाइन बादली से जोड़ने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया है वाकई में यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि 389 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज तो बन गया है परन्तु उसमें पीने का पानी और बिजली की दिक्कतों के अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। पिछले 10 वर्षों में जितनी भी अनियमितताएँ मेडिकल कॉलेजों में

हुई हैं, उनकी लगातार शिकायतें मेरे पास आ रही है, इसलिए मैंने आज ही इन तीनों मेडिकल कॉलेजों का पिछले 10 वर्षों का ऑडिट प्रधान महालेखाकार (ए.जी.) से कराने के आदेश जारी किये हैं । अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में क्या-क्या अनियमितताएँ हुई? क्या-क्या लूट मची ? किन कारणों से पीने का पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं हुई ? इसलिए मैंने प्रधान महालेखाकार (ए.जी.) से पर्सनली भी रिक्वेस्ट की है और लिखित रूप में भी भेज दिया है कि तीनों मेडिकल कॉलेजों का एक स्पेशल ऑडिट करें ताकि सारी सच्चाई जनता के सामने आ सके और जिन-जिन लोगों ने लूट मचाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधानसभा की सब्जैक्ट कमेटी ऑन पब्लिक हैल्थ इरीगेशन एण्ड पॉवर समिति की चेयरपर्सन श्रीमती संतोष चौहान सारवान व समिति के अन्य सदस्यों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने स्वयं चलकर मेवात जिले का दौरा किया जिससे नूँह क्षेत्र के विकास के कामों में काफी फर्क पड़ा है लेकिन पानी की समस्या मेडिकल कॉलेज में और नूँह क्षेत्र में ज्यों की त्यों ही है। नूँह क्षेत्र में सैक्टरों के लिये कई साल पहले जमीन एक्वायर हो गई थी लेकिन आज तक एक भी ईंट नहीं लगी है, उससे स्लैम डिवैल्प हो रहे हैं। नूँह के अन्दर सैक्टरों की जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है, जिससे वहां डिवैल्पमेंट होनी चाहिए और सैक्टर काटे जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नूँह के अन्दर नल्लहड़ में प्राचीन शिव मन्दिर होने के कारण लाखों श्रद्धालु हर साल देश भर से आते हैं, इसलिए नूँह क्षेत्र से नल्लहड़ तक तीन किलोमीटर के रास्ते को फोर लेन करने के साथ-साथ स्ट्रीट लाइट का भी इन्तजाम किया जाना चाहिए। नूँह क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र नहीं है उसका इन्तजाम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बॉयो फर्टिलाईज़र पर जो छूट दी है वह बहुत कम है इसके अलावा मेरा और, हमारी पार्टी का मानना है कि जो एग्रीकल्चर इक्विपमैंट जैसे पैस्टीसाईड हैं और डीजल हैं उनपर भी वैट में छूट देनी चाहिए। पॉली हाउसिज़ का जो नया चलन चला हुआ है वह मेवात तक भी पहुँच गया है। पॉली हाउस में लोगों को बड़ी भारी दिक्कते हैं। आज जमींदारों को ना दवाइयां मिलती हैं और ना ही कोई साधन मिलते हैं, उसका जो प्रोड्यूज है उसको खरीदने का इन्तजाम हो। दूसरी बात यह है कि जमीन कम हो रही है और जो कृषि से जुड़े हुए जो भूमिहीन बेरोजगार युवक हैं उनकी एक सोसॉयटी बनाकर उनको पंचायत की जमीन अलॉट की जाये, जिससे वे भी पॉली हाउस लगा सकें। इसमें खासतौर पर हमारे एस.सी.बी.सी. के नौजवान बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, इस तरह से हम बहुत से लोगों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेवात के अन्दर बेमौसमी बरसात की वजह से पीछे 2-3 मार्च को बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि कई जगहों पर शतप्रतिशत फसल खराब हो चुकी है, इसलिए उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। सिंचाई के बारे में हमारे प्रतिपक्ष नेता ने कहा है कि दक्षिण हरियाणा से रोहतक तो अलग हो गया है, यदि माननीय सदस्य को हनुमान जी की तरह शक्ति होती तो अपनी छाती चीर कर दिखा देते कि कितनी अन्याय की गाथाएं लिखी हुई है। पानी का असमान बंटवारा हुआ है, हम गंदा पानी जहर के रूप में पीने के लिये मजबूर हैं। पानी को लेकर माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि दिल्ली में मीटिंग है तो उसमें मैं यह बात रखना चाहता हूँ कि हमारी मेवात फीडर कैनाल जो बननी है जिसके लिये सैन्टर वॉटर कमीशन ने प्रिलिमिनरी प्रोजैक्ट रिपोर्ट दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को एप्रूव कर दी थी, उसकी डी.पी.आर. बननी है।

[श्री जाकिर हुसैन]

751 क्यूसिक में यह नहर होगी जिसमें हमें पानी कहीं से नहीं लेना है, यह बड़ा अहम मुद्दा है कि पानी हमें 0.37 एम.ए.एफ यमुना से और 0.12 एम.ए.एफ. रावी ब्यास से ऑलरेडी अलॉटिड है। अध्यक्ष महोदय, जो पानी हमें आज की तारीख में गुड़गांव कैनाल के थ्रू मिलना चाहिए। सर, यह यमुना अपर वॉटर बोर्ड का फैसला है कि 600 क्यूसिक पानी पर मेवात जिले का हक है। हमें यह पानी मिलना चाहिए और फरीदाबाद, पलवल जिले का जो पानी 76 हजार आर.डी. पर है वह भी हमें मिलना चाहिए और जो 100-150 क्यूसिक पानी हमें मिल रहा है वह हमें गंद मिल रहा है। मैं आज इस विषय को मीटिंग में रख रहा हूं। मैं आपको इससे सम्बन्धित सारे कागजात भी देता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस समस्या का हल निकाला जाए। यह इस एरिया के डिवैल्पमेंट से संबंधित है। सन् 2000 में जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैलप किया और इससे सरकार को काफी फायदा हुआ और गुड़गांव शहर को डिवैल्प होने में इससे काफी मदद मिली। लेकिन आज गुड़गांव में जितने सैक्टर्स डिवैल्प हुए हैं उनमें ज्यादातर प्राइवेट बिल्डर्ज द्वारा डिवैल्प किये जा रहे हैं। इन सैक्टरों में जमीन के रेट इतने ऊंचे हैं कि आम आदमी इनमें जमीन खरीद नहीं सकता। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इन सैक्टरों को खुद डिवैल्प करें और उन्हें जनता को रियायती रेट पर दे। किसी भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी सड़क और पानी की आवश्यकता होती है। मेवात में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर सन् 1903 में दिल्ली से अलवर तक अंग्रेजों ने एक सड़क बनाई थी जिस पर क्वीन विक्टोरिया गई थी। उस समय जयपुर रोड़ नहीं बना था परंतु अब अलवर रोड़ को छोड़कर जयपुर रोड़ को डिवैल्प किया गया है और उसके बाद भिवाड़ी रोड़ को डिवैल्प किया गया । हमारे पलवल के क्षेत्र को एक टापू की तरह छोड़ दिया गया है। सन् 1966 में जब हरियाणा प्रदेश का निर्माण हुआ तो हमें उस वक्त उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा जोकि विकास को तरस रहा है। अध्यक्ष जी, एस.वाई.एल. के पानी का तो पता नहीं लेकिन जितने पानी पर हमारा हक है हमें वह दिलाया जाए । अभी जब मैं नमाज पढूंगा तो आपके लिए दुआ मांगूंगा कि आप और तरक्की करें। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार के बाद अब हमें लग रहा है कि हमारे मेवात के क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है। अब वहां पर जल बोर्ड के जे.ईज. है वे भी अच्छा काम कर रहे है और प्रधान सचिव जैसे उच्च अधिकारी निरीक्षण करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटला झील का जीर्णोद्धार किया है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक मरती हुई परियोजना को जिंदगी दी है। यह एरिया मेन अलवर रोड पर है। इस परियोजना को और आगे बढ़ाया जा सकता है। यह एरिया 5 हजार एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिस पर आप झील डिवैल्प कर सकते हैं। यहां पर एक टुरिस्ट कॉम्पलैक्स बनाया जा सकता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवा लें। आपको पता चलेगा कि यहां पर पब्लिक हैल्थ की पीने के पानी की एक बड़ी परियोजना स्थापित की जा सकती है जिसके थ्रू मेवात के विकास हो को एक नई दिशा मिल सकती है। अध्यक्ष जी, मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड के बारे में माननीय गवर्नर साहब ने कहा है कि यह परियोजन मर चुकी है और हम इसे पुनर्जीवित करेंगे। पिछली सरकार के अधिकारियों, विधायकों तथा मंत्रियों ने इस मरी-मराई परियोजना को भी ऐसे नोंचा है जैसे किसी चीज को चील-कौए नोंचते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका ऑडिट करवाया जाए और इसकी इन्कवायरी करवाकर जो व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाएं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी

जाए। अध्यक्ष जी, इस क्षेत्र की इतनी अनदेखी हुई है कि पिछले 6 साल में मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। पिछली सरकार में जो विधायक थे अगर वे दोबारा विधायक नहीं बने तो उन्हें सारी जिंदगी यह मलाल रहेगा कि वे इसकी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए लेकिन इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरी आपसे अपील है कि मेवात में एक युनिवर्सिटी बनाई जाए। भाजपा ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है यह कदम उस दिशा में सबसे बड़ा सहयोग होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की तर्ज पर जो मेवात की बहु-बेटियों के लिए स्पेशल नि:शुल्क बसों की सुविधा का प्रावधान किया है इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। यह काफी पुरानी स्कीम है जिसे चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने शुरू किया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस स्कीम को और आगे बढ़ाएं। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण)

[14.00 बजे] **श्री अध्यक्ष** : अब श्री उमेश अग्रवाल जी बोलेंगे। उमेश जी, आप पांच सात मिनट में अपना बजट भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री उमेश अग्रवाल (गुडगाँव) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में जो वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर से शिक्षा के बजट में उन्होंने 32 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया था क्योंकि पहली से आठवीं तक की कक्षाओं तक परीक्षाएं समाप्त कर दी गईं थी। अब हमारी सरकार आने के बाद सरकार ने सभी स्कूलों की कक्षाओं में मंथली टैस्ट, डेली टीचर डायरी और वार्षिक परीक्षाएं शुरू कर दी हैं। ऐसा करने से शिक्षा के स्तर में परिवर्तन आने की संभावना हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में एक लाख 20 हजार से भी अधिक अध्यापकों के कुल पद हैं जिन में से 40 हजार के करीब पद रिक्त पड़े हुए हैं। उन अध्यापकों के 12000 के करीब पदोन्नति वगैरह के केसिज पैंडिंग थे जिनमें से 9000 के करीब वर्तमान सरकार के आने के बाद निपटा दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 14570 के करीब स्कूल हैं जिनमें से 1000 के करीब स्कूलों में या तो शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी अगर थी तो उन शौचालयों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा था। वर्तमान सरकार ने 43 करोड़ रूपये शौचालयों की व्यवस्था के लिए भी इस बजट में दिए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक अधिकारी को माह

[श्री उमेश अग्रवाल]

में दो बार स्कूलों को बैक करने का आदेश भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम हरियाणा में उच्चतर शिक्षा की बात करें तो हरियाणा में 15 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से तीन यूनिवर्सिटीज रोहतक में हैं, तीन यूनिवर्सिटीज हिसार में हैं, दो यूनिवर्सिटीज सोनीपत में हैं, एक यूनिवर्सिटी भिवानी में, एक यूनिवर्सिटी कुरूक्षेत्र में, एक यूनिवर्सिटी सिरसा में और एक यूनिवर्सिटी जीन्द में है। जबकि प्रदेश को 50 प्रतिशत से ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला गुड़गांव जिसकी आबादी 25 लाख से भी अधिक है उसमें एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गुड़गाँव के अन्दर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए क्योंकि गुड़गाँव में दो लाख से भी अधिक छात्र-छात्राएं हैं । वहां पर एक यूनिवर्सिटी की सख्त आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का भी पुन : धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है जबकि जैव उर्वरक तथा एल.ई.डी. इत्यादी पर टैक्स समाप्त और कम किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दस वर्षों में व्यापारियों का जिस प्रकार से शोषण हुआ है उस शोषण से व्यापारियों को मुक्ति दिलाना नितान्त आवश्यक है । इसके लिए मैं सदन में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जिला कुरूक्षेत्र की पेहवा तहसील के मुस्तापुर गाँव में 16 मार्च 2008 को एक ही परिवार के नौ लोगों ने आत्म हत्या कर ली थी आत्म हत्या तो नाम दिया गया था असल में वह हत्या ही थी । उस हत्या का कारण यह था कि जिन किसानों ने उस व्यापारी से पैसा लिया हुआ था वह पैसा उन किसानों ने वापिस नहीं दिया । उस आढ़ती ने जिस एजैन्सी का पैसा देना था उस एजैन्सी को समय पर पैसा नहीं दिया गया। इसी कारण से पूरे परिवार के नौ लोगों ने आत्म हत्या की थी । व्यापारी जो टैक्स देता है वह टैक्स वह अपने पास से नहीं देता बल्कि वह एक टैक्स कलैक्टर है क्योंकि वह ग्राहकों से टैक्स कलैक्ट करके सरकार के खजाने में पैसा जमा करवाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर व्यापारी को टैक्स पेयर की बजाये टैक्स कलैक्टर का दर्जा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की यह पहले भी रीति थी । टैक्स कलैक्टर का दर्जा मिलने के साथ साथ जो व्यापारी जितना टैक्स इकट्ठा करते हैं उसमें से उसकी एक प्रतिशत राशि व्यापारी कल्याण कोष में जमा हो और उस पैसे से व्यापारियों के लिए भी पैंशन और नि :शुल्क दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की जाए जिससे उनका कल्याण हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में बजट की किस प्रकार से खराब व्यवस्था थी उसकी तरफ भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस साल केन्द्र सरकार ने राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया है। शहरों के अन्दर जो स्टाम्प डयूटी का पैसा आता है वह दो प्रतिशत पैसा अतिरिक्त दिया जाता है । जिसके बारे में माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा ने भी चर्चा की । पिछली सरकार के समय में उस पैसे की किटी बनाकर दिनांक 1.4.2012 को एक पूल में डालना शुरू कर दिया। जिसके कारण फरीदाबाद जैसे जो दूसरे बड़े शहर थे उनका स्टाम्प डयूटी का पैसा प्रदेश के केवल एक जिले में खर्च होने लगा । जिसके कारण दूसरे सभी शहरों का भट्ठा बैठ गया । अगर मैं गुड़गाँव की बात करूं तो स्टाम्प डयूटी का पैसा दो प्रतिशत के हिसाब से पिछले चार सालों का लगभग 800 करोड़ रूपये बनता है जबकि गुड़गांव को केवल 322 करोड़ रूपये मिले और बाकी के 478 करोड़ रूपये गुड़गाँव के हिस्से का पैसा दूसरे शहरों को दे दिया गया । इसके बारे में मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि स्टाम्प डयूटी का दो प्रतिशत पैसा जिस शहर का होता है उसी शहर को दिया जाए । अध्यक्ष महोदय, बजट

के पैरा न.10 में एक और बात कही गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कम रोजगार होने के कारण लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस पलायन के कारण शहर ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसके लिए मैं गुड़गांव का उदाहरण देना चाहूंगा कि गुड़गांव में लोग विशेष तौर पर रोजगार की तलाश में आये और गुड़गाँव में जो आयुध डिपो (Ammunition Depot) है जिसकी परिधि 900 मीटर की है उसके आसपास सस्ती जमीन होने के कारण वे लोग उस आयुध डिपो के पास अपने मकान बनाकर बस गये । उन लोगों का उस एरिया में बसने का एक कारण और भी था कि पिछली सरकार ने जो एस.ई.जैड बनाने की जो घोषणा की थी जिसके अन्दर दस करोड़ रूपये का निवेश करके दस लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी । उनका वह वायदा भी पूरा नहीं हो पाया। वहां पर जो लोग आकर बसे हुए हैं आज उनको मूलभूत सुविधायें नहीं मिल रही हैं। बिजली, पानी व सड़कों की सुविधा उनको अभी तक नहीं मिली हैं तो सीवरेज सुविधा की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात है। गुड़गाँव जैसे एन.सी.आर. क्षेत्र में जो दिल्ली से सटा हुआ है वहां पर जो लोग आयुध डिपो की परिधि में रहते हैं उनकी ढाई लाख की संख्या है। ये लोग मूलभूत सुविधवाओं से वंचित हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनाँक 31.1.2013 को आदेश दिये थे कि वहां के नागरिकों को मूलभूत सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर दी जायें लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार ने उनको आज तक मूलभूत सुविधायें नहीं दी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग रहते हैं जो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, उनको तुरंत मूलभूत सुविधायें प्रदान की जायें ताकि वे इस नारकीय जीवन से बाहर आ सकें। चूंकि मैं व्यापारी वर्ग से संबंध रखता हूं इसलिए जितना आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मैंने उतने ही समय का सदुपयोग करते हुए सदन के सम्मुख अपनी बात रखी है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयभान जी, अब आप बोलिए तथा केवल 5 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री उदयभान (होडल) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। 17 मार्च, 2015 को माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में बज़ट पेश किया था। इस बज़ट से प्रदेश की जनता, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति वर्ग, कर्मचारी वर्ग आदि सभी वर्गों को बहुत आशाएं, उम्मीदें और अपेक्षाएं थी। लेकिन इस लोक लुभावने बज़ट में केवल ढींगे हॉकने के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं कह सकता हूं कि खोदा पहाड़, निकली चुहिया। चुनावों के दौरान इस सरकार द्वारा की गई 159 घोषनाओं में से कोई भी पूरी नहीं की गई। युवा वर्ग के लोग भाजपा की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे तथा मोदी-मोदी के नाम से पागल हो गये थे क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया था कि 10+2 पास बेरोजगार नवयुवकों को 6,000/- रूपये तथा ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट पास नवयुवकों को 9,000/-रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा लेकिन इस दिशा में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की बात कही गई थी लेकिन इस बारे में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आप कहते हैं कि आपने सदन में कर-रहित बज़ट पेश किया है, यह बात बड़ी अजीब लगती है। आपने तो बज़ट पेश होने से पहले ही हरियाणा में डीजल पर वैट लगाकर 1400 करोड़ रूपये का बोझ प्रदेश की

[श्री उदयभान]

पेश होने से पहले ही हरियाणा में डीजल पर वैट लगाकर 1400 करोड़ रूपये का बोझ प्रदेश की जनता पर डाल दिया है। पहले हरियाणा राज्य में दिल्ली, चण्डीगढ़ व पूरे देश की अपेक्षा पैट्रोल व डीजल सस्ते दामों पर मिलता था लेकिन अब पैट्रोल व डीजल हरियाणा में सबसे महंगा मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप हरियाणा में भी वैट आदि लगाकर गुजरात मॉडल तो लागू नहीं करने जा रहे हैं तथा यहां पर भी डीजल व पैट्रोल के रेट्स गुजरात राज्य के बराबर तो नहीं करने जा रहे हैं ? पहले तो यह भी कहा गया था कि किसानों को जैविक खाद संबंधी बड़ी भारी सुविधा प्रदान की जायेगी। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार चेयर पर पदासीन हुए)** मैं कहना चाहूंगा कि जैविक खाद पर जो रिलैक्सेशन दी गई है वह ढाई लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है। यदि सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़े भी देखें तो पता चलेगा कि पहले यह 18.1 प्रतिशत् था लेकिन अब यह 18.9 प्रतिशत् पर चला गया है। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति वर्ग के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि वायदा तो यह किया गया था इस वर्ग के बैकलॉग को पूरा किया जायेगा लेकिन अभी तक तो इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति वर्ग के बैकलॉग को स्पैशल ड्राईव चलाकर पूरा करेंगे या किसी और अन्य प्रक्रिया द्वारा पूरा करेंगे ? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में रोस्टर प्रणाली लागू करेंगे अथवा नहीं ? एक विषय के बारे में मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने प्रोमोशन में रिजर्वेशन के मामले में पी.राघवेन्द्र राव की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री होते थे उस समय 50वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था जो 1 जुलाई, 1995 को लागू होना था जो आज तक लागू नहीं हुआ है। मैं सरकार से यह अपील भी करना चाहूंगा कि उस विधेयक को हरियाणा प्रदेश में लागू करने की कृपा करे। इस बारे में हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिये हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रोमोशन में रिजरवेशन की पॉलिसी को मूल रूप से 1 जुलाई, 1995 से लागू किया जाये जिससे बहुत बड़ा क्रेडिट इस सरकार को ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को 100-100 वर्ग गज के जो प्लॉट दिये गये हैं। उनके लिए सही ढंग के रास्ते बनाए जाएं, नालियां बनाई जाएं तथा जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वे उपलब्ध कराई जाएं। बजट में लिखा है कि 41 हजार रूपये की राशि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के लिए है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह राशि केवल शिडयूल्ड कास्ट के लिए है लेकिन यह राशि बी.पी.एल. सम्बन्धित सभी वर्गों के लिए है इसलिए उसमें लिखना चाहिए था कि बी.पी.एल. के लोग चाहे वे समाज के किसी भी वर्ग से सम्बंध रखते हों उनके लिए 41 हजार रूपये की ग्रांट दी जाएगी इसलिए इस बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के लिए, इंदिरा आवास योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम आदि के लिए बजट में ठीक से प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनके बजट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, शिडयूल्ड कास्ट को मकान बनाने के लिए सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट 50 हजार रूपये तथा मकान की मरम्मत के लिए केवल 10 हजार रूपये देता है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 10 हजार रूपये में मकान की मरम्मत होती है और 50 हजार रूपये में मकान बन सकता है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मकान बनाने के लिए कम से कम 50 हजार की बजाय दो लाख रूपये किए जाएं और मरम्मत के लिए 10 हजार रूपये की बजाय 50 हजार रूपये किया जाए ऐसा मेरा अनुरोध है। सभापति महोदय, हमारे कृषि मंत्री महोदय ने सिंचाई के बारे में अपनी

भावनाएं व्यक्त की हैं। उनकी नियत पर हमें पूरा भरोसा है और वे हर खेत तक पानी देने के मामले में गम्भीर नजर आ रहे हैं। जो गंदा पानी है उसके बारे में बहुत बार यहां चर्चा हुई । यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल हमारे गुड़गाव, पलवल और फरीदाबाद की लाइफ लाइन है लेकिन उसमें दिल्ली से कैमीकल युक्त पानी आ रहा है। सभापति महोदय, जिस तरह हैदरपुर ट्रीटमैंट प्लांट के तहत और वजीराबाद प्लांट के तहत साफ पानी दिया जा रहा है उसी तरह हमारी कैनाल में भी साफ पानी दिया जाए । (विघ्न) सभापति महोदय, मैं जल्दी कंक्ल्यूड करूंगा और अच्छे सुझाव दूंगा । ये सुझाव सरकार के लिए बहुत बढ़िया सुझाव हैं क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि मीटिंग होने वाली है इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि 26 नाले जो यमुना में पड़ते हैं उन पर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगने चाहिएं और यमुना एक्शन प्लान के तहत यह चीज है । सभापति महोदय, बी.जे.पी. सरकार ने गंगा और यमुना को साफ करने का संकल्प लिया है और उसके लिए आन्दोलन भी चला रहे हैं । सभापति महोदय, मथुरा की तरफ से हमारे पलवल को क्रॉस करके पानी आ रहा है इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पानी यमुना में गिरे वह ट्रीट होकर गिरे। सभापति महोदय, सरकार सुनिश्चित करे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी जब दिल्ली सरकार से बात करें तो उनको पाबंद किया जाए कि जो गंदा पानी है वह यमुना में ट्रीट होकर डले। सभापति महोदय, ओखला हैड पर जो पानी मिलता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उसमें 52 परसैंट पानी जो है वह हरियाणा का हिस्सा है, उसमें 21 परसैंट पानी राजस्थान का है और 27 परसैंट उत्तरप्रदेश का है। जो हमारा हरियाणा का हिस्सा है वह आगरा कैनाल और गुड़गाव कैनाल के माध्यम से हमें मिलता है। सभापति महोदय, होडल और हसनपुर दो रजवाहों को 33 हजार क्यूसिक पानी 4 महीनों में मिलना चाहिए था जबकि उसके अगेनस्ट 4255 क्यूसिक पानी मिल रहा है तो किस प्रकार हर क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। सभापति महोदय, इसी तरह से हमारा हथीन रजवाहा है उसकी मानपुर डिस्ट्रीब्यूट्री से डाढ़का माइनर निकलती है। उसमें 7-8 गांव सेवली, लोहाना, सोंधा, डाढ़का, होडल, होडल पटीगढ़ी और बोराका पड़ते हैं और इन गांवों की लगभग 6 हजार एकड़ जमीन की कमांड इसी से होती है लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं आता है जिसके लिए प्रपोजल हमने डिपार्टमैंट को भेज रखी है । सिंचाई विभाग ने तो प्रपोजल एप्रूव कर दी है लेकिन फाइनांस डिपार्टमैंट से रिवर्ट हो गई है, इसमें केवल 64-65 लाख रूपये का बजट है । अगर उसको पास करके प्रपोजल के मुताबिक कार्य कर दिया जायेगा तो 6 हजार एकड़ जमीन पर सिंचाई हो सकती है। इसी तरह से उजीना डायवर्शन ड्रेन की आर.डी.-0.25 पर पक्का हम्प बनना है और इस पर करीबन 66 लाख रूपये का बजट है। यदि ये दोनों कार्य हो जाते हैं तो हमारे वहां 10 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आबियाने की दर हमारे एरिया से भी उसी के मुताबिक ली जाये जिस प्रकार से पूरे प्रदेश से ली जाती है। सभापति महोदय, हमारे होडल की जो अनाज मण्डी है उसमें बेसिक इन्फ्रास्ट्रैक्चर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने आश्वासन दिया है। मेरा अनुरोध है कि होडल अनाज मण्डी में बेसिक इन्फ्रास्ट्रैक्चर जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए। इसी तरह से गवर्नमैंट गर्ल्ज कालेज,जो मितरोल में बनाना है हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे जो कार्य पाईप लाईन में है यह कार्य भी जल्द करवाया जाए। हम सरकार से कोई नए कार्य की डिमाण्ड नहीं कर रहे, जो कार्य पहले से ही मंजूर हैं और पाईप लाईन में हैं उन्हीं को पूरा करने की बात कर रहे हैं। हमारा पलवल जिला तो सरकार के टार्गेट से बाहर है जो 3 जिले अलग कर रखे हैं। हमारा

[श्री उदयभान]
पलवल जिला तो सबसे दूर है और यू.पी. के साथ बॉर्डर पर है। इसलिए हमारे जिले पर मेहरबानी करके जो कार्य सरकार ने मंजूर कर रखे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए और बजट में पैसे का प्रावधान किया जाए। इसी तरह से बामलीपुर-हसनपुर रोड़ पर आर.ओ.बी. की मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आये हैं उस पर भी जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। इसी तरह से होडल हुडा सैक्टर उसमें भी जल्दी-जल्दी सुविधाएं दी जाएं। इसके अलावा जो गवर्नमैंट कालेज है उसकी बिल्डिंग की ड्राईंग भी पास हो गई है, पैसा भी मंजूर हो गया है उसका कार्य भी जल्द से जल्द करवाया जाए।

श्री सभापति : उदयभान जी, प्लीज आप वाईंड अप करें ।

श्री उदय भान : सभापति महोदय, मैं अभी वाईंड अप करता हूं। मेरे हल्के की कुछ सड़कों के टैंडर वगैरह भी हो चुके हैं और डी.एन.आई.टी. भी हो चुकी है लेकिन पैसे का प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि पिंगोड़ से सिहार, सराय से गुदराना, सोंदल, लुहाना, सेवली, बंचारी, डकोरा, ओल्ड जी.टी. रोड होडल, बिडूकी, गढ़ीपट्टी से बिछोर की सड़कें हैं। इनके बारे में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पैसे का प्रावधान करके जल्द से जल्द इनको बनवाया जाए। इनके अतिरिक्त मार्केटिंग बोर्ड का हसनपुर बाई पास और गलावल से बछीपुरा का बाई पास आलरैडी सैंक्शंड है। इनके एस्टीमेट भी एप्रूव हो चुके हैं। इनको भी बनवाया जाए।

श्री सभापति : उदय भान जी, आपका समय समाप्त हो गया है। प्लीज, आप बैठें। अगर आपकी कोई समस्या बाकी रह गई है तो उसके बारे में आप लिखकर दे दें उसको रिकार्ड में दर्ज कर लिया जायेगा।

श्री उदय भान : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मेरे हल्के के डकोरा, मरौली, जलालपुर, आदि गांवों में पीने के पानी की बहुत समस्या है। इसलिए इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए। (विघ्न)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास(रेवाड़ी) : सम्मानित सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और सदन को प्रणाम करता हूं। इसके साथ-साथ अधिकारियों का सम्मान करता हूं और महमानों का स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक संतुलित, कल्याणकारी, निष्पक्ष, लाभकारी एवं जन भावनाओं के अनुरूप बजट है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित वीर अभिमन्यु उदर में ही दिव्य ज्ञान की प्रेरणा से प्रेरित ज्ञान को बजट के रूप में प्रस्तुत कर पाये इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।।

(इस समय मेजें थप-थपाई गई।) अत : जब जब धर्म की हानि होती है। (विघ्न) आप महान हैं कोई बात नहीं है, अर्थ समझ गये होंगे । यह मैंने क्यों कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतरित होता है। मैं सदन को अपने अनुभव की एक सच्ची कथा सुनाता हूं।

15 सितम्बर, 2013 को माननीय नरेन्द्र मोदी जी पहली बार हरियाणा प्रदेश में रिवाड़ी आए थे। तो उस समय मेरी और हमारे फाईनेंस मिनिस्टर कैप्टन अभिमन्यु जी की ड्यूटी थी कि हम उस समारोह में आने वाले सैनिक उच्चाधिकारियों को जल-पान करवाकर मंच तक पहुंचायें । यह काम हमने सुबह 11.30 बजे तक किया और इसके बाद जब हम 12.00 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को लेने के लिए हैलीपैड पर जा रहे थे तो उस समय वहां पर मौजूद तत्कालीन सूबेदार और आज के एक ऑनरेरी कैप्टन ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस पर मैंने उनको कहा कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से आपको पुलिस ने नहीं रोका तो आप मेरे साथ चल सकते हो। सौभाग्य से वे भी मेरे साथ हैलीपैड पर पहुंच गये। जैसे ही श्री नरेन्द्र मोदी हैलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो उस समय जब मैंने उनकी बॉडी लैंगवेज़, आंखों की तीव्रता और दिव्यता देखी तो उस समय मेरे मुंह से सहसा निकल गया कि भाई कप्तान साहब ये मोदी वो पहले वाले मोदी जी नहीं हैं बल्कि इनमें तो कोई विशेष दिव्य शक्ति अवतरित हुई है क्योंकि मैंने श्री मोदी जी को 10 साल पहले देखा था जब वे हरियाणा में थे उस समय वे सामान्य थे लेकिन मैंने यह महसूस किया कि उस समय उनमें कोई दिव्य शक्ति अवतरित हो चुकी थी और उसके बाद जैसा कि आपके सामने है मोदी जी का नाम जनता की तो बात छोड़िए गर्भ का बच्चा भी पुकार उठा मोदी-मोदी । यही सच्चाई बाद में साक्षात हो चुकी है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं और जो मैंने अभी कहा यह सभी बजट की भूमिका के रूप में मैंने कहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि राजनीति से ही बजट बनता है। (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : सभापति महोदय, आप मुझे भी बोलने के लिए थोड़ा सा समय दे दें।

श्री सभापति : शर्मा जी, अगर यहां पर माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी बैठे होते तो मैं आपको ज़रूर समय दे देता ।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : स्पीकर सर, मैंने आदरणीय मोदी जी का यह अवतरण इसलिए सुनाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अवतरण स्वामी दयानन्द सरस्वती जी पर हुआ, स्वामी विवेकानन्द पर हुआ, एक समय था जब यह अवतरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर हुआ, चौधरी देवी लाल जी पर भी यह अवतरण हुआ था और आंशिक तौर पर हम सभी के ऊपर भी होता रहता है यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब वह पद मिलता है और उस अवतरण की शक्ति मिलती है अगर हम उसका सदुपयोग करें तो हमारी महानता बढ़ती रहती है और अगर हम इसका दुरूपयोग करते हैं तो हमारे अंदर चौतरफा गिरावट आ जाती है। जैसा कि अभी यहां पर जिक्र आया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोपहर के समय आराम करने के लिए लॉन में लेट गये थे इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जब पद मिलता है तो हमें सादगी का परिचय देते हुए पद की गरिमा को भी बनायें रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा संजय जी ने महाराज धृतराष्ट्र को कहा था कि :-

यत्र योगेश्वर : कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर : ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।।

अर्थात हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण जी हैं और जहां गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है - ऐसा मेरा मत है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब-जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार के रूप में जन्म लेते हैं और इसी

[श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास]
प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जहां पर श्री भगवान श्रीकृष्ण जी हैं और जहां पर गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन हैं अर्थात जहां पर भगवान हैं और जहां पर कर्म करने वाले योगी हैं वहां पर नीति और विजय सनातन रहती है। ऐसे ही आप और हम सब लोग अर्जुन हैं और वे भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात परमात्मा हैं । आज हम सभी इस सदन में बैठे हैं। हम सभी सभासद राजनीति और धर्म की कसौटी पर हैं । विधायक का कार्य होता है कि वह विधायिका में बैठ कर विधायिका का कार्य करे, नीति निर्माण का कार्य करे और पब्लिक की भलाई का कार्य करे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सदन का एक-एक क्षण महत्वपूर्ण है इसलिए हमें अपना पूरा समय बजट बनाने में लगाये, नीति निर्माण में लगाये और अपने प्रदेश वासियों की भलाई के लिए योजना बनाने में लगायें। यह हमारा धर्म है और हमें इसका पालन करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि आज से पहले अधिकारियों और नेताओं के अहंकार का राज रहा है। मैं यह मानता हूं कि राज़ होना चाहिए कानून-व्यवस्था का और नीति का। इसलिए यह हमारा धर्म है और इसी पर चलकर हमें जनता की तमाम अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। हमें विधान सभा में वैधानिक सोच के साथ ही काम करना चाहिए। सरकार का खज़ाना आम किसान का है, आम मज़दूर का है और व्यापारी का है। यह किसी अधिकारी और नेता का नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस खज़ाने का पूर्ण रूप से सदुपयोग हो और समान बंटवारे के साथ सभी का सम्पूर्ण विकास हो। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर बेरोज़गारी की बात करूं तो आज जो हमारी युवा शक्ति है जिसे राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए था आज वह हक नहीं तो लूट की तरफ जा रही है। अगर ऐसा रहा तो तो वह समय दूर नहीं जब have और have not की लड़ाई शुरू हो जायेगी । ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों हमें इन सभी को यहीं पर रोकना है। यह हम सबका दायित्व है। बजट में यह हमारे वित्त मंत्री जी ने दिखाया है कि किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके, खनिज और खान में बड़े टुकड़ों को छोड़कर जो खान के छोटे टुकड़े हैं उनको बेरोजगारों को देने के लिए तथा योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, इसके लिए जो काम हो रहा है वह सराहनीय है । सभापति महोदय, अब मैं कुछ बातें अपने हलके के बारे में भी कहना चाहता हूँ ।

श्री सभापति : कापड़ीवास जी, आप कम समय में अपनी पूरी बात कह लीजिए।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : सभापति महोदय, मैं तो पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरा तवा देर से गर्म होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वहाँ पर पानी खारा है।

Shri Kuldip Sharma : Mr. Chairperson Sir, I would request that Shri Randhir Singh Kapriwas should disclose to this House to whom he has mentioned as 'Krishna Avtar'. Whether he is Chief Minister or somebody else, that has not been cleared.

Shri Randhir Singh Kapriwas : Mr. Chairperson Sir, I am talking about the Almighty God. शर्मा जी, यह बात तो आप हमारे विज साहब से पूछ लिया करो, हमारे से क्या पूछते हो । शहर और देहात में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है । शहर का सीवर सिस्टम अव्यवस्थित है । सभापति महोदय, मैं एक और गम्भीर समस्या की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। धारूहेड़ा में राजस्थान की इंडस्ट्रीज का प्रदूषित पानी

बह कर आता है। अभी जब पीछे बरसात हुई थी तो इतनी ज्यादा मात्रा में प्रदूषित पानी बह कर आ गया कि विधायक तो टेलीफोन ऑप्रेटर बन कर रह गया, सो भी नहीं पाया। बार-बार फोन बजते रहे कि पानी आ गया है। वह प्रदूषित पानी कई सालों से आ रहा है तथा इस बारे में कई बार राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की बैठकें भी हो चुकी हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बारे में या तो सरकार कोई कार्रवाई करे अन्यथा वहाँ के लोग सैन्ट्रल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाने को मजबूर हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि भिवाड़ी से जो प्रदूषित पानी आता है उसको रोकने की व्यवस्था की जाये। इसी प्रकार की एक समस्या और है कि रिवाड़ी दो भागों में विभाजित है । एक बड़ा रेलवे फाटक था जो पिछले 20 वर्षों से बंद है। ज्यादा रेलगाड़ियाँ चलने की वजह से आधा शहर पूर्व की तरफ हो गया और आधा शहर पश्चिम की तरफ हो गया है। इसलिए वहाँ पर अंडरपास की सुविधा प्रदान की जाये। सर्कुलर रोड की मुरम्मत की जाये तथा आउटर सर्कुलर रोड को रिंग रोड बनाया जाये। महिला विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये क्योंकि वहाँ पर 2700 लड़कियाँ हैं जो कि पीने के लिए अपने घर से पानी लेकर आती है। वहाँ पर नहर का पानी पहुंचा कर ही इस पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। कन्या उच्च विद्यालय केवल एक है और शहर की आबादी बहुत ज्यादा है। इसलिए कम से कम तीन कन्या उच्च विद्यालय और बनाए जाने चाहिएं। हमारे मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी खोली गई लेकिन वह रीजनल सैन्टर बन कर रह गई क्योंकि न तो आस-पास के कॉलेजों को जोड़ा गया है और न ही कॉमर्स और विज्ञान की पढ़ाई वहाँ पर हो रही है। वहाँ पर न ही तो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है और न ही स्टाफ है। मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मीरपुर यूनिवर्सिटी के लिए फंड और बढ़ाया जाये क्योंकि उसके लिए केवल 18 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जो कि पूरे हरियाणा में सभी यूनिवर्सिटीज में सबसे कम है। हमारे क्षेत्र में टेल तक नहरी पानी नहीं पहुंचता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि टेल तक नहरी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी और अन्तिम बात बताना चाहता हूं कि रिवाड़ी अहीरवाल क्षेत्र देश के सैनिकों के प्रथम स्वतंत्रता सैनानी राव तुलाराम से लेकर रिजांग ला की लड़ाई की अगर मैं चर्चा करता हूं तो 1800 फुट की ऊँचाई पर माइनस 40 सैल्सियस डिग्री में जब सब कुछ जम जाता है वहां अहीरवाल के 156 योद्धाओं ने वर्ष 1962 में अभूत पूर्व लड़ाई लड़ी। ऐसी लड़ाई लड़ी जो विश्व में कीर्तिमान है उसके मुकाबले की लड़ाई ना भूतो ना भविष्यते। इतनी महान लड़ाई पहले कभी नहीं लड़ी गई और जब यह लड़ाई लड़ी गई तो उसमें यह देखा गया कि 156 जवानों के किसी के भी पीठ पर गोली नहीं लगी थी बल्कि उन जवानों ने अपनी छाती पर गोली खाई, उस ऊँचाई पर बिना हथियारों के लड़े, बिना कपड़ों के लड़े क्योंकि उस समय साधन नहीं थे। स्पीकर सर, चीन देश ने तो उस समय हमारे साथ धोखा किया था जिसके कारण उन 156 जवानों ने चीन के एक हजार लोगों को मारा और वहां से भगाया था। उस समय हमारी प्रसिद्ध गायिका ने एक गाना गाया था -

'ऐ मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ।'(शोर एवं व्यवधान)

देश की सुरक्षा की बात हो रही है अगर बजट पर भी यह बात मैं नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा। अगर यह ऐसे शहीदों की भूमि है तो मैं इस सदन से एक ही चीज मांगता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी रिवाड़ी में आए थे वहां रेलवे स्टेशन है और मैं वहां एक चीज की मांग करता हूं कि रिवाड़ी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाए। बाकी कुछ मिले या न मिले। अब मैं बजट पर दो

[श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास]

बात कहना चाहूंगा कि-

"मिले भरोसा सुराज का, सबका हो सम्मान, देश ईर्ष्या छोड़ कर, नेक करें सब काम। सभी दलों में प्रेम हो सबका रखें ध्यान, नियम पूर्वक सदन चले, बजट करे कल्याण। जय भारत।"

श्री सभापति : अब मैं वित मंत्री जी को बजट 2015-16 के अनुमानों के उत्तर देने की अनुमति देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने सभी दलों को बोलने का समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान) ढुल साहब, आपकी पार्टी के लगभग सभी लोग बोल चुके हैं। जो विपक्ष का समय निर्धारित किया था वह उससे ज्यादा बोल चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैडम किरण चौधरी जी 39 मिनट तो आप बोले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 2015-16 के बजट पर जो चर्चा हुई । हरियाणा के इतिहास में बजट पर इतनी लम्बी चर्चा कभी नहीं हुई । इस विधान सभा में कभी भी बजट पर इतनी लम्बी चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : दलाल साहब, आपके कट मोशनज लगे हैं आप उन पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : सभापति महोदय, सदन का समय बढ़ाया जाए! हमें अभी बजट पर बोलना है। हमें स्पीकर साहब ने कहा था कि आपको बोलने के लिए 25 मिनट दे देंगे लेकिन हमें मिली केवल पांच मिनट। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : सदन का समय बढ़ाया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय सभापति महोदय, --- (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : सभापति महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। You have assured us कि आपको बोलने का समय दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : सभापति महोदय, मैं भी बोलना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : विपक्ष के साथियों के जो नाम मुझे बोलने के लिए दिए गये थे मैंने उनको बुलवा दिया है । (शोर एवं व्यवधान) बहन जी, आप सबसे ज्यादा बोली हैं ।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय सभापति महोदय, -- (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये बोलने के लिए हरेक मैम्बर को कैसे टाईम मिल सकता है सभी पार्टियों के लिए बोलने से पहले समय निर्धारित किया गया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कैप्टन अभिमुन्य : सभापति महोदय........(शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : सभापति महोदय......... (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : जो नाम प्रतिपक्ष नेता की तरफ से और कांग्रेस विधायक दल की नेता की तरफ से बोलने के लिए आये थे। उनको मैंने बुलावा दिया हैं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज सभी बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्दर सिंह संधू : सभापति महोदय........(शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : संधू जी, प्लीज बैठ जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : सभापति महोदय, अभी तक मुझे बोलने का मौका नहीं दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय.......(शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : करण दलाल जी, प्लीज बैठ जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यू : सभापति महोदय, विपक्षी के पार्टियों के नेताओं ने अपनी तरफ से बजट पर अभिव्यक्ति की है इसका मतलब माननीय सदस्यों को अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की अभिव्यक्ति पर भरोसा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) क्या विश्वास नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, सभी पार्टियों को बराबर समय दिया गया था। क्या वे अपने-अपने दल में समान बंटवारा नहीं कर सकते थे? (शोर एवं व्यवधान) क्या अपने-अपने दल में न्याय नहीं कर सकते थे? (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, ये लोग चेयर की तरफ उंगली उठाकर चेयर को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कौन सी मर्यादा है ? (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, सीनियर सदस्यों ने नये सदस्यों को बोलने का समय ही नहीं दिया। पार्टी के सीनियर सदस्यों ने नये सदस्यों के साथ न्याय नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, इन्होंने नये सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया और सभापति महोदय की तरफ उंगली उठाकर बात कर रहें है। (शोर एवं व्यवधान) पहले अपने दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम कीजिए। यह कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : सभापति महोदय......... (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : कादियान जी, आप तो इस हाउस के सीनियर सदस्य हो। आपको सभी बातों की जानकारी है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज बैठ जाईये। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आजाद विधायकों को भी बोलने का मौका दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, जब आपने सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए पूरा समय दिया था तो समय-सारणी के हिसाब से समय का बंटवारा हुआ था। माननीय सदस्यों को बोलने के लिए पूरा मौका दिया गया था। विपक्ष को सत्ता पक्ष से ज्यादा समय दिया गया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने हाउस का समय बढ़ाने में उदारदिली दिखाई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी फिराकदिली का परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि उनके दल के नेताओं ने अपनी संकीर्णता के कारण से समय नहीं दिया तो इसमें न तो अध्यक्ष महोदय की गल्ती है और न ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गल्ती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाईये । जब कट मॉशन आयेगा तो उस समय बोलने का मौका दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से......... (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो टैक्स लगाया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ हिम्मत है तो सुनिये । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य फिर हिम्मत की बात करते हैं। इनका अहंकार आज तक मिटा नहीं है। रस्सी तो जल गई है परन्तु बल अभी तक नहीं गया। अपने अहंकार में आकर फिर हिम्मत की बात करने लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इनको सावधान कीजिए। (शोर एवं व्यवधान) हम बार-बार इनकी धमकियों को स्वीकार करने वाले नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) हमारे अन्दर यदि हिम्मत थी तो आज हम इस महान सदन के सदस्य हैं। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को अपने दल के नेता से बात करनी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आपकी पार्टी ने ही फैसला किया हुआ है कि श्रीमती किरण चौधरी आपके विधायक दल की नेता हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य श्रीमती किरण चौधरी को विधायक दल का नेता नहीं मानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का हक और अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी पार्टियां अपना-अपना नेता निश्चित करती हैं। कांग्रेस हाई कमान ने श्रीमती किरण चौधरी को आपके विधायक दल का नेता बनाया है। मैडम किरण चौधरी ने स्वयं का और मैडम गीता भुक्कल जी का नाम बजट पर बोलने के लिया दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने आपको छोड़कर कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो समय सारणी तय हुई है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के सदस्य 60 मिनट बजट पर बोलेंगे। अभी माननीय सदस्य श्री उदय भान जी के बोलने से पहले कल मैडम किरण 1 घण्टा 39 मिनट बोली । (शोर एवं व्यवधान) 12 मिनट श्री उदय भान जी बोले। मैडम किरण चौधरी आपकी पार्टी के सदस्यों को बोलना था 60 मिनट और बोले 1 घण्टा 39 मिनट।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने के समय के बीच में बहुत टोका-टाकी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम, यह बात तो मैंने आपकी स्वीकार कर ली है कि आपके बोलने के समय टोका-टाकी हुई है। (शोर एवं व्यवधान) यदि 20 मिनट टोका-टाकी के निकाल देते हैं तो भी आपने बहुत ज्यादा समय लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे अलावा मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम दूंगी उन माननीय सदस्यों को जरूर बजट पर बोलने का मौका दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम जी, टाइम की मैनेजमैंट के साथ-साथ आपको माननीय सदस्य निश्चित करने पड़ेंगे कि कौन सा सदस्य व कितने समय तक, किस विषय पर बोलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के ऊपर टैक्स लगाये जा रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, क्या आपको अपने नेता पर विश्वास नहीं है, वो ये बातें नहीं बता सकते ? मैडम गीता भुक्कल जी बोली वो नहीं बता सकती थी ? श्री उदय भान जी बोले वो ये बातें नहीं बता सकते थे ? (शोर एवं व्यवधान) दलाल जी, यदि आपके नेता आपके नाम की सिफारिश करती तो दूसरे सदस्य की जगह आपको जरूर बजट पर बोलने के लिये समय मिलता। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, ये लोग माननीय सदस्यों को कह दो कि मुझसे अलग से मिलें, इनको डील करना मुझे अच्छी तरह से आता है। मैं इनके सारे वहम निकाल दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं कहना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य फालतू बोलते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को बोलने का समय नहीं देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, ये लोग सदन का समय बर्बाद करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं श्री करण सिंह दलाल जी के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिये 5 मिनट का समय देने को कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाँ, कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का समय नहीं दिया है। मैं सुबह से बोलने के इंतजार में बैठा हुआ हूं परंतु आपने हमारा समय भी भाजपा के सदस्यों को दे दिया है। अगर आप हमें बोलने का समय नहीं देंगे तो मैं सदन में नहीं रहूंगा और सदन का बहिष्कार करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वॉकआउट करके सदन से बाहर जाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, ये लोग सदन से भागना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव के ऊपर जो लम्बी चर्चा हुई है और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध सरकार.......... (शोर एवं व्यवधान) मुझे स्पीकर साहब ने बोलने के लिए समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब श्री अभय सिंह चौटाला बोलेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : .... (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, यह विपक्ष के साथ ज्यादती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो मैम्बर नहीं बोल पाए हैं उन्हें डिमांड पर या कट मोशन पर बोलने का समय दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान) हमने सदन के लिए 14 सिटिंग फिक्स कर दी हैं, आप तो केवल 7 सिटिंग में ही काम खत्म कर देते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, आपने वायदा किया था कि आप हमें बोलने का समय दोगे। आपने 14 सिटिंग फिक्स तो कर दी हैं परंतु हमें बोलने तो दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ एक लाइन बोलनी है इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष जी, ये एक लाइन पर ही 20-25 मिनट लगा देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो 90 के 90 विधायकों को बोलने का समय दे रहा हूं परंतु आप तो 45-46 विधायकों को ही बोलने का समय देते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री महोदय ने बोलना शुरू कर दिया है और अब विपक्ष नहीं बोल सकता । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, फाइनैंस मिनिस्टर का रिप्लाई शुरू हो चुका है । अब बीच में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है । इन्होंने जो कुछ कहना था ये कह चुके हैं । अब इन्हें सुनना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष जी, आपने इतना टाईम बढ़ा दिया है और इसके बाद भी ये कहते हैं कि आपने समय नहीं दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष जी, यह हमारे वित्त मंत्री की गरिमा का सवाल है । इन्हें बोलने दिया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, फाइनैंस मिनिस्टर का रिप्लाई शुरू हो चुका है । Speaker Sir, you were kind enough. You have given sufficient time to every party to speak, now there is no need. अब आप ने फाइनैंस मिनिस्टर को बोलने का मौका दे दिया है और ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। ये बाहर भागने का बहाना चाहते हैं । इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि विपक्ष को ज्यादा बोलने का समय मिला है और रूलिंग पार्टी को कम समय मिला है। भाजपा को केवल 198 मिनट का समय दिया गया है और विपक्ष को 236 मिनट का समय मिला है। फिर भी आप कहते हैं कि हमें कम समय दिया गया है।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, इनैलो तो भाजपा की बी टीम है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, इनैलो तो भाजपा की बी टीम है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, इन्होंने तय कर रखा है कि इन्होंने आज जवाब नहीं सुनना है। ये सुबह से ही तय करके आए हैं कि हमने आज सदन से वॉक-आउट करना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी तो मनी बिल और एप्रोप्रिएशन बिल भी आएगा............ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाईये। दलाल साहब आपको फिर बीच में मौका दे देंगे। आपकी केवल एक लाइन ही तो है। अब विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला बोलेंगे।

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, I want read only one line. (Interruption)

श्रीमती किरण चौधरी : .... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बजट पर चर्चा का विषय शुरू हुआ था, उस समय इन्होंने स्वयं सदन में खड़े होकर यह कहा था कि हर विधायक को 5-5, 7-7 मिनट बजट पर बोलने के लिए जरूर मिलने चाहिएं । उस समय मैंने तो बल्कि इनको यह कहा था कि हर सदस्य को 5-5, 7-7 मिनट बजट पर बोलने के लिए एक्सट्रा मिलने चाहिएं । लेकिन अब भी कुछ माननीय सदस्य बजट पर बोलने के लिए रह गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन का समय आधे घण्टे या एक घण्टे के लिए और बढ़ा दें ताकि सभी माननीय सदस्य बजट की चर्चा में भाग ले सकें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य बिना मतलब के बार-बार हमारी पार्टी को बी-टीम की संज्ञा दे रहे हैं और बिना मतलब के शोर मचा रहे हैं। इनको शोर नहीं मचाना चाहिए ताकि एक आध मिनट और बोलने का किसी सदस्य को मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बैठिये ।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं सिर्फ एक लाईन कहना चाहता हूं ।

वित्त मन्त्री कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रति पक्ष ने जो बात कही है वैसे तो यह रिकार्ड की बात है और मैं अपनी कही हुई बात कभी भूलता नहीं हूं। चौटाला साहब ने इस बारे में प्रस्ताव जरूर दिया था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने उच्च आसन पर बैठकर सभी पार्टियों का बोलने का समय तय किया था। अब किस-किस पार्टी को कितने समय के लिए बुलवाना यह जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष महोदय या माननीय सभापति महोदय की नहीं है बल्कि यह जिम्मेदारी सभी दल के नेताओं की होती है। सदन में पार्टीयों/नेताओं के साथ समन्वय की कमी या कोई न्यायपूर्ण वितरण की कमी है उसके लिए न तो सदन के नेता, नही सत्ता पक्ष और नहीं सभापति या अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार नहीं है। ये अपनी गलतियों का दोष अपनी कमियों का दोष मेहरबानी करके न तो सत्ता पक्ष पर डालें और न ही अध्यक्ष महोदय पर डालें।

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, I want to read only one line.

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप श्री करण सिंह दलाल जी को उनकी एक लाइन पढ़ने के लिए अवश्य समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, दलाल साहब, आप अपनी एक लाईन पढ़िये। अब तो मंत्री जी ने भी इस बारे में सिफारिश कर दी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : धन्यवाद सर। सर, यह एक बुक है Statement of Fiscal Policy and Disclosures इसमें इन्होंने लिखा है : The State Government had decided to levy 5% cess on the VAT and divided among the Urban Bodies. यह सैश टैक्स नहीं है तो और क्या है और सरकार कह रही है कि बिना टैक्स का बजट हरियाणा प्रदेश की जनता को दे रहें हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठ जाईये आपने अपनी एक लाइन को पढ़ दिया है।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी आप बोलने का समय दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, आप बैठिये, अभी मंत्री जी बोल रहे हैं । आपको बोलने के लिए बाद में समय दे दिया जायेगा ।

कैप्टन अभिमन्यू : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे फाजिल और विद्वान दोस्त ने अपनी जानकारी के अभाव में सदन का इतना कीमती समय खराब किया इस बात की मुझे हैरानी है। मैं जब इस सदन में नहीं आया था तब मैं इनको बहुत विद्वान मानता था। लेकिन इन्होंने सदन में मुझे गलत साबित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कही हुई अपनी बात पर अब भी कायम हूं। जो बात मैंने पहले कही हैं उसी बात पर मैं अब भी कायम हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2015-16 के बजट पर जिस प्रकार से ऐतिहासिक चर्चा हुई इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं कि हरियाणा के इतिहास में बजट अभिभाषण पर शायद ही इतनी लम्बी चर्चा हुई हो। शायद ही कभी इतने ज्यादा सदस्यों ने उस बजट की चर्चा में हिस्सा लिया होगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस महान सदन के सभी माननीय सदस्यों ने बजट के अभिभाषण पर न केवल अपनी टीका-टिप्पणी की है, न केवल उसकी आलोचना की है, न केवल उसकी समीक्षा की है परन्तु जहां-जहां उनको उचित लगा उन्होंने अपने अपने तरीके से उसकी सराहना करने का काम भी किया है। (विघ्न)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, आप बैठिये, अभी मंत्री जी बोल रहे हैं। आपको बोलने के लिए बाद में समय दे दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) अब जय प्रकाश जी बोलेगे।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। प्रदेश का नाश हो गया और लोगों ने प्रदेश को लूट खाया। आपने मुझे पहले बोलने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। सरकार ने जो जैविक खाद पर वैट कम किया है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि चूंकि कृषि-उत्पादन में डीजल प्रयोग में आता है, इसलिए डीजल पर जो वैट लगाया गया है उसको वापस ले लिया जाये, बेशक ट्रॅास्पोर्ट व इंडस्ट्रीज़ आदि पर वैट कम न करें क्योंकि डीजल पर वैट लगाने से किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता अवश्य दे। इसके लिए कोई कार्ड या कॉपी वगैरह बनाई जा सकती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहता हूं। वह यह है कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने भाषण को अनावश्यक रूप से लंबा कर रहे हैं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं रहस्योद्घाटन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के क्षेत्र में नीलम यूनिवर्सिटी में करोड़ों रूपये का फर्जीवाड़ा कैथल में चल रहा है जिसको मैं उजागर करना चाहूंगा। इनकी पार्टी के कैथल से विधायक श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की इस यूनिवर्सिटी के अंदर गरीब दलितों का व हरिजन भाईयों का ऐडमीशन तो 5000 की संख्या में दिखाया गया है लेकिन वास्तव में वहां पर इस वर्ग के केवल 500 लड़के ही अध्ययनरत हैं। इस मामले में डिस्टैंस एजुकेशन कार्यक्रम चलाने हेतु भी सरकार से कोई इजाजत नहीं ली गई है। मैं इस तरह के फर्जीवाड़ों के विरूद्ध लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर आया हूं। बिजली के बारे में बताना चाहूंगा कि गरीब किसान लोगों के तो बिजली के बिल न भरने के कारण तुरंत कनैक्शन काट दिये जाते हैं लेकिन श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला पिता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जिनका 45,112/-रूपये का बिजली का बिल बकाया है, उनका बिजली का कनैक्शन क्यों नहीं काटा जाता है ? केवल गरीबों, किसानों और मजदूरों के बिजली के कनैक्शन तुरंत काट दिये जाते हैं। इससे ज्यादा अन्याय जनता के साथ और क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, कृपया अब आप बैठिए ।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने अभी अभी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक फर्जीवाड़े का जिक्र किया है, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस फर्जीवाड़े की जाँच कब तक करवाई जायेगी ? मेरी यह भी प्रार्थना है कि हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पंजाब राज्य के समान वेतनमान दिये जायें। (विघ्न) जब श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला लोक निर्माण मंत्री होते थे, उस समय कैथल विधान सभा क्षेत्र में 168 करोड़ रूपये खर्च किये गये तथा विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया जिस वजह से ये आज यहाँ बैठे हैं । (हंसी) आप भी उनकी लाइन पर मत चलना अन्यथा आप भी यहाँ आ जाओगे।

Shri Kuldeep Sharma : Speaker sir, I want to speak just one line.

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, कृपया जल्दी से अपनी बात बोलें । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldeep Sharma : Sir, Hon'ble Finance Minister recently went to Hayward for some kind of attachment course and the whole of the Haryana was looking with excitement that the Finance Minister having been enriched his knowledge with Hayward and the same would be reflected in the Budget (interruptions) Hon'ble Minister just a last line. You would also like it. (Interruptions).

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण योजनाबद्ध तरीके से नहीं बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, कृपया आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने सिर्फ एक लाइन बोलने की इजाजत मांगी थी लेकिन इन्होंने फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Shri Kuldeep Sharma : * * * *

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, आप बैठिए यदि अब सदन में कुलदीप जी बोलें तो, उनकी बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलवन्त राम बाजीगर (गुहला) (अ0जा0) : अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए में आपका आभारी हूं। मैं वर्तमान सरकार की अनुसूचित जातियों के संबंध में कल्याणकारी नीतियों के बारे में उल्लेख करते हुए सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी कुल जनसंख्या का 20.17 प्रतिशत है तथा पिछड़े वर्ग की जनसंख्या लगभग 30 प्रतिशत है जोकि कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा बनता है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए इस वर्ष 368.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 3641.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 2015-16 के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता को 5295.11 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्लोगन "सबका साथ सबका विकास" के लिए प्रयासरत है। अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत राज्य की आबादी के अनुरूप 20 प्रतिशत से अधिक बजट का प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के विकास एवं उत्थान के लिए रखा गया है। वर्ष 2014-15 के लिए राज्य की कुल बजट व्यवस्था 21520.15 करोड़ रुपये में से 4064.80 करोड़ रुपये (18.89 प्रतिशत) अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत रखे गये हैं। इसमें से 1906.43 करोड़ (15.62 प्रतिशत) रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुरूप पूर्ण राशि खर्च की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुसूचित जाति के छात्रों की सुविधा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत आधार लिंक के साथ-साथ बिना आधार के भी राशि वितरण का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने आते ही पी0 राघवेन्द्रा राव कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए सभी श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) में आरक्षण को राज्य मंत्री मण्डल ने अनुमोदन कर दिया है। अत : मैं इस कार्य के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ से सरकार का धन्यवाद करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इसके दिशा-निर्देश जारी किये जायें ताकि अनुसूचित जाति के सभी वर्गों को लाभ मिल सके। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 26-02-2015 को हुई जिसमें अपराध के आंकड़ों की समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में भी सख्त निर्देश दिये कि बिना किसी भेदभाव के कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उपरोक्त कानून को सख्ती से लागू किया जाए ताकि पीड़ितों को समय पर लाभ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं अनुसूचित जाति के लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवाओं की लड़कियों की शादी में शुगन राशि में इजाफा करके 41000 हजार रुपये कर दये गये हैं और यह भी निर्देश दिये गये हैं कि शगुन की राशि एक सप्ताह में प्रदान की जाए। अन्तर्जातीय विवाह योजना को प्रोत्साहन देने के लिए (प्रोत्साहन राशि) 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिए गए हैं। मैं इस सराहनीय बजट के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़े समुदाय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं कैप्टन अभिमन्यु जी का

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

**चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

धन्यवाद करता हूं कि जिसने सारे वर्गों व पूरे प्रदेश के हित को देखते हुए बजट पेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने वर्षों पुरानी कन्या महाविद्यालय की मांग को मात्र दो महीने में ही पूरा कर दिया जोकि पिछली सरकार की अनदेखी के कारण, मेरी बहन-बेटियों को शिक्षा ग्रहण के लिए 40 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। मैं इसके लिए हल्का गुहला की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं।

अब मैं अपने क्षेत्र गुहला की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जोकि पिछली सरकारों की अनदेखी का नतीजा है।

1. अध्यक्ष महोदय, गुहला चीका शहर में से जीन्द/कैथल/पटियाला रोड, जो हाईवे है वह चीका शहर के बीच से निकलता है और ज्यादा भीड़ के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं इसलिए मेरे शहर की चारों सड़कों को नगरपालिका की सीमा तक फोरलैन बनाई जाये और गुहला चीका में बाईपास बनाया जाए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

2. अध्यक्ष महोदय, गुहला हल्का कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहां पर मिट्टी जांच के लिए लैब नहीं है तथा किसानों को मिट्टी जांच के लिए करनाल या हिसार जाना पड़ता है और इसलिए मेरे क्षेत्र में मिट्टी जांच लैब खोली जाए।

3. (I) अध्यक्ष महोदय, मेरे गुहला क्षेत्र में लगभग 3 लाख आबादी है और जिसमें 108 गांव और 240 डेरे हैं परन्तु सिविल अस्पताल केवल एक ही है तथा आबादी को देखते हुए सीवन उप-मण्डल में एक और सिविल अस्पताल खोला जाए।

(II) सर, सिविल अस्पताल गुहला में अल्ट्रासाउंड/डिजिटल एक्सरे मशीनें भी नहीं हैं तथा मेरा अनुरोध है कि जल्दी मशीनों को व्यवस्था की जाए ताकि मरीजों को भटकना न पड़े।

अध्यक्ष महोदय, गुहला में सिर्फ तीन ही पी0एच0सी0 हैं, (खरका, भागल, कांगथली) परन्तु आबादी को देखते हुए पांच पी0एच0सी0 और खोली जाएं जिससे आस-पास के लगभग 15-15 गांव को लाभ मिल सके, उन गांव के नाम इस प्रकार हैं :- दाबा-चाबा, हरनौली, खानपूर, भूसला और कल्लर माजरा।

4. अध्यक्ष महोदय, हमारे घग्गर पार इलाके के लगभग 20 गांव ऐसे हैं जहां नीचे का पानी बिल्कुल खारा व तेजाबी है जिसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ फसलों पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से 1.1.2014 से कैंसर के रोगियों की संख्या 27 तथा काला पीलिया रोगियों की संख्या 24 हो गई है। मेरी अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है कि या तो इन गांवों में नहरी पानी या फिर R.O. का प्रबंध किया जाए ताकि भविष्य में इन रोगों पर अंकुश लगाया जा सके।

5. अध्यक्ष महोदय, गुहला में सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं इसलिए 100 सरकारी आवास बनाये जायें।

6. अध्यक्ष महोदय, गुहला क्षेत्र की काफी समय से चली आ रही सब डिपो की मांग को आज तक पिछली सरकारों ने पूरा नहीं किया ।

7. इस सरकार से लोगों को उम्मीद भी है और मैं भी अनुरोध करता हूं कि इस मांग को

[श्री कुलवन्त राम बाजीगर]

जल्द ही पूरा किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो अपने क्षेत्र की समस्या रखने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी इन मांगों को जल्दी ही पूरा किया जायेगा।

8. अध्यक्ष जी, एक और बड़ी गम्भीर समस्या है । मेरे हल्के में मेरे क्षेत्र में कोहली खेड़ा व स्योशर जंगल पड़ता है। उसमें जो जंगली जानवर हैं जैसे नीलगाय, सुअर, हिरण आदि जो फसल को उजाड़ देते हैं, जमींदारों की पकी पकाई फसल भी खराब कर देते हैं।

मेरा आग्रह है कि जंगल के चारों तरफ जाल लगाया जाए जिससे लोगों की फसल के साथ-साथ जंगल से लकड़ी भी चोरी नही होगी, इस पर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। जयहिन्द।

***श्री विशम्बर सिंह बाल्मीकि (बवानी खेड़ा) (अ0ज0)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में 'सबका साथ सबका विकास' स्पष्ट नजर आता है। जैसे कि पेश किए गए बजट 2015-16 में ऐसा कोई नया कर नहीं लगाया है, बल्कि वैट दर को घटाकर 5 प्रतिशत कम करना एक सहरानीय कदम है जिससे कि जनता पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी एवं सहकारिता विकास के लिये 2,636.65 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह परिव्यय वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान से 10.10 प्रतिशत अधिक है। पशुचिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के एक नये परिसर का निर्माण किए जाने की योजना है। हमारी सरकार गरीबों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान को समर्पित है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, भूख की कोई जाति नहीं होती और निराशा का कोई बिगुल नहीं होता। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में हमारे प्रेरणा श्रोत पं0 दीन दयाल उपाध्याय ने हमें कतार में अन्तिम व्यक्ति की भलाई व प्रगति (अन्त्योदय) के प्रति सचेत किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए 368.79 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है, इसमें 213.03 करोड़ रुपये योजनागत परिव्यय शामिल है। यह योजनागत परिव्यय वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान से 6.73 प्रतिशत अधिक है। इससे अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए और अधिक बल मिलेगा। हमारी सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी स्थानीय निकाय, श्रम एवं रोजगार विभाग के विकास के लिये 27,201.27 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। यह परिव्यय मौजूदा वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमानों से 16.93 प्रतिशत अधिक है, जिससे वर्णित क्षेत्रों में अत्यधिक विकास होगा। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं तथा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि निम्नलिखित मांगों को स्वीकार करें। बवानी खेड़ा विधानसभा

* चेयर के आदेशानुसार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया गया।

क्षेत्र में सुन्दर नहर निकलती है, इस नहर से वर्ष 1996 से पहले पानी 15 दिन चलता था, लेकिन बाद में इसके जल वितरण को घटा कर केवल एक सप्ताह कर दिया गया । मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस नहर का पानी पुन : 15 दिन लगातार चलाने की मांग स्वीकार की जाये। बवानी खेड़ा को उप-मण्डल का दर्जा दिए जाने व मार्केट कमेटी बनाए जाने की मांग स्वीकार करें। शिक्षा से सम्बन्धित मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय बनाने के लिये गांव प्रेम नगर की ग्राम पंचायत ने 170 एकड़ भूमि 99 वर्ष के लिये पट्टेनामें पर दी हुई है व जितने भी मापदण्ड हैं वे पूरे हैं। ज्ञात्व है कि गांव निमड़ीवाली द्वारा मापदण्ड पूरे न होने के कारण विभाग ने प्रस्ताव पहले ही रद्द किया है और विश्वविद्यालय को गांव प्रेम नगर में बनाने से तीन विधानसभा क्षेत्रों का शिक्षा क्षेत्र में जुड़ाव बनता है तथा पूरा भिवानी जिला लाभान्वित होगा। गांव खरक कलां में पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 बनाई जाये व गांव कलिगां में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खण्डर हो चुकी है तथा उक्त डिस्पेंसरी के डॉक्टर व अन्य कर्मचारी पशु अस्पताल में बैठ कर अपना कार्य करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि खरक कलां, खरक खुर्द, कलिंगा, सिरसा, रिवाड़ी और सैया ढाणी हरसुख पांच ढाणियां पी0एच0सी0 खरक के अन्तर्गत आती है। इन्हें पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 तक अपग्रेड का प्रस्ताव स्वीकार करें तथा वर्णित की गई सभी मांगों को भी स्वीकार करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री ओमप्रकाश बरवा (लोहारु)** : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के लोहारु की लगभग सभी सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी होती है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सदन इन सभी टूटी-फूटी सड़कों को ठीक करवाने का काम करेगी जोकि निम्नलिखित है :-

1. गांव सोहासड़ा से लेकर लोहारु की सड़क की मरम्मत की जाए।
2. गांव फरटिया भीमा के एप्रोच रोड की मरम्मत करवाई जाए।
3. गांव गढ़ोली खुर्द से बहल तक की सड़क मरम्मत करवाई जाए।
4. कस्बा सिवानी से कालोद गांव तक की सड़क की मरम्मत करवाई जाए।
5. गांव पहाड़ी से लेकर बरालू गांव तक सड़क की मरम्मत करवाई जाए।
6. गांव ढिगावा जाटान से गांव ढिगावा शामियान तक सडक की मरम्मत करवाई जाए।
7. गांव ढाणी टोड़ा से ढाणी मनसुख तक सड़क की मरम्मत करवाई जाए।
8. गांव बड़वा में नैशनल हाइवे नं0 65 की मरम्मत की जाए।
9. गांव गिगनाउ से बारवास तक रोड की मरम्मत करवाई जाए।
10. मेन रोड गांव पातवान तक रोड की मरम्मत करवाई जाए।
11. बड़वा से गांव गायड़ तक रोड की मरम्मत करवाई जाए।

* चेयर के आदेशानुसार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया गया।

[श्री ओमप्रकाश बरवा]

12. गांव किकराल से गांव नलोई तक रोड की मरम्मत करवाई जाए।

13. सिवानी से गांव ढाणी रामजस तक रोड की मरम्मत करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के लोहारू में बहुत से गांव ऐसे हैं जो पक्की सड़क से जुड़े हुए नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्हें भी पक्की सड़क से जोड़ा जाये :-

1. बहल से ढाणी केहरा (चेहड़ कलां) तक लगभग 5 किलोमीटर लम्बे कच्चे रास्ते पर पक्की सड़क बनवाई जाए।

2. लोहारू कस्बा से हाजमपुर गांव तक कच्चे रास्ते पर पक्की सड़क का निर्माण करवाया जाए।

3. बाढड़ा मुख्य सड़क से ढिगावा मण्डी तक लगभग 2 किलोमीटर लम्बा बाईपास (सड़क) बनवाया जाए।

4. गांव गुढढ़ा से बिधवान तक नई सड़क का निर्माण किया जाए।

5. लोहारू कस्बा से गांव जगराम बास तक नई सड़क का निर्माण किया जाए।

6. नलाई गांव से गुरेरा गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाए :-

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के लोहारू की मुख्य मांगे हैं उन्हें भी पूरा किया जाए।

1. लोहारू कस्बा में राजकीय महिला महाविद्यालय की ग्रांट खाते में आई हुई है उसे उच्च शिक्षा विभाग को पुरातत्व विभाग से NOC दिलवाई जाए।

2. कस्बा सिवानी में राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाया जाए।

3. कस्बा सिवानी में हरियाणा रोडवेज का सब डिपो बनवाया जाए।

4. कस्बा सिवानी में स्थित सामान्य अस्पताल में रिक्त पड़े पदों पर चिकित्कों की नियुक्ति की जाए तथा अस्पताल में एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनों का प्रबंध किया जाए।

5. लोहारू व बहल ब्लॉक में खेती व गांव में बिजली के ढीले तारों को टाईट किया जाए व लोहे के खम्भों को बदला जाए।

6. सिवानी तहसील के चने की बरानी फसल की गिरदावरी करवा कर मुआवजा दिया जाए।

7. आवारा पशुओं का स्थाई समाधान करवाया जाए।

8. गांव रुधाणा में राजकीय पशु अस्पताल में चिकित्सक की नियुक्ति की जाए।

9. कम्प्यूटर शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा के लिए नई नीति बनाई जाए।

10. नैशनल हाईवे नं0 52 पर गांव बड़वा से लेकर गांव झुम्पा तक अनेक खतरनाक मोड़ हैं उनको ठीक किया जाए।

11. ट्यूबवैल कनैक्शन फिर से चालू किए जाएं।

12. हल्का लोहारू में स्थित सभी माईनरों की मरम्मत की जाए व सभी की टेल तक पानी पहुंचाया जाए व लिफ्ट पंपों को ठीक करवाया जाए।

13. कांग्रेस सरकार ने अपने शासन काल में बागवानी स्कीम के तहत सब्सिडी योजना शुरू की थी जिसका फायदा किसानों को नहीं मिला। जो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच करवाई जाए।

***श्री अनूप धानक (उकलाना)** 1. उकलाना हल्के के गांव सिवानी बोलान में लड़कियों के स्कूल तथा उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है जिसके कारण उन्हें बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव की जनसंख्या 15000 है, उक्त विद्यालय का दर्जा बढ़ाकर बारहवीं तक किया जाए।

2. (क) बिठमड़ा स्कूल का दर्जा बढ़ाकर बारहवीं तक किया जाए।

(ख) गांव हसनगढ़ में लड़कियों के स्कूल का दर्जा बढ़ाकर बारहवीं तक किया जाए।

3. उकलाना हल्के में कोई आई0टीआई0 तथा पॉलीटैकनिक कॉलेज नहीं है। अत : सुरेवाला चौक पर आई0टी0आई0 व पॉलीटैकनिक कॉलेज खोला जाए।

4. उकलाना हल्के के गांव सरहेड़ा में मिडल स्कूल को अपग्रेड किया जाए।

5. उकलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पाबड़ा में पहले जेबीटी सेंटर को तोड़ दिया गया था। इसे दोबारा बनाया जाए।

6. अग्रोहा में बस अड्डे के लिए विभाग ने 2007-08 में दो एकड़ जमीन दी थी। अत: इस पर बस अड्डे का निर्माण किया जाए।

7. अग्रोहा में तहसील बनवाने के लिए वर्ष 2007-08 में सात एकड़ जमीन दी थी। अत: इस पर तहसील कार्यालय के भवन का निर्माण किया जाए।

8. उकलाना हल्के के गांव खेदड़ से भैणी बादशाहपुर वाले रास्ते पर सड़क निर्माण के लिए पत्थर बिछाया गया है परन्तु सड़क बनाने का कार्य बन्द कर दिया है। अत : उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र करवाया जाए।

9. उकलाना निर्वाचन क्षेत्र की निम्नलिखित सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। इनकी मरम्मत करवाई जाए :-

1. उकलाना से कुन्दरपुरा सड़क।

2. गांव खेदड़ से दौलतपुर सड़क।

3. गांव बधावड़ से ढांड सड़क।

4. कनोह से किरमारा सड़क।

5. गांव साहू से चमारखेड़ा सड़क।

---

* चेयर के आदेशानुसार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया गया।

[श्री अनूप धानक]

6. गांव साहू से खैरी सड़क।

7. गांव पाबड़ा से साहू।

8. बुढ़ाखेड़ा बाईपास से जी0टी0 रोड।

9. दौलतपुर से फरीदपुर।

10. बिठमड़ा से गैबीपुर तथा

11. साभियाना से चमारखेड़ा सड़क।

12. उकलाना वार्ड नं0 13 में गन्दगी भरी होने के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता। उक्त तालाब के स्थान पर पार्क का निर्माण करवाया जाए।

13. सुरेवाला से उकलाना सड़क को चौड़ा करके डिवाईडर बनवाने का कष्ट करें।

14. गांव हसनगढ़ से कल्लर भैणी सड़क के बीच से जो कच्चा रास्ता लितानी मोड़ व कल्लर भैणी के बीच में नेशनल हाईवे पर मिलता है, उसे पक्का करवाने का कष्ट करें।

15. उकलाना मंडी दो भागों में बंटी होने के कारण रेलवे लाईन पर अन्डर पास बनावाने का कष्ट करें।

16. उकलाना हल्के के गांव सौथा से खेड़ी जालब तक के कच्चे रास्ते को पक्का करवाने का कष्ट करें।

17. उकलाना हल्का के गांव बालक से संदोल तक के कच्चे रास्ते को पक्का करवाने का कष्ट करें।

18. उकलाना हल्के के गांव सवौथा में जलघर में मौजूदा पानी की एक डिग्गी पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों के पीने के स्वच्छ पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिग्गी बनाने का कष्ट करें।

19. उकलाना गांव के वार्ड नं0 11, 12 तथा 13 में सीवरेज की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

20. उकलाना के गांव अग्रोहा में बूस्टिंग स्टेशन के लिए दी गई जमीन पर अभी तक कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ। अत : इस पर कार्य आरम्भ करवाया जाए।

21. उकलाना मण्डी के सीवरेज प्लांट का गांव बुढ़ाखेड़ा में उद्घाटन के बाद कार्य शुरु नहीं हुआ। उक्त प्लांट पर कार्य शुरु करवाया जाए।

22. खेदड़ थर्मल प्लांट के 10 किलोमीटर अधीन आने वाले गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाए, गांव निम्न प्रकार से हैं :-

1. गांव सरहेड़ा।

2. गांव गैबीपुर।

3. गांव खरकड़ा।

23. उकलाना हल्के के गांव की ढाणियों में बिजली उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

24. उकलाना हल्के की नहरों में महीनें में एक सप्ताह ही पानी आ पाता है जिसके कारण समय पर बिजाई और फसलें तैयार नहीं हो पाती। महीने में कम से कम दो सप्ताह पानी दिया जाए।

25. उकलाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जर्जर इमारत के निर्माण का कार्य शुरु किया जाए।

26. उकलाना नगर पालिका कार्यालय में कर्मचारियों के रिक्त पद हैं। उन्हें तुरन्त भरा जाए।

27. उकलाना मण्डी में पार्क बनाया जाए।

28. उकलाना हल्के के गांवों में मिनी बैंक की कोई व्यवस्था नहीं है। अत : निम्नलिखित गांवों में मिनी बैंक खोले जाएं।

1. गांव प्रभुवाला।

2. गांव सन्डौल।

3. गांव किराड़ा।

4. गांव ढांड।

5. गांव ज्ञानपुरा।

6. गांव बाड़ाखेड़ा।

7. गांव सुरेवाला।

8. गांव छान।

9. गांव नया गांव।

10. गांव कन्धुल।

11.गांव भैरी अकबरपुर, तथा

12. गांव सरहेड़ा।

29. गांव लितानी खण्ड उकलाना उप-मण्डल हिसार में गन्दे पानी की वजह से तालाब बन गया है जिसका पानी दूषित होने से बीमारियां फैलती जा रही है तथा पशुओं में भी लगातार बीमारियां फैल रही हैं, गन्दे पानी के इस तालाब की जगह कोई पार्क या चबूतरे का निर्माण करवाया जाए।

30. उकलाना मण्डी में महिला सामुदायिक केन्द्र बनाने का कष्ट किया जाए।

[श्री अनूप धानक]

31. उकलाना व अग्रोहा में बी0डी0पी0ओ0 के दो पद रिक्त पड़े हैं। इन्हें तुरन्त भरा जाए।

32. उकलाना हल्का के गांव बालक में स्टेडियम को दी गई 6.5 एकड़ जमीन पर स्टेडियम बनाया जाए।

33. उकलाना हल्के के गांव बधावड़ में स्टेडियम बनाया जाए।

34. उकलाना विधानसभा क्षेत्र में बहुत अधिक आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसल नष्ट होती है। इन आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए कोई योजना बनाई जाए।

35. अग्रोहा में बहुत से धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं। अत : अग्रोहा के स्थलों को सरकार के पर्यटन स्थल बनाए जाएं।

36. उकलाना में डिग्री कॉलेज खोला जाए।

37. बी0पी0एल0 कार्ड बनवाने के लिए सरकार दोबारा सर्वे करवाये।

38. उकलाना मण्डी में एक चौकी बनाई जाए। उकलाना मण्डी दो भागों में बंटी हुई है। अगर रेलवे लाईन से इस तरफ कोई घटना हो जाए और पुलिस को फोन किया जाए तो कई बार फाटक बंद होने के कारण घटना को अंजाम देकर मुजरिम भाग जाते हैं। अत : पुलिस को पी0सी0आर0 या तीन गाड़ी दी जांए। थोड़े दिन पहले उकलाना मण्डी में संजय जैन के मार्बल हाउस पर डकैती हुई। अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती तो मुजरिम पकड़े जाते।

39. मेरे गांव खेरी में बरसाती पानी निकासी की बड़ी समस्या है। स्कूल में पानी इकट्ठा हो जाता है, गली में भी पानी इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करवाया जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनराम्भण)

[15.00 बजे] वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यू) : अध्यक्ष महोदय, मैं पुन : आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि हरियाणा के इतिहास में इस महान सदन में शायद ही कोई ऐसा मौका आया होगा कि किसी बजट अभिभाषण पर इतनी लम्बी चर्चा हुई होगी और उस चर्चा पर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के साथियों ने शिरकत की होगी । अध्यक्ष महादेय, मैं सदन के सभी साथियों का, नेता प्रतिपक्ष का और विपक्ष के अन्य नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बजट के डॉक्यूमैंट का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। सभी साथियों ने मेरी उम्मीद और अपेक्षाओं से ज्यादा इसका बेहतर आंकलन, इसकी समीक्षा और इसकी आलोचना

की है। मेरे साथियों ने बजट पर अपने सुझाव या अपने क्षेत्र या अपने राजनैतिक इतिहास से प्रेरित मांगें इस सदन के पटल पर रखी हैं। मैंने अपनी तरफ से जो सकारात्मक सुझाव मुझे लगे, उनको नोट भी किया है और भविष्य के लिए उनको ध्यान में रखने का मैं विश्वास दिलाता हूं। जो सकारात्मक आलोचना मुझे सुनने को मिली है वह भविष्य के लिए निश्चित तौर पर एक दिशा निर्देश का काम करेगी ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं । अध्यक्ष महोदय, सदन के साथियों ने बड़ी मेहनत से इस बजट पर चर्चा की है। इस सारी चर्चा के दौरान एक विशेष बात पूरे सदन के वातावरण से उभर कर आई है कि जिन चुनौतियों के संदर्भ में यहां चिंताएं व्यक्त की गई हैं वह सबकी कॉमन थी। उन चिंताओं में पक्ष और विपक्ष में कोई अंतर्भेद नहीं था और चुनौतियों को समझने में भी कोई अंतर्भेद नहीं था। चुनौतियों का सामने करने की दिशा के बारे में भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं और उनकी प्रायरिटी के ऊपर भी अन्य विचार हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन की इस भावना से मैं अभिभूत हूं कि हरियाणा प्रदेश भविष्य में किस दिशा में जाए इस बात को लेकर सदन में सबकी एक चिंता थी कि हम अपने हरियाणा के इस बजट में जो रिवैन्यू डैफीसिट हो या जो बोरोइंग हो वह मर्यादा और सीमा से बाहर नहीं जाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि किसी किसी सदन में इस तरह का भाव उत्पन्न होता है। आज बहुत प्रेरणादाई वातावरण मेरे लिए बनकर आया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने चुनौतियां थी और उन चुनौतियों का ब्यान मैंने बजट के भाषण में दे रखा था। हमारे सामने चुनौतियां थी कि हमारा कृषि क्षेत्र कमजोर हो रहा है, प्राइमरी सैक्टर कमजोर हो रहा है और उसका सकल घरेलू उत्पाद में कंट्रीब्यूशन घट रहा है। हमारे यहां रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। मैन्युफैक्चिरिंग सैक्टर जो है वह डी ग्रोथ जोन की तरफ बढ़ रहा है। उन तमाम चुनौतियों के बीच और बढ़ते हुए कर्जे के बीच और हमारे फिसकल डैफीसिट के टारगेट की चुनौती के बीच, हरियाणा सरकार में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों ने जो सहयोग इस बजट को बनाने में दिया है, उनको रिकार्ड पर लाते हुए मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए उन चुनौतियों से पार पाने की हमने पूरी कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को हमने दो लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया है। इस बजट के जितने भी प्रावधान हैं वे इन दोनों लक्ष्यों से प्रेरित हैं कि हमारी जो आर्थिक उन्नति की दर है वह तीव्र हो। हमारे पूरे प्रदेश में विकास में और रोजगार के अवसरों में जो असमानता थी उस असमानता को दूर करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। इन दो चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमने बजट में अपने प्रावधान किए हैं। जैसा मैंने कहा कि इसके लिए बहुत सारे विकल्प थे। हम अपने कर्जे की जितनी सीमा है उसको उस सीमा के नजदीक पूरा ऊपर तक रखें या उससे कम रखते हुए या जितना उसका अधिक से अधिक उपयोग हम अपने प्रदेश के विकास में कर सकते हैं उतना उसका प्रयोग किया जाए और जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ग्रोथ कम्परोमाइज न हो इसके लिए दो रास्ते हमारे सामने हैं। एक तो हमें ग्रोथ करनी है दूसरा स्ट्रक्चरल जो कम्पोजिशन है जो करैक्शंज है वह करैक्शंज करने के दोनों काम हम साथ साथ लेकर चलेंगें। यह नहीं चल सकता कि हम कहें कि पहले वाले जितने गड्ढे हैं पहले उनको भरेंगें और फिर उसके ऊपर इमारत बनाएंगें। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनके साथ साथ हमें उन गड्ढों को भी भरना होगा और साथ साथ विकास को भी तेजी देनी होगी। उस उदेश्य से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाक्टर साहब, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने इस सदन की मर्यादाओं की चिंता की है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, प्लीज आप बीच में इंट्रप्ट न करें ।

[कैप्टन अभिमन्यु]

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, उन पर इस सदन की मर्यादाओं की चिंता करने की जिम्मेवारी रही है। उनका बैठे-बैठे बोलने का स्वभाव अभी भी नहीं जा रहा है, इससे हमें बड़ी हैरानी होती है। जिनके ऊपर सदन की मार्यादाओं की जिम्मेवारी रही हो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। हमारे वरिष्ठ साथी हैं जिनसे सभी नये सदस्य प्रेरणा प्राप्त करने के बारे में सोचते थे कि सदन में किस प्रकार का आचरण हो । लेकिन वे बार-बार रैनिंग कामेंट्री करेंगे तो नये सदस्य क्या सोचेंगे ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपको बजट पर बोलने के लिए पूरा अवसर दिया गया । आप 1 घंटा 39 मिनट बोले हो। आप प्लीज सदन को डिस्टर्ब न करें।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हमने बजट में हर पहलू का ध्यान रखा है। हमारे सामने फिसकल करैक्शंज करने की चुनौती थी । हमारे सामने फिसकल डेफीसिट को कम करने की चुनौती थी। उसके लिए हमने जो रास्ते चुने (विघ्न)

डा. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए । कादियान साहब, आपको बोलने के लिए पूरा अवसर दिया गया है। प्लीज आप बैठें। आप 1 घंटा 39 मिनट बोले हैं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, प्लीज आप उनका जवाब सुनें। आप अपनी बात कह चुके हैं। प्लीज, बैठें ।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट की कुछ प्राथमिकताएं हैं । हमने बजट के माध्यम से कोशिश की है कि जो हमारा प्लांड और कैपिटल एक्सपैंडीचर है उसमें पिछले 10 वर्षों से भयंकर इनकंसिसटैंसी थी। इस दौरान एक वर्ष तो 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाती है और अगले वर्ष गिर जाता है। ऐसा लगता है कि दूरदृष्टि के अभाव के कारण से कैपीटल एक्सपैंडीचर के अंदर कंसीसटैंसी नहीं थी । हमने भविष्य के लिए यह बजट 5 साल के विजन पेपर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको पहले साल में शुरूआत करने का एक आधार रखा है। हमने बजट में प्लांड एक्सपैंडीचर और कैपीटल एक्सपैंडीचर के कंपोनैंट को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे काबिल वित्तमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि प्लांड और कैपीटल एक्सपैंडीचर पिछले वर्षों में एक वर्ष ऊपर गया और अगले वर्ष नीचे आ गया। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा एक छोटा प्रदेश है यदि कभी अकाल पड़ गया तो नीचे-ऊपर हो जाता है। यह कभी कॉसटैंट नहीं रहता। अभी जैसे बे-मौसमी बरसात हो गई और किसानों की फसल बर्बाद हो गई हैं इससे भी असर पड़ता है और मौजूदा सरकार के समय में भी यह ऊपर-नीचे होगा।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत तौर पर मैं हुड्डा साहब की इज्जत करता हूं। उनके समय की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके बारे में सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके आम जन के समक्ष समीक्षा के लिए रखा है। उसमें जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलेगी और जो गलत बातें हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलेगी। उसमें जो

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

हमारे ध्यान में आया कि कुछ गलतियां सुधारने की जरूरत है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जनता ने हमें मैंडेट दिया है और पहले कांग्रेस की सरकार ने अपनी बुद्धि से जितना बेहतर हो सकता था कार्य किये होंगे। लेकिन एक सामान्य अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते जो सैद्धांतिक कमियां मेरे ध्यान में आती हैं उनको हरियाणा की जनता के हित में दुरूस्त करना इस महान सदन के बिहाफ पर मेरी जिम्मेवारी बनती है और वही हमने किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस बजट के माध्यम से जो प्लांड बजट का कम्पोनैंट है जिसको योजनागत खर्च कहा जाता है, कैपीटल एक्सपैंडीचर है जिसको ऐसट बनाया जाता है। जो समाज का ऐसट होता है। जैसे आज कोई कालेज बनाया जाता है या कोई पुल बनाया जाता है और उसका लाभ आने वाले 15-20 साल में मिलने वाला है। यदि उसका निरंतर खर्च एक तयशुदा दिशा के अंदर बनता रहेगा तो उसका लाभ हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इसी तरह की दुरूस्तीकरण का प्रावधान हमने बजट में किया है। हमने कुछ प्रायोरिटी एरियाज डिफाईन किए हैं कि कौन-कौन से क्षेत्र पिछड़ गए हैं, समय की क्या मांग है और कौन से क्षेत्र में तुरंत ध्यान देने की जरूरत है ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। जहां से राज्य के विकास को शुरू किया जा सके। हमने इन्फ्रास्ट्रैक्चर डिवैल्पमैंट एक मुख्य बिंदु आईडैंटीफाई किया है। हमने उसमें स्किल अपग्रेडेशन को भी एक मुख्य बिन्दु आईडैंटीफाई किया है और इसी प्रकार से हमने जैनरेशन ऑफ इम्पलॉयमैंट को भी उसमें एक मुख्य बिन्दु आईडैंटीफाई किया है। यह सब कैसे सम्भव होगा यह सभी कुछ हमने इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हमारी किसी भी बात के तारतम्य के अंदर किसी को भी कोई भेद नहीं मिलेगा। हमने इस बात का भी बजट के अंदर प्रावधान रखा है कि यह सब सम्भव होगा एग्रीकल्चर सैक्टर और एलाईड सैक्टर के अंदर इनवैस्टमैंट को बढ़ावा देकर। मैं एक बार पुनः यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कृषि और कृषि से सम्बंधित क्षेत्रों में इनवैस्टमैंट को बढ़ावा देकर। यह सम्भव होगा हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को उद्यम क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए नये उद्योग खोलने के रास्ते देते हुए माईक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राईजिज को जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके इस बजट के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की कोशिश की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा यह बजट प्रत्येक क्षेत्र की असमानताओं को दूर करते हुए विकास की गति में तेजी के साथ और आगे बढ़ाने का काम करेगा। सदन में एक चिंता व्यक्त हुई है कि रेवैन्यू डेफीसिट बहुत बढ़ा है। मैं भी यह मानता हूं कि रेवैन्यू डेफीसिट निश्चित तौर से बढ़ा है। एफ.आर.बी.एम. एक्ट की उल्लंघना के बारे में भी आदरणीय सी.एल.पी. लीडर ने कहा कि जो डेफीसिट के टारगैट्स थे उनको अचीव नहीं किया गया। यह बात मैंने अपनी बजट स्पीच में जानबूझकर कही कि हम डैफीसिट के टारगैट्स को अचीव नहीं कर पाये है मैं यह भी कह सकता था कि यह पिछली सरकार के कार्यकाल का विषय है और पिछली सरकार के क्रियान्वयन का विषय है। यह एफ.आर.बी.एम. एक्ट की उल्लंघना भी पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई है। उसके कुछ कारण हैं। इस साल का जो रेवैन्यू डफीसिट बढ़ा है उसके बढ़ने के भी अपने कारण हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेवैन्यू डेफीसिट में सुधार करना एक साल के अंदर सम्भव नहीं होता। उस दिशा में प्रयास करना प्रारम्भ करना है। जो विरासत में हमें समस्यायें मिली हैं उनको एक दिन में नहीं सुधारा जा सकता। हम इनको सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने इस बार भी रेवैन्यू डैफीसिट के टारगैट्स फिक्स किये हैं। हमारी आदरणीय सी.एल.पी. लीडर साहिबा ने कहा था कि हमने इस बार पिछली बार से ज्यादा रेवैन्यू डैफीसिट के टारगैट्स फिक्स कर लिये

[कैप्टन अभिमन्यु]

हैं। मैं यह मानता हूं कि आंकड़ों से हिसाब से यह ज्यादा है लेकिन वह परसैंटेज़ के हिसाब से जो केन्द्र सरकार की तरफ से हमें दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं कि जी.एस.डी.पी. के कुल सवा तीन प्रतिशत से ज्यादा वह नहीं हो सकता है जो इस बार 3.46 प्रतिशत गया है हमने इस बार का उसका लक्ष्य 3.14 प्रतिशत रखा है। इस सदन की भावना को भी मैं आत्मसात करता हूं और यह इससे ज्यादा न हो पाये इसके लिए हमारी सरकार पुरज़ोर कोशिश करेगी कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने डैफीसिट को कंट्रोल करने का काम करे। कुछ माननीय साथियों द्वारा कर्ज़ बढ़ाने के ऊपर भी एतराज़ किया गया है। यह ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर हम यह कर्ज़ नहीं लेते तो फिर हम प्रदेश के विकास के लिए खर्च नहीं कर सकते परन्तु हमने इतना भी तय किया है कि जो यह अतिरिक्त कर्ज़ लिया जायेगा यह अतिरिक्त कर्ज़ नॉन-प्लान एक्सपैंडीचर में नहीं जायेगा बल्कि यह कर्ज़ प्लॉन्ड एक्सपैंडीचर में जायेगा और कैपिटल एक्सपैंडीचर में जायेगा और इसके साथ ही अतिरिक्त कर्ज़ लेने के बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई जो हमारी मर्यादा है अर्थात हमारी जो डैट बोरोईंग की हमारी लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही इसको रखने का हमारा प्रस्ताव है। इस लिमिट से बाहर नहीं जाने की इस सदन में अपने पूरे प्रयासों की मैं अपनी सरकार की तरफ से कमिटमैंट देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेसी साथी यह बात ठीक कह रहे हैं कि इनके समय में यह बात नहीं थी। इसमें हमने यह चिंता व्यक्त की थी कि जो यह कर्ज़ था वह प्लैंड एक्सपैंडीचर में जा रहा था या फिर नॉन-प्लैंड एक्सपैंडीचर में जा रहा था। यह एक बेसिक स्ट्रक्चरल कमी थी जिसे हमने महसूस किया और हमने अपने राज्य के हित में इस कमी को दुरूस्त करने की तरफ पहला कदम उठाया है। इस कमी को हम एक-दो साल में या आज ही दुरूस्त कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता है। इस समय यह आवश्यकता है कि राज्य के हित को सर्वोपरि रखते हुए हम इस दिशा में काम करें जो यह पहला कदम इस बजट में उठाने की हमने पहल की है और आप सभी से समर्थन की अपेक्षा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, रैवेन्यू डैफीसिट के बारे में मुझे यहां पर इसके कारण बताने के लिए कहा गया है। यहां पर राशि का भी उल्लेख किया गया और नेता प्रतिपक्ष ने भी आंकड़ों का उल्लेख करते हुए हमें कहा था कि हमें इसके कारण बताने चाहिएं। मैं भी यह मानता हूं कि सदन के पटल पर हर चीज़ की समीक्षा आनी ही चाहिए। इस साल का हमारा विशेष रूप से 9500 करोड़ रूपये का हमारा रैवेन्यू डैफीसिट हुआ है। ये तीन मद हैं जिनके अंदर सरकार ने वर्ष 2014-15 का बजट प्रोजैक्ट किया था कि उनसे इतना रैवेन्यू आयेगा उसमें रैवेन्यू घटा है। ये तीन मद हैं स्टैम्प ड्यूटी, एक्साईज़ ड्यूटी और माईन्स। अक्तूबर, 2014 में जिस दिन इस वर्तमान सरकार ने काम सम्भाला उस समय बजट के अनुमान का जो कुल रैवेन्यू आना चाहिए था वह हमको 46 प्रतिशत तक ही उस वक्त तक आया था और जो उस वक्त तक का खर्च था वह उस अनुपात में उससे ज्यादा हो चुका था। वह चुनाव का वर्ष था इसलिए चुनाव का वर्ष होने के कारण इस प्रकार की परिस्थितियां तत्कालीन सरकार के सामने बनी होंगी। यह सब किन कारणों और किन बातों के कारण हुआ उन सभी कारणों और उन बातों को आप भी समझ सकते हैं, उन बातों का उल्लेख करके मैं यहाँ वातावरण में कोई उन्नमाद पैदा नहीं करना चाहता हूँ लेकिन उस 86 प्रतिशत को आज हम 83 प्रतिशत लेकर इस राज्य को किसी प्रकार से चलाने में कामयाब हुये हैं। वर्ष 2013-14 के कुछ खर्चे 2014-15 के लिए डैफर किये गये थे। साढ़े 4 हजार करोड़ रूपये की ऐसी राशि है जिसमें कुछ आमदनी आनी थी वह आई नहीं और जो 2013-14 के खर्चे थे

जिस प्रकार पॉवर की सब्सिडी का था, वे 2014-15 के लिए डैफर कर दिये थे। वर्ष 2014-15 में पेमेंट करने के लिए छोड़ दिये गये थे । कुछ आमदनियाँ पहले भी फिक्स हो गई थी परन्तु अभी उसकी डिटेल में जाने का समय नहीं है। उन चीजों को दुरूस्त करके हमें आगे बढ़ना है। हमारी अर्थव्यवस्था में ताकत है, उसको एब्जार्ब करके, अपने आपको सुधार कर वह आगे बढ़ सकती है। आप सबके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे । अध्यक्ष महोदय, 2025 करोड़ रूपये की नई स्कीमें हैं जिनका प्रावधान 2014-15 के बजट में भी नहीं था। चुनाव को ध्यान में रखते हुये बिना ही बजट में प्रावधान किये वे घोषणाएं कर दी गई । आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि यह पिछला साल किस प्रकार के वातावरण में गुजरा है ? अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि मैं आंकड़ों की डिटेल देना चाहूँगा। इस साल हमारी 247 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लायबिलिटीज बढ़ी हैं, डैफर्ड एक्सपैंडीचर 1778 करोड़ रूपये का और जो एक्सैस प्रोजैक्शन ऑफ रिवैन्यू था 2210 करोड़ रूपये का था जो कि रिलायजेबल भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कांग्रेस विधायक दल की नेता ने जिक्र किया था तब मैंने उनको बीच में टोक कर कहा था कि आंकड़े शायद ठीक नहीं हैं, तब उन्होंने भी बड़ी विनम्रता से कहा था कि ठीक नहीं हैं तो दुरूस्त कर लीजिएगा। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने भी स्टैम्प ड्यूटी के आंकड़ों को उद्धृत किया था। बजट ऐस्टीमेट्स के 3950 करोड़ रूपये थे लेकिन जब बाद में रिवाईज्ड ऐस्टीमेट्स आया तो हमने उसको 3300 करोड़ रूपये कर दिया था, उसकी तुलना में आज अगले वर्ष के लिए 3600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इन आंकड़ों को दुरूस्त करना मेरी जिम्मेदारी थी। इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब अक्तूबर में हमने जिम्मेदारी सम्भाली उस समय हमारे पास 3950 करोड़ रूपये का बजट ऐस्टीमेट था और इस 3950 करोड़ रूपये की स्थिति यह थी कि हम महज 1600 करोड़ रूपये के आसपास खड़े थे। बमुश्किल 5 महीनों में प्रयास करके हम इसको 3300 करोड़ रूपये लेकर आये हैं। कुल मिला कर जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें एक ऐसा वातावरण बन गया था तथा उनमें गैर-जिम्मेदाराना भाव आ गया था। मैंने श्वेत-पत्र के माध्यम से इस बात का उल्लेख पहले भी किया था, एक चिन्ता व्यक्त की गई थी कि आपने टैक्स का जो साढ़े 5 हजार करोड़ रूपये का रिवैन्यू बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है उसको कैसे पूरा करोगे, यह कैसे बढ़ेगा? अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए एक चुनौती है, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और हमने उसको मार्ग दिखाया है कि यह कम्प्यूटराईजेशन से बढ़ेगा। यह आई.टी. के प्रयोग से बढ़ेगा, यह भ्रष्टाचार को रोकने से बढ़ेगा, यह नीचे तक की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने से बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है मैं फिर से दोहराने की हद तक जाना चाहूँगा कि अगर 10 वर्ष पहले वर्ष 2004-05 की टैक्स रेशो को मेनटेन किया जाता तो 20 हजार करोड़ रूपये हमारी सरकार के खजाने में आना चाहिए था। इसी प्रकार से अगर 2005-06 और 2006-07 की दर को लेकर चला जाये तो लगभग 26-27 हजार करोड़ रूपये आना चाहिए था। इस राज्य की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के निर्णय हुये, मैं कांग्रेस विधायक दल की नेता से कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक शेयर सुनाया था वह मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि

सुना था उड़ेंगे गालिब के पुर्जे,
देखने हम भी गये, मगर तमाशा न हुआ।

कौन-से पुर्जे उड़ते देखना चाहते थे, किसके पुर्जे उड़ते देखना चाहते थे, हमसे कौनसी बातें सुनना चाहते थे ? अगर माननीय कांग्रेस विधायक दल की नेता को वे पुर्जे देखने हैं तो एक बार श्वेत पत्र

को दोबारा से देख लीजिएगा, वे पुर्जे कुछ इधर पड़े हैं कुछ उधर पड़े हैं। साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रूपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सरकार के खजाने में आने चाहिएं थे, वह सरकार का हक था, वह किसी प्राईवेट बिल्डर या रियल इस्टेट डिवैल्पर का अधिकार नहीं था उसको अपने खजाने में रखने का। ऐसे कौन-से कारण थे जिसके कारण वह पैसा सरकार के खजाने में हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में प्लांड और कैपिटल ऐक्सपैंडीचर में उसको इन्वैस्टमैंट नहीं किया जा सकता था, क्या कारण थे ? अध्यक्ष महोदय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साढ़े 3 हजार करोड़ रूपये का इन्कम टैक्स चुका दिया गया केवल मात्र इस कारण से कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसिज के अन्दर कुछ परिवर्तन करने थे वह परिवर्तन करने का साहस सरकार ने नहीं किया। उस पारदर्शिता का साहस सरकार ने नहीं किया और सरकार ने उसको जाकर कहा कंटस्ट किया ? आदरणीय अध्यक्ष जी, कितने ही ऐसे अवसर हैं मैं इसको केवल आलोचना के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था के अन्दर राजस्व जुटाने के पर्याप्त अवसर मोजूद हैं। इस अर्थव्यवस्था के अन्दर ताकत थी लेकिन उस ताकत को हमने राज्य के खजाने में लाकर परिवर्तन करने की बजाए सब जानते हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था काम करती थी। आज उन भूल दोषों को दूर करने की चुनौती हमारे सामने है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने सैक्टोरल एलोकेशन जो हमने की है वह आपके माध्यम से मैं केवल सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमने जो प्रायोरिटी सैक्टर आईडैंटीफाई किए हैं यह हम जानते हैं कि उनके अलावा ऐसे बहुत सारे एरियाज और भी थे जिनको भी और पैसे की आवश्यकता थी। उन मदों में देने की आवश्यकता है लेकिन हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार और आज की आवश्यकता के अनुरूप जितना जहां-जहां दे सकते हैं हमने उनको आईडैंटीफाई किया है। आवश्यकता है आज शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की इसलिए हमने इस क्षेत्र में 13.23 प्रतिशत बजट बढ़ाया है। हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता हुई तो उसमें हमने 14.45 प्रतिशत बजट बढ़ाया है। सोशल वैलफेयर के क्षेत्र में 16.67 प्रतिशत बजट बढ़ाया। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज में 25.6 प्रतिशत बढ़ाया। एग्रीकल्चर एलाईड सैक्टर में 20.49 प्रतिशत बजट बढ़ाया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस महान सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि कृषि और किसान से संबंधित बहुत चर्चाएं हुई हमारे साथियों ने चिन्ता व्यक्त की कि रिकॉर्ड के ऊपर एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने सीनियर व मेरे काबिल साथियों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में कृषि के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया था उसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि हमने वर्ष 2015-16 के बजट में की है। ये कुछ कारण थे जो हमने खोजे हैं कि कृषि का क्षेत्र क्यों पिछड़ा ? क्यों किसान बदहाल हुआ ? आज उसमें करैक्शन करने की आवश्यकता है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इसमें जहां तक ये कह रहे हैं कि हमने इतने प्रतिशत इन्क्रीज किया। एग्रीकल्चर एंड अलाईड के लिए 1106 करोड़ रूपये पिछली बार थे। अबकी बार 1369 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। मीनिंग देयर बाई 23 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ न कि 60 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ है।

कैप्टन अभिमन्यू : डॉक्टर साहब ने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने बताया कि हमने हैल्थ विभाग में 14 प्रतिशत बजट बढ़ाया है। इसके बारे में स्पष्ट करें।

कैप्टन अभिमन्यू : सर, मैंने पूरा स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र का विषय रखा है। इसमें सारे कंपोनैन्ट्स आ गये। मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैं बजट पर स्पीच नहीं दोहरा रहा हूं। मैं क्षेत्रों में अपनी एलोकेशन बता रहा हूं जिन क्षेत्रों को हमने प्राथमिकता दी है मैं आपको उनकी एक ब्रॉड इंडिकेटिव फिगर दे रहा हूं। आंकड़ों में उलझाना मेरा उद्देश्य नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी, से वही बात पूछना चाह रहा हूं कि बजट के अन्दर दर्शाया गया है कि वर्ष 2014-15 में 3.83 करोड़ रूपये बजट हैल्थ के लिए था अबकि बार 3.82 करोड़ रूपये है यह बजट बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। आप कहते हो कि हमने पिछले साल के मुकाबले 14 प्रतिशत बढ़ाया है।

कैप्टन अभिमन्यू : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आपने अपने ब्यान में जो जी.एस.टी. की उस कुल एलोकेशन की प्रसन्टेज को इंगित किया था कि मैंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है वह आंकड़ा पिछले वर्ष से उसकी वृद्धि दर का है। जो मैंने आपके समक्ष रखा है इसलिए आप दूसरे आंकड़े की बात कर रहे हैं और मैं दूसरे आंकड़े की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से रूरल डवैल्पमैंट में इन्फ्रासट्रैक्चर डवैल्पमैंट के लिए 22.03 प्रतिशत और अर्बन डवैल्पमैंट में 34.03 प्रतिशत की वृद्धि करके हमने इन सात सैक्टर्ज को प्राथमिकता दी है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो नया टैक्स लगाया है और नया सेस लगाया है। उसके बारे में बतायें।

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस बात की अनुमति दें तो करण सिंह दलाल जी को बजट के बारे में अच्छी तरह से बता भी दूँगा और पढ़ा भी दूँगा। माननीय सदस्य को अर्थ-शास्त्र पढ़ने और समझने की जरूरत है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें लिखा हुआ है कि There will be 5 % cess on the VAT.

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की ना समझ के कारण सदन में गलत बात स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मंत्री जी क्लेरिफाई करें।

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, हमने कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया है। मैंने इस बारे में क्लेरिफाई कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, प्लीज बैठ जाईये। माननीय वित मंत्री जी ने आपको क्लेरिफाई कर दिया है।(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर गलत ब्यान नहीं कर सकता हूँ। माननीय सदस्य जिस संदर्भ को पढ़ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण दलाल जी, प्लीज बैठ जाईये। आप जिस प्वॉयंट को पढ़ रहे हो उसी प्वॉयंट के बारे में बात करें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पूरी स्पीच देने लग जाएं। मंत्री जी बजट की रिप्लाई दे रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान) प्लीज बैठ जाईये।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने न तो कोई टैक्स लगाया है और न ही कोई सेस लगाया है। ये जिस लाईन को पढ़ रहें हैं वह लाईन केवल मात्र एक्सप्लेन कर रही है कि अर्बन लोकल बॉडीज का एलोकेशन वैट, सेस और शेयर में से आयेगा । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कोई नई बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ऐलान कर दें कि वैट के ऊपर सेस नहीं लगायेंगे। हम मान लेते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, यदि इनको समझ में आ जाये तो समझा देंगा। मुझे लगता है कि इनको समझाना बड़ा ही मुश्किल है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बजट के प्रस्ताव में कोई नया वैट नहीं है और न ही कोई नया सेस है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य को पता चल गया है या नहीं ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में बहुत अच्छी चर्चाएँ हुईं और बहुत से व्यंग्य विनोद भी हुए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमें कहा गया कि अनुभवहीन सरकार है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा था कि हम सरकार के कामकाज में नये हैं। हम सीखना चाहते हैं और सीखेंगे भी। अध्यक्ष महोदय, मैं करण सिंह दलाल जी को कहना चाहता हूँ कि आप से भी सीखेंगे। हम यह भी सीखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक जो तोल कर पाया हूँ। ना सीखने वाली मात्रा ज्यादा है और सीखने वाली मात्रा कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से उम्मीद करूँगा कि सरकार को आप भी अपने अनुभव का लाभ देंगे। (शोर एवं व्यवधान) हमें कहा गया था कि अनुभव की कमी है, हाँ हमें और चीजों का अनुभव हो सकता है। जिस अनुभव को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर आयें हैं। अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि जमीनों का अनुभव कम है (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार पिछले10 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश में एक ही काम में लगी रही इस प्रकार का अनुभव हम नहीं सीखना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी तो बजट पर न बोलते हुए पोलिटिकल स्पीच दे रहें हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इस अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रकार का अनुभव न करें। सरकार और सरकार में बनने वाला बजट किसी क्षेत्र, किसी वर्ग या कुछ लोगों के लिए नहीं है। हमारा बजट पूरे हरियाणा प्रदेश के 21 जिलों का, 90 विधान सभा क्षेत्रों का और 6500 से अधिक गाँवों का है। यह सबका समान रूप से विकास करने वाला बजट है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : जी हाँ ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हाउस की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण)

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले संकेत किए थे कि अनुभव से बड़ा अभिप्राय होता है ये उनके सूत्र वाक्य हैं। हमारा अभिप्राय शुद्ध है और हम अपने अनुभव की कमी को अपने शुद्ध अभिप्राय से पूरा करते हुए हरियाणा प्रदेश की सेवा का संकल्प लेकर आये हैं। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अन्दर हुडा विभाग ने कितने सैक्टरों को डिवैल्प किया हैं और कितने सैक्टर उसकी तुलना में प्राईवेट कॉलोनाईजरों के हाथों में गये हैं ? अध्यक्ष महोदय, उनके क्या परिणाम हुये, मैं इनकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ।

श्री अभय चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य ने माननीय वित्त मंत्री के साथ बैठकर बजट पर सभी बातों की चर्चा करते हुए पूछा था कि पिछले 10 वर्षों में हुडा विभाग ने गुड़गांव के अन्दर कितने नये सैक्टरों को डिवैल्प किया है और 10 वर्षों से पहले कितने डेवैल्प हुये और पहले वालों में प्राईवेट सैक्टर किन-किन के पास थे। इस बार कितने नये डेवैल्प हुए, हुडा विभाग ने नये सैक्टरों में कितने सैक्टर बनाये जिससे आम लोगों को लाभ मिला। जो नये सैक्टर बने हैं वे किन लोगों ने बनाये हैं। यदि इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी सदन को बतायेंगे तो सदन को भी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से हुडा विभाग के सैक्टरों से आम लोगों को लाभ मिलता है। हुडा विभाग इसलिए बनाया गया है कि आम लोगों को लाभ मिले, सस्ते रेट पर प्लॉट मिलें जिन्हें खरीद करके आम आदमी अपना घर बना सके और अपना बसेरा कर सके । अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि हुडा के सैक्टर काटने की बजाय प्राईवेट सैक्टर कितने काटे गये हैं, माननीय मंत्री जी को सदन को विस्तार से बताना चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बजट से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्य ने यह विषय मेरे सामने रखा था, फिर इस बारे में कभी चर्चा होगी, उम्मीद है कि जब चर्चा होगी तो बात बहुत आगे तक जायेगी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने हुड्डा (HOODA) की बजाय हुड्डा (HOODA) के सैक्टर काट दिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को हुड्डा (HOODA) का मतलब समझाना चाहता हूँ, हुड्डा (HUDA) का मतलब होता है 'हरियाणा और ऑवरआल डिवैल्पमैंट अथॉरिटी' (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि पिछले 10 वर्षों से हुड्डा (HOODA) को हुडा (HUDA) से ज्यादा बड़ा मानते रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए इतनी महत्वपूर्ण संस्था हुडा के 15 हजार करोड़ रुपये की हरियाणा का खजाना इंतजार कर रहा क्योंकि वह हुडा (HUDA) की तरफ बढ़ा दिये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने खजाना बनाया है। भाजपा सरकार दो दिन आगे-पीछे रिकवरी करवा लें। आपकी पार्टी के लिये खजाना छोड़ दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यू : हुड्डा जी, आप यह भी सदन को बतायें कि किसकी जेब में छोड़ दिया और क्यों खजाना छोड़ दिया? यदि आपको यही बातचीत करनी है तो आप सदन को यह भी बतायें कि किन कारणों से खजाने को छोड़ दिया है ? कौन सी नीतियों और कौन से कानून के आधार पर आपने खजाना छोड़ दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, खजाना किन कारणों से छोड़ा गया है, उसकी इन्क्वायरी होगी या नहीं यह भी सदन में विस्तार से बताया जाना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष नेता की चिन्ता, सरकार और सदन दोनों अच्छी तरह से समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि दांगी साहब ने कल भी और आज सुबह भी मुझसे कहा कि जांच पूरी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, सदन उनकी भावनाओं का सम्मान करता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले भी कहा था कि सरकार जो जांच करवाना चाहती है तो करवाये क्योंकि मेरे कार्यकाल में कोई भी गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जांच करवाने की हिम्मत होनी चाहिए। सरकार को बने हुए चार महीने के करीब हो गये हैं, अब तक तो जांच हो जानी चाहिए थी। किसने रोका है? मैं जांच करवाने के लिये तैयार हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जांच करवाने के लिये हिम्मत की कमी नहीं है। कानून अपना काम करेगा, हुड्डा साहब जांच के लिये कहे या ना कहे लेकिन सरकार अपना काम करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहता हूँ कि लोगों को गुमराह करना छोड़ दो और जांच करो ।

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष महोदय, विधायक दल की नेता मैडम किरण चौधरी ने प्लूटो से उद्धृत करते हुए कहा था कि 'reality is a poor copy of ideology' आपने बिल्कुल ठीक कहा था लेकिन आप थोड़ा अतीत में चली गई जिससे मुझे लगा कि आप को मुझसे पूछने की बजाय अपने पड़ोसी सदस्य से पूछने की ज्यादा इच्छा थी । (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Minister that the reality is of what is today. He should talk about the reality and not about the idolism.

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष जी, शायद मेरी समझ की कमी रह गई होगी। मुझे कम्युनिकेशन गैप के कारण लगा कि वे पूछ रही होंगी कि हरियाणा नंबर वन कैसे था और श्वेत-पत्र क्या बता रहा है। मुझे लगा कि माननीय सदस्या मेरे माध्यम से संवाद कर रही हैं। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : आप मुझ से पूछ लीजिए कि मैं किस संदर्भ में पूछ रही हूं। मैं बता देती हूं । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि प्लूटो ने

'द रिपब्लिक' में एक महान कल्पना दी थी कि एक राज्य की राज काज व्यवस्था में ऐसा आदर्श होना चाहिए जो समाज से योग्य व्यक्तियों को चुनकर उनको निजी स्वार्थों और व्यक्तिगत हितों से पूरी तरह अलग करते हुए विद्वान लोगों को तैयार करके फिलॉस्फर किंग्स बनाएं। आज मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री इसी फिलॉस्फर किंग की तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। इनका अपना कोई निजी स्वार्थ या व्यक्तिगत हित नहीं हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) मुझे सदन के साथ यह बात सांझा करते हुए खुशी हो रही है। इस में आदरणीय प्लूटो के जिक्र से ज्यादा मेरा तात्पर्य नहीं था। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : ...(विघ्न)

Smt. Kiran Choudhry : Plato must be turning in his grave.

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष जी, आदरणीय सी.एल.पी. लीडर ने कहा था कि it is rudderless ship and waiting for an anchor. समुद्र में एक जहाज है जो डोल रहा है और वह लंगर डालने के इंतजार में है। अध्यक्ष जी, यह हमारी मानसिकता नहीं है। ठीक है, जहाज समुद्र में है, समुद्र में तूफान है और तूफानी चक्रवात भी है लेकिन हमारी सरकार एंकर की वेट नही कर रही है बल्कि हमारे काबिल कप्तान मुख्यमंत्री जी के हाथ में हैं और यह तूफानों से पार पाकर आगे बढ़ेगी और साहिल तक पहुंचेगी। मैडम किरण चौधरी, यह आपका वाक्य था और इसे क्लीयर करना मेरा फर्ज है। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, I have said 'a rudderless ship floating among the figures'. I talked about the figures. I know what I have said.

Capt. Abhimanyu : Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Member that we do not need an anchor. We have the capacity to ride the rough troughs of the tides and we will move on the course. We will stay on the course and we will reach the destination. हम मंजिल को प्राप्त करेंगे और हरियाणा राज्य को मंजिल पर लेकर जाएंगे। (इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई।) आदरणीय सी.एल.पी. लीडर साहिबा ने एक अच्छे विषय पर चिंता जाहिर की थी। उनकी टोटल सैटिसफैक्शन की जाएगी। इनका प्रश्न था कि आप 800 मेगावॉट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट पानीपत में लगाने जा रहे हैं और इसके लिए करीब 4000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना है। आपने पूछा है कि आप इस बजट में यह पॉवर प्लांट कैसे लगाओगे। मैं कोई रॉकेट साईंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक साधारण सी बात कर रहा हूं जिसे आप अच्छी तरह से समझती हैं। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पॉवर प्लांट के बारे में नहीं कहा है। मैंने कहा है कि आपने जो प्रावधान किये हैं वे कैसे पूरे कर पाओगे ? (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यू : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या का प्रश्न मेरे सामने है । इसकी स्क्रिप्ट में इन्होंने कहा है कि ये 4 हजार करोड़ रूपये के प्लांट आप कैसे लगा पाओगे ? (विघ्न)

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, I did not say about the plants at all. In fact I have commended the Finance Minister on that. I only said it because the amount of money that is put in is so less for bringing forward the development works which you are talking about.

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने यह प्रश्न किया और हमें बधाई भी दी और यह भी कहा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा प्राप्त करोगे तो हम आपको लॉड (laud) भी करेंगे और बधाई भी देंगे। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणी सी.एल.पी. लीडर साहिबा को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार दिन-रात काम करेगी, पुरूषार्थ की पराकाष्ठा करेगी और एक दिन इनसे शाबाशी लेकर रहेगी। (इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई।)

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, there is nothing wrong in what I am saying. I only want to say that when the Union Budget was presented in the Parliament, wife of the Finance Minister, Government of India had come to watch because her husband was making a maiden speech in the House. When she came out, the press asked for her reactions. She said that the speech was boring. Incidentally, somebody is here also and press obviously missed that opportunity of asking the Hon'ble Finance Minister's wife as to what her reactions are because she runs domestic business. But one thing which somebody who sat in the back heard that son of the Finance Minister was asking his mother that there is real independence in this country now as father has been speaking in your presence for one hour. (Interruption).

Captain Abhimanyu : Thank you very much, Sir. I really appreciate this. यह बात ठीक है कि यह बड़ा दु :साहस का काम ही रहा है। लेकिन अर्थ-प्रबन्धन के मामले में उनका भी मेरे साथ 20-21 वर्ष का अनुभव है। इसके लिए वे इस बात को साबित कर देंगी कि कैप्टन साहब ने अभी तक ठीक ठाक गुजारा चलाया है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी की आदरणीय सी.एल.पी. लीडर साहिबा ने कहा है वैसे तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं अपनी समझ के अनुसार उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पानीपत में जो 800 मैगावाट का सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सामान्यत: प्रति मैगावाट के लिए 5 और 6 करोड़ रूपये के बीच में खर्चा आता है। उसमें पॉवर कम्पनी को जो इक्विटी का कम्पोनैंट देना होता है वह 30 प्रतिशत होता है उसको देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वह सरकार जरूर देगी। इस साल के बजट में उसके लिए 700 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। आने वाले समय में इस 30 प्रतिशत इक्विटी कम्पोनैंट की पूर्ति करके इसी प्रकार के दूसरे प्रोजैक्ट भी इसी तरह की डैट इक्विटी स्ट्रैक्चर है उसकी कम्पोजीशन के हिसाब से लगाये जायेंगे। (विघ्न) एक सदन की सामूहिक चिन्ता थी वह यह थी क्योंकि आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण में इस प्रकार से ऐसा लगता था कि अनुसूचित जाति के लिए बजट का जो प्रावधान किया गया है वह कम किया गया है। वह आंकड़ा अपने आप में उस विभाग की दृष्टि से कम लगता है। मेरे से वरिष्ठ माननीय सदस्य मुझ से सभी सीनियर हैं वे मंत्री भी रहे हैं इसलिए वे इस बारे में सभी जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन की योजना के अनुसार राज्य सरकार को विभिन्न विभागों के माध्यम से किये जाने वाले विकास या अन्य खर्च की अनुपात जनसंख्या के अनुपात में उस पैसे को खर्च करना अनिवार्यता है। वह पैसा सभी विभागों के खर्च में से जो शिड्यूल्ड कॉस्ट सब-प्लॉन का हिस्सा है वह कुल मिलाकर जो पिछले वर्ष 4215 करोड़ रूपये था उस को बढ़ाकर इस साल के बजट में 4729 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस की बैठक का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस की बैठक का समय दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एफ.आर.बी.एम. एक्ट के बारे में मैं दोबारा से नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने सदन को विश्वास दे दिया है कि हरियाणा सरकार जो केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एफ.आर.बी.एम. के जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारे फिसकल रेवेन्यू और बजटरी लिमिट्स के जो हमारे टारगेट्स हैं उनके अन्दर रहने के लिए हम कमिटिड हैं और हम रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के बारे में इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट भाषण के दौरान एक विषय और आया था कि आप जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, आप इन लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करेंगे। जिसमें रेवेन्यू डैफीसिट भी आ गया है और सारी ग्रौथ के लिए फण्डिंग भी आ गई। मैंने पहले भी आंकड़ों के साथ इस विषय के बारे में बताया है। मैं इसके बारे में सदन को एक आंकड़े की तुलना दे रहा हूं। प्लॉन एक्सपैंडीचर और नॉन-प्लॉन एक्सपैंडीचर का जो कम्पोजीशन है उसमें परिवर्तन करने की दिशा में हमने काम शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में नान-प्लान खर्च 71.26 प्रतिशत् तथा प्लान खर्च 28.74 प्रतिशत् था। इस वर्ष प्लान खर्च को बढ़ाकर हम ने 32.5 प्रतिशत् कर दिया है तथा नान-प्लान खर्च को 67.49 प्रतिशत् कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है इस दिशा में हम आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं। (विघ्न) नान-प्लान खर्च को घटाने का एक ही तरीका है जिसको मैं आदरणीय कादियान साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब ओवरऑल बजट बढ़ता है तो उसमें नान-प्लान की बजाए प्लान का कोंपोनेंट बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि नान-प्लान की रेश्यो अपने आप कम आ जाएगी। यह एक साधारण सी बात है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, महंगाई को आप कैसे रोकेंगे ? इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने काबिल दोस्त को कहा था कि आप उन्हें समय दे दीजिए, इनको अर्थव्यवस्था के कुछ छोटे-छोटे सिद्धांत भी बता देंगे और कुछ बजट संबंधी बातें भी बता देंगे। इनको इस बात की जानकारी नहीं है। चूंकि यह विषय बजट से संबंधित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शून्य प्रतिशत् के करीब इन्फ्लेशन अपने आप में एक चुनौती होती है जिसको लेकर सरकारों को चिंतित होना पड़ता है। यह अर्थशास्त्रियों के लिए अपने आप में एक सवाल है। उस पर तो मैं गहराई में अब नहीं जाना चाहता हूं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने अपने हल्के से संबंधित बहुत सारे विषय रखे। प्रतिपक्ष के आदरणीय नेता ने भी अपने विषय रखे। सी.एल.पी. लीडर साहिबा ने भी व्यक्तिगत रूप से मेरी चिंता की थी। उन्होंने राखीगढ़ी के

[कैप्टन अभिमन्यु]
म्युजियम के बारे में कहा था। इस बारे में बताना चाहूंगा कि वास्तव में यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पुरानी विरासत है तथा इस विरासत से संबंधित प्वांयट को मैं बड़ी जिम्मेवारी से नोट करता हूं । यह प्वांयट मैं इसलिए नोट नहीं करता हूं कि वह स्थान मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है बल्कि इसलिए नोट करता हूं कि वह हरियाणा राज्य की व इस हिन्दुस्तान की विरासत ही नहीं है बल्कि वहां पर मानव सभ्यता के इतिहास से संबंधित सबसे पुरातन व सनातन सभ्यता के अवशेष उपलब्ध हैं । आपके कन्सर्न को मैंने नोट किया हुआ है तथा इस दिशा में हम भविष्य में अवश्य कार्य करेंगे ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, केवल म्युजियम की ही बात नहीं है। वहां पर एक्साकावेशन की वजह से पूरा कार्य बंद पड़ा है। That entire area should be beautified. You should make efforts so that it can become tourist hub and you will get lot of revenue from it.

Captain Abhimanyu : Madam, I have noted your every word that you spoke in all my earnest. I give my commitment to you.

(विघ्न) मुझे बहुत खुशी हुई है कि आदरणीय हुड्डा साहब ने भी इस विषय में अपनी चिंता व्यक्त की है। मुझे बताया गया था कि इस कार्य के लिए 10 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार से आये थे। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है लेकिन इन 10 करोड़ रूपये के बारे में अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। इस बारे में बीच बीच में बात आती रही कि शायद यह पैसा वापिस चला गया या इधर उधर हो गया। लेकिन पता नहीं चला कि यह पैसा कहां चला गया ? आज मुझे बड़ी खुशी है कि सदन का वातावरण बड़ा प्रेरणादायी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। प्रतिपक्ष के आदरणीय नेता ने भूतपूर्व सैनिकों की चिंता व्यक्त की है। वैसे तो इस विषय में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई होगी तो इनसे प्रेरणा प्राप्त करके भूतपूर्व सैनिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा तथा जो भी प्रावधान सप्लीमैंटरी डिमांड आदि के माध्यम से आने वाले समय में हम करने वाले हैं, उनमें निश्चित तौर पर भूतपूर्व सैनिकों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। बहुत सारे विधायकों की अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित स्वाभाविक तौर पर अपेक्षाएं हैं। (विघ्न) इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के लिए बहुत कुछ करें, सभी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को कामयाब करें तथा ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। (विघ्न) आदरणीय ढुल साहब ने अभी जो विषय उठाया है, उस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि फिर उसके अंदर इतिहास की बातें आ जायेंगी। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अब तो हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में हरियाणा प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास होगा तथा निश्चित तौर पर जींद उससे अछूता नहीं रहेगा।

प्रो.रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, बिजली के debt management के बारे में सरकार द्वारा क्या किया गया है वह भी बता दें ?

Smt. Kiran Choudhry : Finance Minister ji, you have mentioned in your budget speech about it. I am concerned for the future generation. I would like to know what you are doing on NCZ (Non construction Zone) about 500 meters, which was notified for NCZ ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, प्रो. साहब ने जो विषय उठाया है उसके संदर्भ में मैं उनको बताना चाहूंगा कि बिजली विभाग अपने आप में स्वतंत्र इकाइयां हैं और ये सरकार से स्पोर्ट होती हैं, उनकी डैट मैनेजमैंट चिंता का विषय है। सरकार निश्चित तौर से उस चिंता का समाधान करने की दिशा में काम कर रही है और कुछ जिम्मेवारीपूर्ण काम करने की हमें आवश्यकता है। मुख्यमंत्री महोदय जी ने सदन के माध्यम से और आप सबसे आह्वान भी किया है कि हम सब मिलकर और राजनीति से ऊपर उठकर इस दिशा में काम करेंगे तो इस समस्या से पार पाया जा सकता है। आदरणीय सी.एल.पी. लीडर साहिबा ने अपनी चर्चा के समय भी इस विषय को रखा था और इन्होंने कहा था कि इन्होंने मुझे पत्र लिखा था। वह पत्र मुझे कल मिला है और उस पत्र का उत्तर भी मैंने कल भेजा है। चूंकि यह विषय सीधे सीधे बजट से सम्बन्धित नहीं है। (विघ्न) जहां तक इन्वायर्नमैंट की बात है तो इसके स्पैसीफिक प्रपोजल्ज राज्य के हित में, पर्यावरण के हित में और आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए पर्यावरण को बचाना आज की इस वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेवारी को मानते हुए जो अच्छे से अच्छा काम होगा उसको हम करेंगे। पर्यावरण के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। मैं सभी विधायकों का जिन्होंने समय निकालकर इस बजट को पढ़ा और इस बजट के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी की, समालोचना भी की, इससे अपनी अपेक्षा और अपने सुझाव भी रखे मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि गालिब की चर्चा भी आदरणीय सी.एल.पी. लीडर साहिबा जी हाउस में कर रही थी इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गालिब ने लिखा है कि -

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि अपेक्षाएं बहुत हैं और हमें बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यदि एक एक लाइन का मैं उत्तर दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। पंजाब के समान वेतनमान देने की दिशा में हमारी सरकार ने एक आयोग की स्थापना की है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बहुत सी पुरानी बातें यहां कह दी गई, अगर फिर उन्हीं पुरानी बातों को छेड़ेंगे तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि 10 सालों तक ये क्या करते रहे और हमारे से 4 महीने का हिसाब लेना शुरू कर दिया इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उन चर्चाओं को न छेड़ा जाए जिसमें इनको खुद को आइना देखने में दिक्कत हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे जीवन में यह एक महत्वपूर्ण अवसर है और मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का सौभाग्य मानता हूं और मैं पूरे सदन की इस भावना की प्रशंसा करते हुए कि इस सदन के सदस्यों ने अर्थ प्रबंधन से सम्बन्धित बहुत जिम्मेवारीपूर्ण वक्तव्य दिया है कि हमको राज्य के नाते से कभी अपनी बोरोइंग (borrowing) को सीमाओं से बाहर नहीं ले जाना है और राज्य के नाते से कभी डैफिसिट को बढ़ने नहीं देना है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं पूरे सदन को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब यह सदन दिनांक 24 मार्च 2015, दोपहर 2.00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

[*15.53 बजे] (तत्पश्चात सदन की बैठक मंगलवार, 24 मार्च, 2015 दोपहर 2.00 बजे तक *स्थगित हुई)

53421-HVS-H.G.P.,Chd.

Sabha Secretariat * Haryana * Chandigarh
LIBRARY